

बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि-आधारित औद्योगिकरण

(अवस्थिति, निष्पादन, समस्याओं एवं सम्भावनाओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन)
(सातवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)



अर्थशास्त्र विषय के अन्तर्गत
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

निर्देशक :

डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी
रीडर एवं विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र
पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय
बाँदा (उ०प्र०)

शोधार्थिनी :

श्रीमती कंचन श्रीवास्तव
शोध केन्द्र :
पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय
बाँदा (उ०प्र०)

डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी

एम.ए. (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र)
पी.एच.डी., रीडर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
पं. जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय
बाँदा - २१०००९ (उ०प्र०)

दिनांक :

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कंचन श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध "बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि-आधारित औद्योगिकरण" मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्व विद्यालय के पत्रांक बु०वि०/ शोध/६५/१८१२-१४ दिनांक १८-५-६५ के द्वारा अर्थशास्त्र विषय में शोध कार्य के लिए पंजीकृत हुई। इन्होंने मेरे निर्देशन में आर्डीनेन्स की धारा ७ द्वारा वांछित अवधि तक कार्य किया तथा इस अवधि में शोध केन्द्र में उपस्थित रही। यह इनकी मौलिक कृति है। इन्होंने इस शोध के सभी चरणों को अत्यन्त संतोषजनक रूप से परिश्रम पूर्वक सम्पन्न किया है। मैं इस शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करने की संस्तुति करता हूँ।

दिनांक : २२.१२.२०००

(डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी)

शोध-निदेशक

रीडर एवं विभागाध्यक्ष

अर्थशास्त्र

अमुख-

प्राचीन काल से कृषि का महत्व भारत में रहा है। कृषि के द्वारा ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमारे देश में कृषि अर्थ व्यवस्था का आधार स्तम्भ है। देश के आर्थिक विकास में कृषि आधारित बड़े उद्योगों की अहम भूमिका रही है। देश की गिरती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्भालने में कृषि आधारित उद्योगों की अहम भूमिका रही है। देश में कृषि उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप ही देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि-आधारित उद्योगों के अर्न्तगत यहाँ दाल मिल, चावल मिल, आटा मिल, है। इस कृषि-आधारित उद्योगों के पीछे कौन से कारक विद्यमान है, इनका उत्पादन क्या है श्रम प्रबंध कैसा है, तथा इन उद्योगों को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इन्ही आर्थिक निहितार्थों के उद्घाटन हेतु शोध प्रयास अवदानित है।

प्रस्तुत **“बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि-आधारित-औद्योगिकरण”** शोध प्रबंध में जो निष्कर्ष सामने आये हैं, वे जहाँ कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति स्पष्ट करता है वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों की समस्याओं की सर्वेक्षणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। **“बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि-आधारित औद्योगिकरण”** शोध प्रबंध का विषय चुनने की प्रेरणा मुझे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञ एवं भारतीय अर्थशास्त्र के आधुनिक चिन्तनशील विद्वान डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी जो कि मेरे प्रबंध के निर्देशक भी है से प्राप्त हुई जिनका गहन निर्देशन ही शोध प्रबंध का राज है।

प्रत्येक अध्ययन एक सामूहिक प्रत्यन का प्रतिफल है। प्रस्तुत शोध प्रबंध के प्रणयन में जिन परोपकारी, सज्जन एवं विद्वान व्यक्तियों तथा संस्थाओं का सहयोग मुझे प्राप्त है। मैं उनके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगी।

सर्वप्रथम मैं अपने गुरु एवं निदेशक सर्वश्री डॉ० सतीश कुमार त्रिपाठी जी, जिनका विराट एवं महान व्यक्तित्व स्वतः ही मेरा निर्देशन करता रहा है के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ उनरकी स्नेहित छाया आगे भी मेरा मार्गदर्शन करती रहे, यही मेरी कामना है। इस क्रम में पं० जे० एन० कालेज, बाँदा के प्राचार्य इन्द्रजीत सिंह, अर्थशास्त्र विभाग के प्रवक्ता

डा० विजय सिंह चौहान जी की भी आभारी हूँ।

साथ ही मैं अपने पूज्यनीय माता पिता एवं पति श्री राकेश श्रीवास्तव के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया साथ में मैं अपने पूज्यनीय भाई साहब (श्रीवी०के० त्रिपाठी) जिनकी प्रेरणा एवं सहायता के बिना शायद शोध प्रबंध लिखना ही सम्भव न होता उनके प्रति आभार की अभिव्यक्ति कर पाना कम से कम मेरे सामर्थ्य से परे है।

इसके अतिरिक्त अपने भाई साहब (विवेक) भाभी के प्रति भी आभारी हूँ। इन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। साथ में जिला उद्योग के कर्मचारियों एवं विशेष रूप से दिनेश श्रीवास्तव के प्रति कृतज्ञ हूँ जिन्होंने सर्वेक्षण के दौरान सम्बंधित सूचनाएँ प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया।

साथ ही मैं अपने भाइयों धीरेन्द्र खरे व आनन्द सिन्हा, अखिलेश निगम उनका आभार व्यक्त करती हूँ उन्होंने सर्वेक्षण के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान किया। और अपनी छोटी बहनों मणि रूपाली, गीता, सीमा, की भी आभारी हूँ। जिन्होंने समय-समय पर पुस्तक आदि शोध सामग्री उपलब्ध कराकर मुझे सहयोग प्रदान किया।

अन्त में मुझे विश्वास है कि इस गवेषणात्मक अनुशीलन को अर्थशास्त्र क्षेत्र के अधिकारों विद्वानों एवं मौलिक चिन्तकों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होगा और यह कृति अपनी मूल्यवत्ता से समाद्रित हो सकेगी। यदि जनपदीय औद्योगिक विकास की नीतियों के सन्दर्भ में यह प्रयास किसी भी प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है तो शोधानार्थी उसे अपने श्रम का पुरस्कार समझेगी।

इसी आकांक्षा के साथ:-

^{कृतज्ञ}
कंचन श्रीवास्तव

शोध केन्द्र-पं० जवाहर लाल नेहरू
कालेज बाँदा (उ०प्र०)

अध्याय अनुक्रम

	पृष्ठ संख्या
आमुख	1.2
प्रथम अनुक्रम	3-35
द्वितीय अनुक्रम	36-52
तृतीय अनुक्रम	53-67
चतुर्थ अनुक्रम	68-83
पंचम अनुक्रम	84-93
षष्ठम अनुक्रम	94-109
सप्तम अनुक्रम	110-116
अष्टम अनुक्रम	117-125
परिशिष्ट	126-137
अ. उ०प्र० की औद्योगिक नीति	
ब. जिला उद्योग केन्द्र एवं आधारित उद्योग	
स. कृषि आधारित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान	
द. कृषि-आधारित उद्योग एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण	
य. कतिपय महत्वपूर्ण सारणियां	
संदर्भ अनुक्रमणिका	138-140
अ. ग्रन्थ	
ब. लेख	
स. रिपोर्ट	
द. समाचार पत्र	
य. विविध - पत्रिकायें	

सारिणी अनुक्रमणिका

(अ) 1.1	बाँदा जनपद में मुख्य फसलों की स्थिति	5
(अ) 1.2	बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों की स्थिति	6
(अ) 1.3	बाँदा जनपद में लघु व ग्रामीण उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या	7
(ब) 1.1	बाँदा जनपद में मुख्य फसलों की स्थिति	10
(ब) 1.2	जनपद में औद्योगिकरण की प्रगति	12
(ब) 1.3	जनपद में उद्योगों की संख्या	13
	बाँदा नगर में संचालित कृषि-आधारित उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत मिलों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने में व्यय की गई	25
2.1	पूँजी का परिमाण	38
2.2(अ)	जनपदों में कृषि विकास में सहायक यन्त्रीकरण खाद व बीजों की स्थिति (जो उद्योगों द्वारा प्राप्त है)	40

2.2(ब)	जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों को प्राप्त कच्चा माल	42
2.4(अ)	फसलों की उत्पादन	45
2.4(ब)	उद्योगों की स्थिति	46
2.4(स)	रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या	47
2.5(अ)	जनपद में फसलों की औसत उपज (कु० प्रति० हेक्टेयर)	49
2.5(ब)	जनपद की श्रम की मात्रा	51
3.1	कृषि-आधारित उद्योगों का विकास खण्ड- वार स्थानीयकरण	53
3.4	बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत मिलों में उत्पादन निष्पादन की स्थिति	64
4.3(अ)	बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की सारणी	75
4.3(ब)	प्रदत्त बैंक ऋण	76
4.3(स)	जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों की प्राप्त वित्तीय सहायता	78
4.4	उत्पत्ति वृद्धिमान नियम	81
5.1	बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग के विभिन्न फर्मों (मिलों) में मजदूरी की प्रकृति	85
5.2	बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों में रोजगार में लगे श्रमिक	87
5.3	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में रोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा आय में वृद्धि	88
5.4(अ)	बाँदा नगर में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति	91
5.4(ब)	कृषि-आधारित उद्योगों में विभिन्न मिलों में श्रमिकों की कार्य अवधि की परिगणना	92
6.1(अ)	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों में विभिन्न मिलों में नवीनीकरण लागत की परिगणना	95
6.1(ब)	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों में मिलों में उत्पादित वस्तुओं की लागत का परिणाम	96
6.3	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत 50 मिलों के द्वारा बेचे गये उत्पादन की मात्रा तथा उससे प्राप्त विक्रय मूल्य	100
6.4	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों में मिलों को प्राप्त कुल आगम की स्थिति	103
6.5	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में लाभ परिगणना	107
7.5	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों के प्रबंधकों द्वारा अनुभावित कठिनाईयाँ; बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों में स्वामित्व प्रकार जनपदों में विकास खण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण	115
		130

चित्र-कोशिका

3.3(अ)	सैद्धान्तिक संभावना रेखाचक्र	62
3.3(ब)	मिलों का उत्पादन सम्भावना वक्र	62
3.4	जनपदों कृषि-आधारित उद्योगों में कार्यरत 50 मिलों का उत्पादन निष्पादन	66
4.1	मिलों की प्रबंध व्यवस्था	70
4.3	बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग को प्राप्त वित्तीय सहायता	
6.1	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों में मिलों में उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत	97
6.2	मांग व पूर्ति कीमत निर्धारित वक्र	98
6.4	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में मिलों को प्राप्त कुल आगम	104
6.5	बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में लाभ की परिगणना	109
7.1	बाँदा नगर में कृषि-आधारित उद्योग, फर्मों द्वारा अनुमानित कठिनाईयाँ	116

मानचित्र

1.1(अ)	भारत-उत्तर प्रदेश, बाँदा
1.3	बाँदा जनपद के विकास खण्ड



प्रथम अनुक्रम

1.1 पूर्व पीठिका

(अ) भारतीय अर्थव्यवस्था व कृषि-आधारित-उद्योग

(ब) जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना के विशिष्ट पहलू

(स) शोध समस्यागत साहित्य-सिंहवलोकन

1.2 शोध समस्या का स्वरूप एवं शोध-अभिकल्प

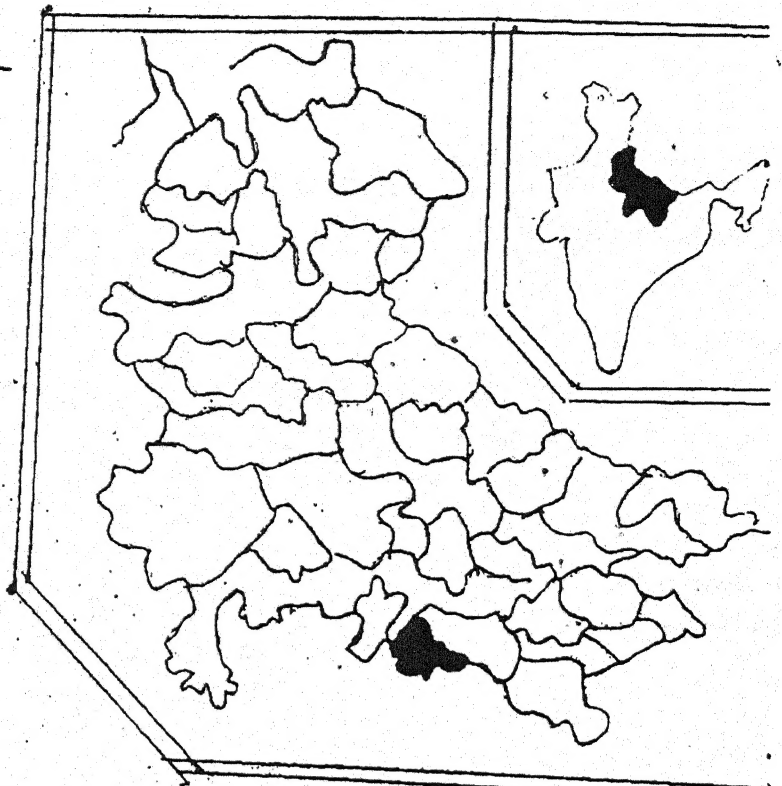
1.3 शोध समस्या की कतिपय संकल्पनायें

1.4 शोध की प्रवर्तमान प्रासंगिकता, सीमायें एवं अवधारणायें

1.5 अध्ययनगत प्रारूप

भारत का मानचित्र

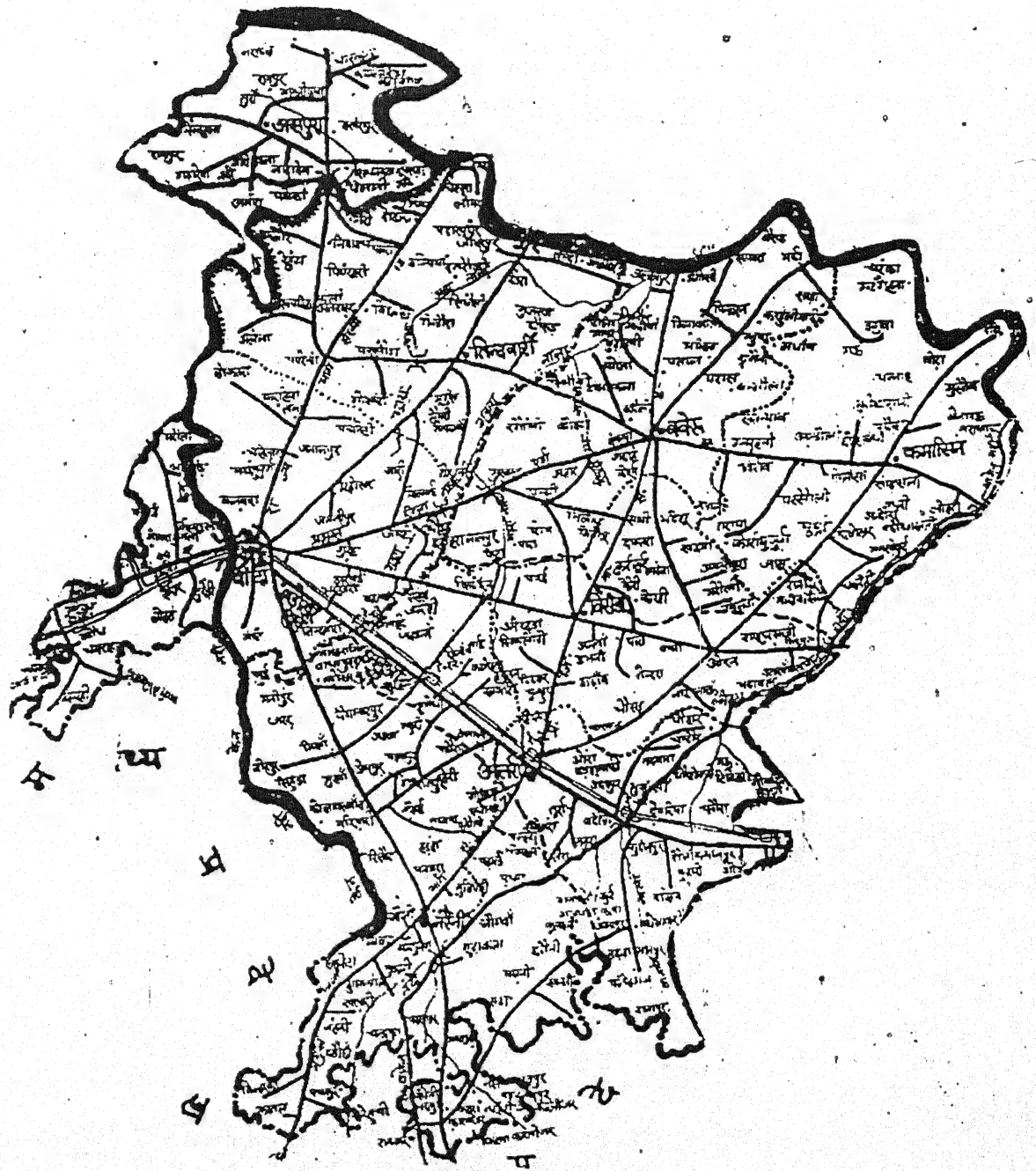
उत्तर प्रदेश का मानचित्र



बौदा जनपद का मानचित्र



बाँदा जनपद का मानचित्र



(अ) पूर्व पीठिका

भारतीय अर्थव्यवस्था व कृषि-आधारित उद्योग-

भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। देश के रीढ़ की हड्डी के रूप में कृषि के रूप में कृषि ही कार्य कर रही है। भारत वर्ष की आधार स्तम्भ कृषि ही है। इसलिये देश के अधिकांश उद्योग कृषि पर ही आधारित है। जैसा नेहरू जी ने कहा है कि “कृषि उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण है कारण स्पष्ट कि हमारे उद्योग कृषि पर ही निर्भर करते हैं।”¹

अतः कथन स्पष्ट है कि हमारे देश की जनसंख्या 84,63,02,6,882 है इसमें ग्रामीण जनसंख्या 62,86,91,6,76² है। इस प्रकार 25.7 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में अनेक प्रकार की खनिज पदार्थ वनस्पति कृषि उत्पादन होता है। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था की अनेक विशेषताये हैं-

भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। अर्थात् बहुत नीचा है। इसलिये अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में औद्योगीकरण का अभाव है। बड़े व लघु उद्योगों की कमी है। व यातायात एवं संचार के साधनों की कमी है इसलिये कृषि विपणन में कठिनाई होती है।

इसलिये भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि आधारित औद्योगिक की मूल संकल्पना कृषि है। और इसका मूल उद्देश्य ग्राम्य आर्थिक संरचना को उर्ध्वमुखी रूप में रूपान्तरित करना है ।

भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। यहाँ कि कुल जनसंख्या 13,91,12,28,73³ है। इसमें ग्रामीण

-
1. पाटनी.आर0. एस0-औद्योगिक अर्थशास्त्र
 2. प्रतियोगिता दर्पण - अतिरिक्तांक
 3. उत्तर प्रदेश वार्षिकी-1997-98

जनसंख्या 11,15,06,372 है। अर्थात् 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है। अतः 80 प्रतिशत लोगो की जीविका का साधन कृषि है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों का ही सहारा दिया जा रहा है। क्योंकि 1994-1995 में 5 लाख व्यक्तियों को इन उद्योगों में रोजगार मिला था जो बढ़कर 8 लाख हो गया। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें-गन्ना, कपास, धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना है। अतः इस प्रदेश चीनी उद्योग, सूती उद्योग, जूट उद्योग, चावल मिल, दाल मिल अधिक मात्रा में है।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड सम्भाग के मण्डल (चित्रकूट धाम मण्डल) का मुख्यालय बाँदा नगर में स्थित है। बाँदा नगर का नाम बाँदा बामदेव के नाम पर रखा गया है इस मण्डल में महोबा, कर्वी, हमीरपुर, तथा बाँदा जिले आते हैं। मण्डल का अस्तित्व भी पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। मण्डल में भी कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता है।

चित्रकूट धाम मण्डल में बाँदा जनपद जहाँ भौगोलिक दृष्टि से चौथा स्थान रखता है वही पठारी होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद है। इस जनपद की प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना निम्न स्तरीय है यद्यपि बाँदा जनपद कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। और यहाँ के कुल उत्पादन का 92 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है यहाँ की मुख्य फसले चावल, तिलहन, गेहूँ, मटर, अरहर, मूँग, जूट, कपास, तम्बाकू है। इनको एक तालिका द्वारा इस प्रकार दृष्टव्य किया जा सकता है-

तालिका- (अ) 1.1

बाँदा जनपद में मुख्य फसलों की स्थिति (मीटरी टन में)

फसल	1980-85	1993-94	1995-96	1997-98
चावल	325839	53545.0	53248.00	5428.60
दालें	167718	59.00	161182.00	171262.00
तिलहन	4511	3815400	6266.00	6364.00
गन्ना	28800	180376.00	27835.00	2880.00
जूट	--	--	--	--
कपास	--	2824.00	--	--

स्रोत- सांख्यिकीय पत्रिका 1980-85-93--94- 97-98

अतः तालिका से स्पष्ट है कि कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है इसलिये पहले उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं कि कृषि आधारित उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं उद्योग तीन प्रकार के होते हैं-

- 1-प्राथमिक क्षेत्र- प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व अन्य औपचारिक क्षेत्र के उद्योग आते हैं।
- 2- द्वितीयक क्षेत्र- द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण एवं संगठित क्षेत्र के उद्योग आते हैं।
- 3-तृतीयक क्षेत्र - परिवहन संचार एवं भण्डारण आदि की सेवायें की जाती हैं।

अतः कृषि आधारित उद्योग प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में मुख्य रूप से धान मिल, चावल मिल, आटा मिल, तेल मिल, चीनी मिल, कताई मिल, जूट मिल, बीड़ी उद्योग, निर्माण उद्योग आदि आते हैं।

जनपद में चार तहसीलें-1:-बाँदा 2:-बबेरु 3:-नरैनी 4:-अतर्रा तथा 8 विकास खण्ड

1:-बड़ोखर खुर्द 2:-तिन्दवारी 3:-जसपुरा 4:-बबेरु 5:-कमासिन 6:-बिसण्डा 7:-महुआ 8:-नरैनी। इन सभी तहसीलों व विकास खण्डों में कृषि बहुत मात्रा में होती इस पूरे जनपद

में कृषि उद्योगों की बाहुल्यता है। यहाँ कुल उद्योगों की संख्या 24705 है। इसमें ग्रामीण व लघु उद्योग 3288 है। जनपद में कृषि आधारित उद्योगों को एक तालिका द्वारा दिखाया जा सकता है।

तालिका:- (अ)1.2

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों की स्थिति

उद्योगों का नाम	1985-86	1993-94	1998-99
धान मिल	10	15	28
आटा मिल	-	-	-
दाल मिल	8	10	-
तेल मिल	12	18	75
गुड़ बनाने की ईकाई	-	-	5
बीड़ी बनाने की ईकाई	10	21	28
कताई मिल	-	1	2
कालीन उद्योग	-	2	5
दोना पत्तल निर्माण ईकाई	10	22	26
सुतली बनाने की ईकाई	8	10	18

स्रोत औद्योगिक निर्देशिका जिला उद्योग केन्द्र -बाँदा

अतः तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में कृषि-आधारित लघु उद्योग अधिक मात्रा में है। इन उद्योगों में अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला इस स्थिति को तालिका द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कर करते हैं-

तालिका:- (अ) 1 . 3

बाँदा जनपद में लघु व ग्रामीण उद्योगों में
लगे व्यक्तियों की संख्या-

उद्योग	1985-86	1993-94	1996-97	1998-99
लघु उद्योग ईकाइयों में कार्यरत व्यक्ति	380	388	1767	1792
ग्रामीण एवं लघु उद्योग ईकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	911	921	3534	3665

स्रोत:-सांख्यिकीय पत्रिका- 1985-86, 93-94, 96-97, 97-98,

इस तालिका से स्पष्ट है कि कृषि-आधारित उद्योगों में जनपद के 65 प्रतिशत व्यक्ति लगा है। अर्थात् आधे से अधिक व्यक्तियों की जीविका का आधार कृषि ही हैं। यहाँ केवल इन उद्योगों में बरोजगारों व्यक्तियों को रोजगार ही नहीं मिला बल्कि जनपद में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अवसर प्रदान करेंगे। और जनपद में व्यक्तियों की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी और जनपद विकास की ओर उन्मुख होगा।

इस प्रकार देश व प्रदेश व जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर है कृषि ही पूरे ही देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है। आज देश में कृषि रूपी स्तम्भों पर ही अर्थव्यवस्था रूपी छत खड़ी है। जिस दिन इन स्तम्भों का सहारा नहीं मिलेगा तो छत गिर जायेगी और कृषि-आधारित उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का नियति करके अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं।

(ब) जनपद की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना के विशिष्ट पहलू-

भौगोलिक-संरचना:-

भारत 25 राज्यों में बाँटा गया है जिसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है। जिसका क्षेत्रफल 2,94,411 वर्ग किमी. है। जनसंख्या 1,38760,417 है जिसमें 73,743,994 पुरुष तथा 65,14,423 स्त्रियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 69 जिले हैं। जिसमें बाँदा भी एक जिला है। चित्रकूट धाम मण्डल का मुख्यालय भी बाँदा में स्थित है। इस मण्डल में बाँदा, कर्वी, (चित्रकूट धाम) हमीरपुर महोबा, चार जिले शामिल किये गये हैं। बाँदा का नाम बाँदा बामदेव ऋषि के नाम पर रखा गया है जो कर्णवती (केन नदी)के तट पर स्थित है। बाँदा जनपद का भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश में चौथा स्थान है। परन्तु पठारी क्षेत्र होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जनपद है। परन्तु इधर कुछ वर्षों से कृषि आधारित उद्योग इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

बाँदा जनपद की पावन भूमि को भगवान रामचन्द्र जी ने अपना वनवास स्थल बनाया था। शिरोमणि श्री तुलसीदास ऋषि की तपस्थली होने का गौरव प्राप्त है। कालिंजर किला तथा अन्य किलों के भग्नावशेष प्राचीन वैभव कला तथा संस्कृति के प्रतीक हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इस जनपद का महान योगदान चिरस्मणीय रहेगा।

बाँदा जनपद 30°30' की दक्षिणी सीमा पर स्थित है यह जनपद 24°53' और 25°55' उत्तरी अक्षांश तथा 80°70' पूर्व से 81°54' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। जनपद के पूर्व में इलाहाबाद पश्चिम में हमीरपुर, उत्तर में फतेहपुर, तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश की सीमाये इसे स्पर्श करती है। इस प्रकार बाँदा जनपद का विस्तार पूर्व से पश्चिम 147 कि०मी० तथा उत्तर से दक्षिण 104 कि०मी० है। जनपद का क्षेत्रफल 76.24 वर्ग कि०मी० है।

जनपद की जलवायु कर्क रेखा के समीप होने के कारण, बीहर पहाड़, चट्टाने एवं पथरीली भूमि होने के कारण अधिक शुल्क रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु शीघ्र प्रारम्भ हो जाती है। तथा देर तक रहती है। वार्षिक औसत उच्चतम 50.4 तथा न्यूनतम 19.9 से 0 ग्रे 0 रहता है।¹

प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाँदा जनपद 4 तहसीलों (बाँदा, बबेरु, नरैनी तथा अतर्रा है) तथा 8 विकास खण्डों (जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर, महुआ, बिसण्डा, बबेरु, कमासिन तथा नरैनी) और पुलिस चौकी (कालिंजर, खुरंहण्ड, तथा ओरन एवं बाँदा 18 पुलिस थाना (मार्का) जसपुरा, पैलानी, चिल्ला, तिन्दवारी कोतवाली देहात कमासिन, बबेरु, बिसण्डा, बदौसा, अतर्रा, करतल, नरैनी, गिरवाँ, महुआ, बाँदा कोतवाली तथा मटौध में विभक्त है।

जनपद में खाद क्षेत्र में बबूल तथा काटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है जिसमें करौंदा, करील, खेर, चमरौल, महुआ, ईगोटक तथा सहजन आदि होते हैं। जनपद के पाठा क्षेत्र में टाक, सेज तेंदू, अचार, चिरौंजी, हरदू साज, बासों से जगल पाये जाते हैं।

इस जनपद में केन, करतल, बागैन, ओहन, नदी, गरारा नदियाँ बहती हैं। केन जनपद की सबसे लम्बी नदी है।

जनपद की जनसंख्या 1991 में 18,62,139² है इसमें ग्रामीण जनसंख्या 16,22,718 है। तथा नगरीय जनसंख्या 1,88,013 है जहाँ जनसंख्या घनत्व 232 वर्ग कि०मी० है। इसमें 528 हजार व्यक्ति साक्षर हैं। यहाँ 1991 पुरुष जनसंख्या 10,11 हजार है, तथा स्त्रियों की जनसंख्या 1991 में 8,51 हजार है तथा जनपद में कुल साक्षर पुरुष 1991 में 528 हजार है। तथा जनपद में कुल साक्षर स्त्रियों की संख्या 1991 में 1,10 हजार थी।

1. गजेटियर, बाँदा

2. सांख्यिकीय पत्रिका 1994-95 (अर्थ संख्या विभाग कार्यालय, बाँदा)

प्राकृतिक संरचना के अनुसार बाँदा जनपद दो उप सभागों में बाँदा गया है। प्रथम सभाग में 1203 आबाद ग्राम है तथा 138 गैर आबाद ग्राम कुल 1344 ग्राम है द्वितीय सभाग में 677 आबाद ग्राम तथा 44 गैर आबाद ग्राम है।

जनपद कृषि में कुल क्षेत्रफल 580909 हेक्टेयर है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 144 हेक्टेयर है। यहाँ खाद्यान उत्पादन 541.57 मी०टन है। गन्ना 29.78 मी० टन उत्पादन होता है।

बाँदा जनपद में मुख्य रूप से धान, अरहर, मसूर, चना, गेहूँ, ज्वार, जौ, बाजरा, तम्बाकू, जूट, कपास, सनई, हल्दी, तिलहन की खेती होती है। इस प्रकार जनपद के 580909 क्षेत्रफल में की जाती है।

सारिणी संख्या-(ब) 1.1

बाँदा जनपद में मुख्य फसलों की स्थिति (मीटरी टन में)

फसल	1980-85	1985-90	1990-91	1991-92	1995-96
मसूर	12948	104136	125199	80003	16653.88
धान	91342	48568	81335	53530	92948.00
बाजरा	10541	8337	10432	7896	25.00
गेहूँ	203766	197259	220656	206408	78154.00
ज्वार	77843	58995	64964	41851	8314.00
तम्बाकू	140417	11345	13597	13624	15.00
जूट	--	--	--	--	--
सनई	--	526.00	538.00	437.00	46.00
कपास	--	11434.00	2824.00	--	--

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में मुख्य रूप से मसूर, धान, बाजरा, गेहूँ, ज्वार, तम्बाकू, जूट, सनई की फसल होती है।

सामाजिक संरचना:-

समाज मुख्यतः दो वर्गों में बाटा गया है सवर्ण एवं निम्नवर्ग प्रभावकारी वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, लोग सम्मिलित है।

जबकि शोषित वर्ग के अन्तर्गत डुमार, धानुक, लोधी, चमार, मेहतर, आदि सम्मिलित है। शेष जातियों की भूमिका कही उदासीनता की तथा कटी स्वार्थीपन की है। यही कारण है कि इस जिले में वर्ग संघर्ष अतः समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। जाति पाँति एवं पारस्परिक वैमनस्यता के कारण ग्रामीण समाज के अधिकांश लोग पारिवारिक कलह के शिकार है। समाज सामान्यता प्रतिक्रियावादी है। अन्य स्थानों की भैति समाज में हत्या, लूट, कत्ल, चोरी, डकैती, बलात्कार आदि सामाजिक अपराध चरम सीमा पर है। जहाँ एक ओर राजनीतिक अव्यवस्था अशिक्षा, रुढ़िग्रस्तता, धार्मिक ढोंग, श्रम का निरादर असम्मान इस समाज में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक प्रवृत्ति का पाया जाना, देश के प्रति निष्ठा की भावना है। कुल मिलाकर समाज की दशा शोचनीय है।

आर्थिक संरचना:-

बाँदा जनपद आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ा है। जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। इस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 30प्र0 के अन्य जिलों की तुलना में निम्नस्तरीय है। यहाँ के कुल उत्पादन का 92प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। किन्तु बाँदा जनपद की कृषि क्षेत्र की दशा थोड़ी शोचनीय है। अतः कृषि प्रधान क्षेत्र भी बाँदा के आर्थिक पिछड़ेपन के लिये उत्तरदायी है। यहाँ का औद्योगिक पिछड़ापन भी जनपद के आर्थिक विकास की दर को कम करने में सहायक है। इस जनपद में कृषि की बाहुल्यता होने के कारण कृषि आधारित उद्योग अधिक संख्या में है। यहाँ कुल श्रम शक्ति का केवल 8 प्रतिशत भाग ही

जीवकोपार्जन हेतु औद्योगिक क्रिया कलापों में संलग्न है। यहाँ उद्योगों की कुल संख्या 24705 1 है। जनपद में उद्योगों की स्थिति एक तालिका द्वारा नीचे स्पष्ट की गयी है।
जिन उद्योगों पर जनपद की आर्थिक स्थिति निर्भर है।

सारिणी - (ब) 1.2

जनपद में औद्योगिकरण की प्रगति

क्र. सं.	मद	94-95	95-96	96-97
1.	पंजीकृत कारखाने	--	28	28
2.	कार्यरत कारखाने	--	31	31
3.	औसत दैनिक कार्यरत श्रमिक व कर्मचारियों की संख्या	1285	1285	
4.	उत्पादन मूल्य	--	132832	133832

1:-सांख्यिकीय पत्रिका- अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्यालय उ०प्र० -1997 तालिका स्त्रोत्र
सांख्यिकीय पत्रिका-1997

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में उद्योगों की संख्या बहुत कम है
इस कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। इस जनपद में लघु व ग्रामीण उद्योग की स्थिति इस
प्रकार है-

तालिका (ब) 1.3

क्रम सं०	उद्योग का नाम	योग
1	खादी ग्रामोद्योग	1368
2	खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण उद्योग	96
3	लघु उद्योग ईकाई	113
	3.1 इन्जीनियरिंग	54
	3.2 रासायनिक	6
	3.3 विधारान	6
	3.4 हथकरघा	8
	3.5 रेशम	994
	3.6 नारियल की जटा	669
	3.7 हस्तशिल्प	
	3.8 अन्य	
	योग	3288

स्त्रोत:- सांख्यिकीय पत्रिका- 1994-95-97 व उद्योग निदेशालय बाँदा

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद बाँदा में लघु व ग्रामीण उद्योग दोनों हैं जनपद में एक बड़ी कटाई मिल थी जो वर्तमान में बन्द चल रही है। अतः जनपद आर्थिक दृष्टि से पिछड़ होने पर भी धीरे-धीरे अपनी आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है।

(स) शोध समस्यागत साहित्य-सिंहावलोकन

किसी भी शोध कार्य का प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बंधित साहित्य का सिंहावलोकन व सर्वेक्षण आवश्यक होता है। क्योंकि सम्बंधित साहित्य के अध्ययन के अभाव में शोधकार्य प्रस्तुत शोध से सम्बंधित अध्ययन सामग्री का अभाव है जो अध्ययन सामग्री है वो लघु

उद्योगों के सम्बंध में उपलब्ध है इसमें डा० आर०ए० चौरसिया की पुस्तक “Agro Industrial Development-A Study ” योजना मासिका पत्रिका ” प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली सांख्यिकीय पत्रिका(अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रकाशित) Brojendra Nath Bonergee की किताब “Industry Agriculture and Rural Development जिला उद्योग द्वारा प्रकाशित “औद्योगिक निर्देशिका आदि ।

उपरोक्त सामग्री भी पूर्णता कृषि-आधारित उद्योगों से सम्बंधित नहीं है जो सामग्री है भी वे आसानी से उपलब्ध नहीं होती है इस शोध विषय से सम्बंधित आकड़े भी समय से कार्यालय से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि शोध समस्या से सम्बंधित सामग्री उपलब्ध नहीं है जो सामग्री है भी लघु व कुटीर उद्योगों से पूर्णतः सम्बंधित साहित्य का अभाव है।

१.२ शोध समस्या का स्वरूप एवं शोध-अभिकल्प -

प्रस्तुत शोध समस्या के पीछे सबसे तात्कालिक एवं सशक्त प्रेरणा आज देश में व्याप्त आर्थिक समस्या है। आज देश के आर्थिक संकट से निपटाने के लिये कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये । यही कृषि-आधारित उद्योग ही देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। तथा देश में बड़ी संख्या में लोगों की जीविका प्राप्त हो रही है देश में कृषि आधारित उद्योगों तैयार समान का विदेशों में निर्यात किया जाता है जिससे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अतः देश के आर्थिक विकास में कृषि आधारित उद्योगों का गौरवपूर्ण स्थान है अनेक बड़े देशों में यह उद्योग अपनी चरम सीमा में पहुँच चुके लेकिन बुन्देलखण्ड क्षेत्र का बाँदा जनपद इस क्षेत्र में सबसे पीछे है आज भी यह जनपद औद्योगिक अपेक्षा का शिकार है। आज बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में मन्दगति से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है आज कृषि-आधारित उद्योगों की ओर न व्यक्ति न सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है । जबकि इन उद्योगों का अपनाअलग महत्व है। क्योंकि

आज देश निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोग इस उद्योग से किसी न किसी प्रकार से सम्बन्धित हैं। आज देश की आधे से अधिक जनसंख्या की जीविका का साधन है। बाँदा नगर में कृषि आधारित उद्योगों के विकास एवं ह्रास की अपनी विशिष्ट आर्थिक एवं तन्त्रगत समस्याएँ हैं। राजकीय उप्रेक्षा एवं वित्तीय तथा तकनीकी कुपोषण से पुष्ट इस उद्योग की समस्याएँ एवं भविष्यगत सम्भावनाओं की जानकारी ही मेरे शोध समस्या के चयन का कारण है अर्थात् बाँदा जनपद के विशेष संदर्भ में बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि आधारित औद्योगिकरण की अवस्थिति निष्पादन समस्याओं एवं सम्भावनाओं का एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (सातवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक) प्रस्तुत शोध का कथ्य विषय है।

शोध समस्या का कथन -

नगर की दी हुई सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति में अन्तर्गत आर्थिक विश्लेषण के साप्रेक्ष प्रस्तुत शोध समस्या का मुख्य कथन यह है। “बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि - आधारित औद्योगिकरण” (अवस्थिति, निष्पादन, समस्याओं, एवं सम्भावनाओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन) सातवीं पंचवर्षीय योजना से अद्यतन समय तक। इस शोध के द्वारा कृषि -आधारित उद्योग से सम्बन्धित अन्य उद्योगों के विकास की सम्भावनाओं के लिये नये आयाम प्रस्तुत किये जा सकते हैं। स्पष्ट है कि इन सभी आयामों के अनुशीलन का नगरीय परिप्रेक्ष्य में अनुभवगम्य एवं विकासात्मक महत्व है।

इन उद्योगों के द्वारा बाँदा जनपद का आर्थिक विकास उच्च शीर्ष तक कर सकते हैं।

शोध-अभिकल्प-

शोध अध्ययन वह प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसी भी क्षेत्र में ज्ञान सम्बर्द्धन के प्रयास किये जाते हैं शोध प्रक्रिया का सार तत्त्व मुख्यतः दो बातों पर निहित है- प्रथम शोध अध्ययन के उद्देश्य तथा द्वितीय अनुसंधान अभिकल्प जहाँ तक शोध

अध्ययन के उद्देश्य का सवाल है वह चयनित शोध समस्या की प्रक्रिया एवं उसकी प्रसंगिकता से अनुशासित होता है वास्तव में नवीन एवं प्राचीन तथ्यों के सम्बंध में अनुशीलन करके तथा पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा करके सामाजिक आर्थिक घटनाओं के सम्बंध में हमारे ज्ञान को प्रगतिशील बनाये रखना अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इस प्रकार शोध अध्ययन के उद्देश्यों में चयनित शोध समस्या के स्वरूप का समावेश होता है, इस सन्दर्भ में अग्रगामी विवरण से पूर्व इस तथ्य पर विचार कर लेना उचित होगा कि शोध अभिकल्प क्या है।

शोध अभिकल्प की अवधारणा-

शोध अध्ययन की पूर्व योजना बनाना ही शोध अभिकल्प तैयार करना है। शोध अध्ययन के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों की उद्घटित करने के लिये पहले से ही बनाई गई योजना की रूप रेखा को शोध अभिकल्प कहते हैं। फरलिंगर के अनुसार अनुसंधान अभिकल्प को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है “अनुसंधान अभिकल्प नियोजित अन्वेषण की एक ऐसी योजना, संरचना तथा व्यूह संरचना होती है, जिसके आधार पर शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जाते हैं और प्रसरण पर शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किया जाते हैं और प्रसरण पर नियन्त्रण स्थापित किया जाता है।”¹

ऐकॉफ के अनुसार “To design is to plan, that is, & design is the process of making decisions before the situation arises in which the decision has to be carried out. It is a process of deliberate anticipation directed to word bringing an expected situation under control.”²

संक्षेप में शोध अभिकल्प को सरलतम शब्दों में निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है,

-
1. Kerlinger ; F. N. Foundation of Behavioural research (Hot) 1964, 9-275
 2. Achoff : The Design of Social Research, Chicago Press, P-5.

Research design as mapping strategy. It is essentially a statement of the object of the inquiry and the strategies and reporting in the findings." ¹

स्पष्ट शोध अभिकल्प वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रम का एक अभिन्न अंग है । अभिकल्प रचना शोध कर्ताओं को एक विशिष्ट सांख्यिकीय परिकल्पना की रचना आकड़ों के संकलन तथा उनके विश्लेषण के प्रति अति महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा इसके आधार पर सम्भावित निष्कर्षों को जानने में अत्यधिक मार्गदर्शन करती है।

व्यापक रूप में शोध अभिकल्प के अन्तर्गत अध्ययन की समस्या का निरूपण आकड़े संकलन की विधि समग्र और निदर्शन आदि निश्चित किये जाते हैं।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त अभिकल्प का प्रकार - अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार शोध अभिकल्प को तैयार किया जाता है अनुसंधान के प्रकार के अनुसार अभिकल्प बनता है अभिकल्प के प्रकार इस प्रकार हैं।

- 1:- प्रयोगगम्य शोध-अभिकल्प
- 2:- सांख्यिकीय शोध-अभिकल्प
- 3:- सैद्धांतिक शोध-अभिकल्प
- 4:- विवरणात्मक शोध-अभिकल्प
- 5:- क्षणिक शोध-अभिकल्प

प्रस्तुत अध्ययन में विवरणात्मक या वर्णनात्मक शोध अभिकल्प प्रयुक्त की गयी है। यह शोध अभिकल्प बहुत ही सरल अध्ययन के लिये बनाया जाता है इसके अन्तर्गत कारण कार्य की स्थापना नहीं होती है। साधारण सर्वेक्षण किया जाता है श्री ए० काम्पबेल ए० एण्ड करोना जी के अनुसार "Survey research is considered to be a forerunner of social scientific

research which immediately distinguishes Surveys research from the status survey.¹

जैसे-प्रतिशत एवं माध्य आदि का प्रयोग किया जायेगा।

किसी भी शोध अध्ययन को क्रमबद्ध एवं दिशात्मक बनाने के लिये तर्कों को सत्यापित करने में अनुसंधान पद्धतियों का अत्यधिक महत्व है। ये अनुसंधान पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं।

1:- प्रयोगिक अनुसंधान

2:- क्षेत्र अनुसंधान

3:- सर्वेक्षण अनुसंधान

4:- मूल्यांकन अनुसंधान

5:-क्रियापरक अनुसंधान

6:- एक्स पोस्ट फेक्टो रिसर्च ।

सर्वेक्षण प्रवृत्ति में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सीधे सम्पर्क में आता है ऐसा इसलिये होता है कि इस विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षणकर्त्री को अपने विषय से सम्बंधित परिस्थितियों तथा व्यक्तियों से सीधे तौर पर तथ्यों को सम्मिलित करना पड़ता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनुसंधान कर्ता को उनके साथ निकट या धनिष्ठ सम्बंध स्थापित करना पड़ता है। सर्वेक्षण की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से सम्बंधित परिस्थितियों तथा व्यक्तियों से सीधा सम्पर्क स्थापित करने में कितना सफल हो सकता है।

समंक संकलन के उपकरण :-

अनुसंधान की समस्या के अनुसार आकड़ा संकलन के लिये उपयुक्त उपकरण का

1. काम्पबेल, ए0 एण्ड कटोना जी, दि सेम्पल सर्वे ए टेक्नीड फोर सोशल साइंस रिसर्च "इन एल फेस्टिनेजेय डी0केट्स रिचर्स मेथड्स दि विहेवोरिय साइंस न्यूयार्क हाल्ट एण्ड विन्सटन।

चुनाव करना होता है। शोध अध्ययन के व्यवहार्य अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण निम्न होते हैं-

- 1:- प्रश्नावली
- 2:- साक्षात्कार सूची
- 3:- पैमाने की दर
- 4:- जाँच या सत्यापन शीलता

१:- प्रश्नावली-

आधुनिक शोधों में प्रश्नावली का उद्देश्य अध्ययन विषय से सम्बंधित प्राथमिक तथ्य-सामग्री को सकत्र करना है। प्रश्नावली का अर्थ उस सुव्यवस्थित तालिका से है जो विषय के सम्बंध में सूचनायें प्राप्त करने में सहयोग देती है।

गुडे तथा हैट के शब्दों में In general the word questionnaire refers to a device for securing on swexs to qeustions by using a form which the respondent fills in himself."¹

२:- साक्षात्कार अनुसूची -

समंक संकलन का एक अति प्रचलित उपकरण अनुसूची एक अनुसंधान समस्या से सम्बंधित तर्क संगत प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता उत्तरदातओं से प्रायः पूर्व निर्धारित सम्पर्क के अनुसार सम्बंधित प्रश्नों के प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्राप्त करता है एवं सूची को स्वयं अपने आपसे भरता है। स्पष्टतः “ अनुसूची का तात्पर्य अनुसंधान कर्ता द्वारा सूचनाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के आयोजित एवं व्यवस्थित प्रपत्र से है”²

1. Good and Halt-Methods in social research.

2. गुप्ता, आर०बी० एवं गुप्ता मीरा, सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, कानपुर ३०प्र०

प्रस्तुत शोध प्रबंध में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है जब शोध करने वाला कुछ प्रश्न लिखकर स्वयं सूचनाओं के पास जाता है और उनसे पूँछ-पूँछ कर प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखता है इस प्रकार की अनुसूची को साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। सम्बंधित अनुसंधान समस्या के गहन अध्ययन का भी समुचित अवसर प्राप्त होता है। इससे प्राप्त आकड़ों के वर्गीकरण तथा सरणीयन में भी विशेष सुविधा रहती है सहायक सूचनाओं की प्राप्ति के लिये एवं संकलित सूचना की परीक्षा के लिये भी यह अनुसूची उपयोगी है, व्यक्तिगत रूप से सूचना दाता मिलकर सम्बंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ही इस प्रकार अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य है।

1:- पैमाने की दर-

पैमाने एक प्रमाणन उपकरण है जिसके आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन क्रमिक ढंग से किया जाता है।

गुडे एवं हॉट के अनुसार:-

“स्केलिंग प्रविधि द्वारा मर्दों की किसी श्रृंखला को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। दूसरे शब्दों में स्केलिंग प्रविधियों गुणात्मक तथ्यों की श्रृंखला को मात्रात्मक श्रृंखला में बदलों की विधियाँ हैं।”¹

जाँच या सत्यापन शीलता-

किसी भी अध्ययन की प्रमाणिकता के लिये यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित तथ्यों की पुनः परीक्षा या सत्यापन किया जाये।

अतः स्पष्ट है कि इस शोध प्रबंध में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है।

समंको के आधार पर-

वास्तविक आंकड़ों के बिना कोई भी शोध या अनुसंधान वास्तव में अंपग प्राणी की भांति

1. गुडे और हॉट- मेथड्स इन सोशल रिसर्च

है” शोध की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय के सम्बंध में कितने वास्तविक सूचनाओं एवं तथ्यों अथवा आंकड़ों को एकत्रित करने में सफल होता है। अतः अनुसंधान प्रवृत्ति में समंको के संकलन की दृष्टि से समंक दो प्रकार के होते हैं।

1- प्राथमिक समंक

2- द्वितीय समंक

१-प्राथमिक समंक-

प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता नये सिरे से एकत्र करता है। प्राथमिक समंक अनुसंधान कर्ता द्वारा वास्तविक अध्ययन स्थल में जाकर विषय या समस्या से सम्बंधित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके समस्या से सम्बंधित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से संकलित किये जाते हैं।

२-द्वितीयक समंक-

द्वितीयक समंक वे आंकड़े हैं जो कि शोधानार्थी को प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों सांख्यिकीय प्राण्डलिपि पत्र डायरी आदि से प्राप्त होते हैं।

संक्षेपतः किसी भी शोध अध्ययन की प्रकृति एवं निष्कर्ष समंक संकलन की विधि से बहुत प्रभावित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्षात्कार सूची द्वारा प्राथमिक समंक एकत्रित किये जायेंगे क्योंकि प्राथमिक समंकों के उद्देश्य अनुसंधान के अनुकूल होता है और प्रस्तुत शोध सर्वेक्षणात्मक है।

संकलित समंको के विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ-प्रस्तुत शोध अध्ययन में समंको के विश्लेषण में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ निम्नवत् हैं।

1. औसत, प्रतिशत एवं गणितीय माध्य
2. रेखाचित्र

3. समंको का चित्रमय प्रदर्शन

इसके अतिरिक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिये विभिन्न सूत्रों द्वारा केन्द्रीय प्रवृत्ति विचलन सह सम्बंध आदि ज्ञात करते हैं।

प्रस्तुत शोध में शोधनार्थी के द्वारा 50 मिलों का सर्वेक्षण कार्य साक्षात्कार अनुसूची द्वारा किया गया इसमें जिन 50 मिलों को लिया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं।

मिलों के नाम	पता	सन्(स्थापना वर्ष)
1. रामदास राजकुमार दाल मिल	गूलर नाका बाँदा	1950
2. अन्नपूर्णा राईस मिल	खुरहण्ड बाँदा	1976
3. श्री नारायण राईस मिल	बबेरु बाँदा	1988
4. मंसूरी चावल उद्योग	नरैनी बाँदा	1987
5. मिश्र आयल उद्योग	कनवारा बाँदा	1986
6. सीता राम राईस मिल	नरैनी बाँदा	1985
7. वैश्य आयल उद्योग	बाँदा	1982
8. लल्लू टिरिहाया आयल उद्योग	पैलानी बाँदा	1975
9. नवल किशोर आयल मिल	सब्जी मण्डी बाँदा	1976
10. ईश्वर चन्द्र तेल मिल	खुटला बाँदा	1980
11. राम चरन साहू आयल मिल	पैलानी बाँदा	1985
12. जुगुल किशोर आयल मिल	अलीगंज बाँदा	1990
13. अरुण आयल उद्योग मिल	नरैनी बाँदा	1990
14. नारायण राईस मिल	अतर्रा बाँदा	1970
15. अन्नपूर्णा दाल प्लान्ट	खुरहण्ड बाँदा	1983
16. भागवत प्रसाद चावल उद्योग	नरैनी, बाँदा	1993

17. महावीर राइस मिल	अतर्रा बाँदा	1970
18. रामनारायण कुशवाहा आइल मिल	बिसण्डा बाँदा	1988
19. श्री काशी प्रसाद गुप्ता राइस मिल	अतर्रा बाँदा	1970
20. श्री राम राइस मिल	नरैनी, बाँदा	1990
21. श्री रामफल कुशवाहा राइस मिल	बिसण्डा बाँदा	1980
22. चन्द्रभान गुप्ता आटा मिल	पैलानी बाँदा	1993
23. भूतेश्वर राइस मिल	खुरहण्ड बाँदा	1978
24. गुप्ता मिनी दाल उद्योग	मर्दन नाका बाँदा	1980
25. रस्तोगी दाल मिल	बबेरु बाँदा	1985
26. ओम प्रकाश गुप्ता तेल मिल	छोटी बाजार बाँदा	1980
27. दिनेश तेल उद्योग	छोटी बाजार बाँदा	1988
28. राम दास तेल मिल	मढ़िया नाका बाँदा	1986
29. ओम शिव शिवा आयल मिल	पीली कोठी बाँदा	1985
30. पदुम आयल मिल छाबी तालाब	अतर्रा रोड बबेरु बाँदा	1980
31. ललन आयल मिल	छाबी तालाब बाँदा	1887
32. पाण्डे राइस मिल	बिसण्डा बाँदा	1982
33. लोकचन्द आवत लाल राइस मिल	पीली कोठी बाँदा	1961
34. गौतम राइस मिल	अतर्रा बाँदा	1969
35. जय माँ दुर्गे मिनी राइस मिल	अतर्रा बाँदा	1976
36. विजय कुमार साहू	अतर्रा बाँदा	1989
37. रमेश लाही उद्योग	सिंहपुर बाँदा	1988
38. द्विवेदी मसाला उद्योग	कमासिन बाँदा	1985

39. कुशवाहा आयल उद्योग	बाँदा 1987	
40. श्री हरी शंकर गुप्ता राइस मिल	स्टेशन रोड, बाँदा	1989
41. गुप्ता आयल मिल	अम्बेदकर चौराहा, बाँदा	1987
42. शंकर लाई उद्योग	सिहपुर, बाँदा	1989
43. शिवहरे आयल उद्योग	मर्दन नाका, बाँदा	1962
44. त्रिपाठी आयल उद्योग	बाँदा	1977
45. चौहान आयल मिल	खूटी चौराहा, बाँदा	1989
46. महेश मसाला उद्योग	अतर्रा, बाँदा	1987
47. खान आयल मिल	कुरही, बाँदा	1989
48. अवस्थी आयल मिल	गिरवाँ, बाँदा	1985
49. श्रीवास्तव आयल उद्योग	पैलानी बाँदा	1989
50. राम आधार तेल उद्योग	जसपुरा, बाँदा	1982

उपरोक्त मिलों के सर्वेक्षण करने पर महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त हुई जिसको सारणी संख्या

1.2 में दर्शाया जा रहा है।

सारिणी संख्या-1.2

बाँदा नगर में संचालित कृषि-आधारित उद्योग
के अन्तर्गत कार्यरत मिलों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ
करने में व्यय की गई पूंजी का परिणाम

क्रम सं०	व्यय पूंजी (रु० में)	मिलों की संख्या
1	2	3
1.	10,000-10,0000	34 (68.00प्रतिशत)
2.	10,0000-20,0000	10 (20.00 प्रतिशत)
3.	20,000-30,0000	02 (4.00प्रतिशत)
4.	30,0000-40,000	03 (6.00प्रतिशत)
5.	40,000-50,000	01 (2.00प्रतिशत)
	समग्र योग	50 (100 प्रतिशत)

स्रोत-साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी-लघुकोष्णक में प्रदर्शित संख्या सम्बंधित कालम संख्या का प्रतिशतांश है।

अतः अपर्युक्त सारिणी संख्या 1.2 में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सर्वाधिक (68.00प्रतिशत) मिलों में 10,000 -10,000 रु० की पूंजी उत्पादन प्रारम्भ करने में व्यय की गई।

9.3 शोध समस्या की कतिपय संकल्पनाएँ :-

संकल्पना एक कल्पना है, मान्यताओं का एक संग्रह या समूह है, वह अर्थ कथन है, जिसे अभी सम्पूर्ण होना है, संकल्पना तथ्यों का वह कच्चा घड़ा है, जिसका पकना निःशेष है। यह संकल्पना बोध बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तथ्यों एवं अनुभवों से परे प्रक्षेपण करने वाले वास्तविक एवं अवधारणात्मक तथ्यों तथा उनके पारस्परिक सम्बंधों के विषय में

स्थायी कथन सही नहीं है जिसकी मान्यताओं की या निष्कर्षों की जांच न कर ली जायें, उक्त संकल्पनायें अर्ध सत्य रहती हैं और अन्तिम विश्लेषण में तथ्यों के सापेक्ष व्यावहारिक सत्यता के आधार पर व्युत्पन्न संकल्पनायें या तो स्वीकृत होती हैं या तिरस्कृत होती हैं। स्थूल रूप से वैज्ञानिक अध्ययन में दो प्रकार की संकल्पनायें प्रयुक्त होती हैं-यथा

1:- तात्त्विक संकल्पना

2:- सांख्यिकीय संकल्पना

१-तात्त्विक संकल्पना-

तात्त्विक संकल्पना के अन्तर्गत दो या दो से अधिक चरों के बीच अनुमान पर आधारित सम्बंधों को व्यक्त किया जाता है। एक तात्त्विक संकल्पना परीक्षण योग्य नहीं होती है। पहले इसे परिचालनात्मक एवं प्रयोगात्मक शब्दों में अनुदिन करना पड़ता है। तात्त्विक संकल्पनाओं के परीक्षण का एक लाभपूर्ण द्वारा सांख्यिकीय संकल्पनाओं द्वारा किया जाता है।

२-सांख्यिकीय संकल्पना-

सांख्यिकीय संकल्पना को निम्न भौतिक कथात्मक रूप दिया जा सकता है। यथा:

“एक ऐसी परिकल्पना जिसका प्रतिपादन आशान्वित परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिये उस समय किया जाता है जबकि आदर्श प्ररचना के अपनार्ये जाने पर सांख्यिकीय ढंगो को सभी प्राप्त संमक पर लागू किया जा सकता है सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाती है।”¹

एक सांख्यिकीय संकल्पना के अनेक विकल्प हो सकते हैं किन्तु प्रायः विकल्प के रूप में चुनी गयी संकल्पना जिसका प्रतिपादन रोयनाल्ड पिशर द्वारा किया गया हैं।

1. आर०ए०पिशर : दि डिजाइन आफ एक्सपेरिमेन्ट्स, है फनर, न्यूयार्क 951 पृष्ठ 16; सन्दर्भित सामाजिक अनुसंधान, सुरेन्द्र सिंह, पृ०-156

पिशर के अनुसार:-“शून्य परिकल्पना को अप्रमाणित सिद्ध करने के लिये ही प्रत्येक प्रयोग को वर्तमान का कछुआ कहा जा सकता है।”

शून्य संकल्पना या नकारात्मक संकल्पना संयोग की आशा की पूष्ठभूमि में प्राप्ति के लिये आकड़ों के परीक्षण को व्यक्त करने का एक दृश्य ढंग है । शून्य संकल्पना संयोग पर आधारित आशा है। इसे हम शून्य संकल्पना के नाम से इसलिये पुकारते हैं क्योंकि परीक्षण कार्य रीतिकी सहायता से हम इसे ही गलत अथवा सही सिद्ध करना चाहते हैं।

उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि किसी सफल अनुसंधान के लिये संकल्पनाये एक अनिवार्य शर्त है। प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित निम्नांकित शून्य संकल्पनाये हैं। यथा-

1. बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि-आधारित उद्योगों की विशिष्ट भूमिका है।
2. कृषि-आधारित उद्योगों की लाभदायकता के लिये विवेकपूर्ण नियोजन आवश्यक है।
3. कृषि-आधारित उद्योगों के लिये यातायात के लिस आवश्यक साधन नहीं है।
4. कृषि-आधारित उद्योगों की स्वरूप व संरचना में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं।
5. कृषि-आधारित औद्योगिकरण की मूल संकल्पना कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था से सम्बद्ध है।
6. इसका मूल उद्देश्य ग्राम्य आर्थिक संरचना को उर्ध्वमुखी रूप में रूपान्तरित करना है। वस्तुतः यह बड़े पैमाने के गहन पूंजी विनियोजन वाले वृहत औद्योगिकरण का एक विकल्प भी है।
7. कृषि-उत्पादन विधायन आधारित औद्योगिक कृषि क्षेत्र को उद्योग का मानक प्रदान करता है।
8. यह लघु पैमाने वांछित तकनीक, तुलनात्मक लागत अंतर क्षेत्रीय लाभकारिता क्षेत्रीय संसाधन और क्षेत्रीय विपणन व्यवस्था को आधार मानकर निर्गत उत्पन्न

करने का वह ढांचा है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को आय प्रदान करता है

- 9 इससे 70 प्रतिशत जनसंख्या के रोजगार का सृजन होता है।
- 10 कृषि-आधारित उद्योग की प्रवृत्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था-अधोमुखी है।
- 11 यदि कृषि-आधारित उद्योगों की लाभदायकता के लिये आदेश समस्या का स्थायी हल ढूँढ लिया जाये तो यह उद्योग बड़ी मात्रा में पूंजी पैदा कर सकते हैं।
- 12 इस उद्योग के लिय कच्चा माल एवं मशीनें अन्य नगरों से प्राप्त नहीं हो पाती है।
- 13 इन उद्योगों के विकास में मुख्य समस्या वित्त की है।

हम कह सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योगों को ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गई है जो स्थानीय रूप से आधारित हो ग्राम उन्मुखी हो तथा वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर संगठित हो।

इस प्रकार उपयुक्त निर्मित संकल्पनाओं द्वारा शोधार्थी शोध अध्ययन के निष्कर्षों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

9.8 शोध की प्रवर्तमान प्रासंगिकता सीमाएँ एवं अवधारणायें :-

अपने आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन तथा निम्नस्तर के कारण बाँदा जनपद लगभग प्रत्येक क्षेत्र में शोध के बहुमुखी आयाम प्रस्तुत करता है। ज्ञातव्य है कि बाँदा जनपद की विकास के अवरोधों को समझने एवं समस्याओं का हल खोजने के दृष्टिकोण से विभिन्न पक्षों जैसे ग्राम्य एवं नगर नियोजन कृषि एवं सिंचाई साधनों कृषि उत्पादों की क्रय विक्रय की समस्याओं लघु उद्योगों तथा बैंकिंग से सम्बंधित विषयों पर औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अध्ययन हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। किन्तु जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों की बढ़ती हुई लोकप्रिय एवं आवश्यकता के बावजूद भी इस उद्योगों पर विचार नहीं किया गया। अतः

यह उद्योग अनेक समस्याओं से घिरा होने के कारण जनपद में स्थैतिक रूप में उत्पादन एवं विक्रय का परम्परागत निष्पादन कर रहा है। आज यह अन्वेषण एवं तर्क वितर्क का विषय होना चाहिये कि जनपद में किस प्रकार कृषि-आधारित उद्योगों का विकास करके किस सीमा तक आय एवं रोजगार गरीबी भुखमरी एवं कुपोषण की दूर किया जा सकता है।

अतः चयनित शोध समस्या निम्न प्रकार से प्रसंगिक योगदानात्मक रचनात्मक एवं कल्याणकारी अर्थशास्त्र से सम्बंधित है-

1. इस विषय का अध्ययन ही यह है कि जनपदीय अर्थव्यवस्था को सृष्टि बनाने में कृषि आधारित उद्योग महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकते हैं। इस तथ्य को अभी तक शोध का विषय बनाया गया है। अतः प्रस्तुत शोध जनपद के आर्थिक विकास में कृषि उत्पाद आधारित औद्योगिकरण का अध्ययन जोकि प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता को सुस्पष्ट कर देता है।
2. प्रस्तुत शोध समस्या वर्तमान ही नहीं वरन भविष्यगत प्रसंगिक समस्या है। क्योंकि इससे निश्चित ही भविष्य में योगदान की सम्भावनायें हैं।
3. प्रस्तुत शोध समस्या इस अर्थ में और भी अधिक प्रासंगिक है कि कृषि उत्पादन आधारित उद्योगों का अध्ययन स्वरोजगार तथा निम्न वर्ग एवं निम्न आय वर्ग से अधिक सम्बंधित है।
4. प्रस्तुत शोध प्रबंध इस अर्थ में और भी अधिक महत्व हो जाता है कि किस तरह कृषि उद्योग रोजगार पक्ष से सम्बंधित है एवं सामाजिक उपयोगिता के रूप में यह किस प्रकार कल्याणगत अर्थशास्त्र से सम्बंधित है। निः सन्देह इन विभिन्न समस्याओं के स्पष्टीकरण हेतु शोध समस्या का अध्ययन प्रासंगिक है।

निष्कर्ष अपनी परम्परागत स्थिति , समस्याओं, सम्भावनाओं एवं नगर नियोजन कार्यक्रम के दृष्टिकोण से यह अध्ययन प्रासंगिक है।

अध्ययनगत परिसीमाएँ:-

प्रस्तुत शोध प्रबंध का अध्ययन वैसे न तो किसी मान्य अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पर आधारित है और न ही इस शोध प्रबंध के माध्यम में बाँदा नगर के कृषि आधारित उद्योग से सम्बंधित किन्ही विशिष्ट संकल्पनाओं को कोई विशेष रूप से सत्यापन किया जा रहा है। इसलिये आवश्यक हो जाता है कि इस शोध प्रबन्ध की परिसीमाएँ बतला दी जायें। वे निम्नलिखित हैं-

1. यह शोध प्रत्यन वस्तुतः बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि आधारित औद्योगिकरण की समस्याओं का ही अध्ययन करेगा, सम्पूर्ण शोध किसी सैद्धान्तिक निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु नहीं किया जा रहा है।
2. यह शोध प्रत्यन किसी शोध किसी सैद्धान्तिक निष्कर्ष की प्राप्ति हेतु नहीं किया जा रहा है
3. यह शोध प्रत्यन संकलित समंक की विश्वनीयता के अंश एवं सांख्यिकीय विश्लेषण की तकनीकी को परिसीमाओं से प्रभावित होगा।
4. यह शोध प्रत्यन सातवीं योजना से अद्यतन समय तक समय बद्ध होगा।
5. यह शोध प्रबंध जनपद के सभी उद्योगों पर केन्द्रित नहीं होगा वरन कृषि उत्पादन आधारित औद्योगिकरण पर आधारित होगा।
6. साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा एकत्रित समंक उस सीमा तक नहीं सत्य है जिस सीमा तक उत्तरदाताओं ने सत्य उत्तर दिये हैं अतः निष्कर्षों की जांच इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही जाननी चाहिये।
7. प्रस्तुत शोध में बाँदा नगर में संचालित अन्य उद्योगों से कृषि-आधारित उद्योग का कोई सांख्यिकीय अन्तर्सम्बंध स्थापित नहीं किया गया है।
8. प्रतिशत एवं माध्य के दोष इस अध्ययन की सांख्यिकीय परिसीमा को शापित

करेंगे।

9. सौख्यिकीय निर्वचन हेतु प्रयुक्त सारिणी एवं उन पर आधारित चित्रमय प्रदर्शन भी इन विधियों की साख्यिकीय अवकलनों के दोषों से शासित होंगे।
10. प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक संमक प्रयुक्त किये जायेंगे। इस संदर्भ में द्वितीयक संमको पर उस सीमा तक ही विश्वास किया जा सकता है। जिस सीमा तक उनके प्राप्ति स्रोत विश्वासप्रद हैं।
11. यह शोध प्रयत्न एक निश्चित समय अवधि सातवीं योजना समय तक समयबद्ध रहेगा।
12. यह शोध प्रबंध 'सैम्पलिंग' पर आधारित होगा अतः " केस टू केस स्टडी" करके चयनित शाखाओं के आधार पर ही अध्ययन एवं निष्कर्ष ज्ञापित करेगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर एक चीज की परिसीमायें होती हैं उसी को ध्यान में रखते हुये ही अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इस विषय की परिसीमाओं में ध्यान में रखते हुये ध्यान किया जायेगा।

अवधारणायें:-

किसी भी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिये उसकी अवधारणाओं की गहर जानकारी आवश्यक है अन्यथा शोधकर्ता के गलत निष्कर्षों पर पहुँचने की सम्भावना रहती है। अवधारणाओं द्वारा ही संकल्पनाओं का परीक्षण एवं सिद्धान्तों का निर्माण होता है।

किसी शोधकर्ता द्वारा शोध अध्ययन के लिये प्रयुक्त प्राकृतिक और जरूरी तथ्य ही उस अध्ययन की अवधारणायें हैं। अतः निरीक्षण वस्तुओं और घटनाओं की जानकारी ही अवधारणा है।

पी०वी०यंग:- “ सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में अन्य तथ्यों से अलग किये गये नये वर्ग को एक अवधारणा का नाम दिया जाता है।”¹

अतः सपष्ट है कि शोध समस्या सूचीबद्ध तथा सुलझाने के लिये अवधारणाएँ आवश्यक होती हैं। इसलिये प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणाओं का वर्णन करना प्रासंगिक होगा

जो निम्नवत् हैं।

1. कृषि पर आधारित उद्योग :-

ये वे उद्योग होते हैं जो विशेष रूप से कृषि पदार्थों पर आधारित होते हैं।

2. कृषि-

कृषि उसे कहते हैं जो भूमि पर कृषक द्वारा अनाज (दाल, चावल, तिलहन, गेहूँ, बाजरा, मूँग आदि)

3. कच्चा माल-

इन उद्योगों के लिये कच्चा माल मूल रूप से कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे- तिलहन, चावल, कपास, सनई, दाल आदि।

4. वित्तीय सहायता-

इन उद्योगों को सरकार पूंजी पतियों बैंको व्यावसायिक संगठनों आदि से ब्याज सहित या ब्याज रहित प्रदत्त वित्त को वित्तीय सहायता कहा जा सकता है।

5. ऋण साख-

इन उद्योगों की जो ग्रामीण व व्यावसायिक बैंकों द्वारा उधार पूंजी ब्याज सहित दी जाती है उसे ऋण कहते हैं।

6. रोजगार सृजन-

किसी क्षेत्र में किसी उत्पाद के वितरण के प्रारम्भ होने से रोजगार प्राप्ति के साधन में होने वाली वृद्धि रोजगार सृजन कहते हैं।

7. लागत-

इन उद्योगों में लागत बहुत कम आती है।

8. साधन-

कृषि आधारित उद्योगों में फर्मों को प्राप्त होने वाले उत्पादन हेतु आवश्यक वस्तुओं जैसे-कृषि सामग्री, वित्तीय सहायता आदि, को साधन कहते हैं।

9. लाभ-

इस उद्योगों में मालिकों को बहुत लाभ प्राप्त होता है।

10. जीवन स्तर-

दी हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत सामान्य जीवनयापन हेतु आर्थिक ढाँचे को जीवन स्तर कहेंगे।

11. प्रबंधकीय कौशल-

प्रबंधकीय कौशल वह है जो उत्पादन को उचित रूप से संगठित करता है।

12. उत्पादन फलन-

एक उत्पादन फलन, एक दिये हुये समय के लिये उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक सम्बंध को बताता है।

13. उत्पादन निष्पादन-

उत्पादन का अर्थ है- मूल्यों का सृजन करता और आर्थिक उपयोगिता की वृद्धि करना।

निष्पादन का अर्थ है लगातार उत्पादन का होना है।

14. शोध अभिकल्प-

शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घटित करने के लिये पहले से बनाई गई योजना की रूपरेखा को शोध अभिकल्प कहते हैं।

15. आगम-

किसी भी उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से जिस आय की प्राप्ति होती है उसे आगम कहते हैं।

16. उत्पादन का पैमाना-

उत्पादन के पैमाने से तात्पर्य उत्पादन करने वाली ईकाई के आकार से तथा उत्पादन किस में किया जाता है इस दृष्टि से उत्पादन दो प्रकार का होता है 1-छोटे पैमाने पर 2-बड़े पैमाने पर।

निष्कर्षतः प्रस्तुत शोध-प्रबंध की एक निश्चित शोध प्रविधि है जिसके आधार बौद्ध जनपद के कृषि आधारित उद्योगों के बारे में ज्ञान संचयन के प्रयास किये गये हैं।

9. 4- अध्यायगत-प्रारूप-

प्रस्तुत शोध अध्ययन की अध्ययन परियोजना निम्नवत् रखी जा सकती है-

प्रथम अनुक्रम-

प्रथम अनुक्रम के अन्तर्गत पूर्व पीठिका में भारतीय अर्थव्यवस्था व कृषि आधारित उद्योगों के साथ-साथ जनपद की भौगोलिक सामाजिक आर्थिक संरचना के विशिष्ट पहलू की प्रस्तावना पर प्रकाश डालते हुये शोध समस्यागत साहित्य सिंहावलोकन दिया जायेगा। तत्पश्चात् शोध समस्या का स्वरूप एवं शोध अभिकल्प शोध समस्या की कतिपय संकल्पनाएँ शोध की प्रवर्तमान प्रासंगिकता सीमाये एवे अवधारणायें का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जायेगा।

द्वितीय अनुक्रम-

इस अनुक्रम में कृषि एवं उद्योग का आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योगदान तथा कृषि

एवं उद्योग में अर्न्तसम्बंध , अर्न्तसम्बंधगत, सैद्धान्तिक परिकल्पनायें, बाँदा जनपद में कृषि आधारित औद्योगिकरण हेतु अवस्थापनायें स्पष्ट करना।

तृतीय अनुक्रम-

इस अनुक्रम का सम्बंध कृषि का विकास खण्डवार स्थानीयकरण, उत्पादन के प्रकार व गुण, उत्पादन विधायन की प्रस्थिति, कृषि-आधारित उद्योगों का निष्पादन विशिष्ट प्रवृत्तियां होगा।

चतुर्थ अनुक्रम-

इस अनुक्रम का सम्बंध कृषि पर-आधारित उद्योगों का प्रबंधन एवं वित्तीय पक्ष से है।

पंचम अनुक्रम-

इस अनुक्रम का सम्बंध कृषि-आधारित उद्योगों का रोजगार सृजन एवं आप संवृद्धि पक्ष से है।

षष्ठम अनुक्रम-

इस अनुक्रम का सम्बंध कृषि-आधारित उद्योगों का लागत पक्ष व कृषि आधारित उद्योगों का मूल्य निर्धारण पक्ष, कृषि-आधारित उद्योगों के विक्रय पक्ष कृषि-आधारित उद्योगों का आगम पक्ष, कृषि-आधारित उद्योगों के प्रतिफल पक्ष से हैं।

सप्तम अनुक्रम-

इस अनुक्रम का सम्बंध वित्त पोषण पक्ष, प्रशासनिक पक्ष, कच्चा माल एवं श्रम आपूर्ति पक्ष, शक्ति के साधन, प्रबंधकीय समस्याएँ से सम्बंधित है।

अष्टम अनुक्रम-

इस अनुक्रम का सम्बंध निष्पादन एवं समस्यायें का मूल्यांकन अध्ययनगत निष्कर्ष बिन्दु, कतिपय संभावित कृषि-आधारित उद्योगों के नियोजन हेतु सुझाव प्रवर्तमान स्थिति हेतु सुझाव से सम्बंधित है।



द्वितीय अनुक्रम

कृषि एवं उद्योग का आर्थिक अन्तर्निर्भरता : सैद्धान्तिक पक्ष

2.1 कृषि एवं उद्योग का आर्थिक विकास की प्रक्रिया में योगदान

2.2 कृषि एवं उद्योग में अन्तर्सम्बन्ध

2.3 अन्तर्सम्बन्धगत सैद्धान्तिक परिकल्पनायें

2.4 बाँदा जनपद की विकास प्रक्रिया एवं कृषि उद्योग अन्तर्सम्बन्ध

2.5 बाँदा जनपद में कृषि-आधारित औद्योगिकरण हेतु अवस्थापनायें

द्वितीय अनुक्रम

कृषि एवं उद्योग का आर्थिक विकास प्रक्रिया में योगदान-

भारत में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अंग है। परन्तु भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है कृषि ही देश की अधिकांश जनसंख्या के लिये आजीविका का साधन है। इसी प्रकार उद्योग भी देश के आधार भूत स्तम्भ है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है। आज जो देश औद्योगिकरण में जितना आगे है वह देश उतना ही अधिक उन्नतशील माना जाता है जैसा कि शाही औद्योगिक ने कहा भी है कि “उद्योग सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये अत्यन्त लाभदायक होगा क्योंकि यह पूंजी के नये साधनों को उत्पन्न करेगा पूंजी की बचत को बढ़ावा होगा देगा, सरकार की आय में वृद्धि करेगा श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकेगा और राष्ट्रीय जीवन के लिये प्रेरणा प्रदान करेगा।”¹

इस प्रकार हमें दोनों के महत्व को स्पष्ट करने के लिये पहले दोनों के अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है।

उद्योग का अर्थ:-

उद्योग वह प्रक्रिया है जिस पर देश की व्यापक प्रक्रिया का विचार निहित है। और इसके द्वारा किसी भी देश का सम्पूर्ण आर्थिक की परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि पी कांग चांग ने कहा भी है कि औद्योगिकरण प्रक्रिया है जिसमें आधार भूत उत्पादन कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं। ये आधार भूत परिवर्तन जिनका सम्बंध किसी औद्योगिक उपक्रम के यन्त्रीकरण नवीन उद्योगों के निर्माण नये बाजार की स्थापना से है।

कृषि का अर्थ:-

पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिये मनुष्य द्वारा प्रारम्भिक उद्देश्य

1. पाटनी आर0एल0 - Industrial Economics P. No.5
2. पाटनी आर0एल0 - Industrial Economics P. No.8

भोजन, कपड़ा, ईंधन, आदि की पूर्ति के लिये जो क्रियायें की जाती हैं उन्हें कृषि कहते हैं। जैसे फसलों उत्पादन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, एवं रेशम कीट पालन आदि।

An activity of man primarily aimed at the production of food, fibre & fuel etc. by optimum use of terrestrial resources is called Agriculture."¹

इस प्रकार दोनों के अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि देश के आर्थिक विकास करने के लिये उद्योग व कृषि दोनों जरूरी हैं। कृषि हमारे देश का आधार भूत स्तम्भ है अतः इसी पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था रुपी भवन खड़ा है। इसके महत्व को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं।-

1. राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान-1950-51 में 59 प्रतिशत था जो 1997-98 में 71 प्रतिशत हो गया है।
2. रोजगार में कृषि का महत्व -देश की 70.6 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से अपनी जीविका चला रही है।
3. विदेशों से आय अर्जित करने में-अधिकतर निर्यात कृषि उत्पाद का ही किया जाता है। अर्थात् 40 प्रतिशत निर्यात कृषि पर आधारित वस्तुओं का किया जाता है।
4. उद्योग का आधार भी कृषि को ही माना जाता है क्योंकि उद्योग के लिये 75 प्रतिशत कच्चा माल कृषि से ही मिलता है।

आज हमारे देश में जो महत्व कृषि है वही महत्व उद्योगों का भी है। आज देश की उन्नति उद्योग पर आधारित है आज जो देश जितना औद्योगिकरण में आगे है वही देश अधिक उन्नति शील माना जाता है। आज देश का आधे से अधिक निर्यात उद्योगों द्वारा उत्पादित समानों का ही होता है। चाहे वे चीनी उद्योग व सूती उद्योग हों। अतः स्पष्ट होता है कि कृषि का महत्व आर्थिक नहीं है फिर भी अधिकांश उद्योग धन्ये जो विदेशों से आय

अर्जित कर रहे हैं उनके लिये कच्चा माल कृषि ही प्राप्त होता है। उद्योग के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं-

1:- विदेशों से आय अर्जित करने में उद्योग का सर्वप्रथम स्थान है। आज सूती उद्योगों की देश में 216 मिलें हैं जिससे 11.18 लाख टन उत्पादन होता है और 1998में 0.59 मि० टन चीनी का निर्यात किया गया है। तथा जूट उद्योग से 1998में 379.51 करोड़ रु० की आय अर्जित हुयी है। रेशम उद्योग के निर्यात को तालिका द्वारा स्पष्ट करते हैं।

सारिणी संख्या-2.1

क्रम सं०	वर्ष	निर्यात(रु०में)
1	2	3
1-	1987-88	264.96
2-	1990-91	440-00
3-	1992-93	900.00
4.	1997-98	1020.00
5.	1998-99	1413.00

स्त्रोत:- प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था

- राष्ट्रीय आय में उद्योग का योगदान भी कम नहीं है। 1996-97 में उद्योग का योगदान 6.1 प्रतिशत था।
- उद्योग देश में बेरोजगारी दूर करने में भी सहायक होते हैं आज देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या उद्योग से ही अपना जीवनयापन कर रही है।
- पूंजी निर्माण में वृद्धि भी उद्योग ही सम्भव होती है।

अतः स्पष्ट होता है कि कृषि व उद्योगों का देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपना अलग-अलग महत्व है इन्हीं दोनों के सहारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है यही देश की

अर्थव्यवस्था को चलाने के दो पहिये हैं। आज कृषि का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उद्योग का क्योंकि आजका युग औद्योगिकरण का युग है। औद्योगिकरण की उन्नति के द्वारा ही देश की उन्नति आंकी जाती हैं। परन्तु इन उद्योग का आधार स्तम्भ कृषि ही है क्योंकि इनको कच्चा माल कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर कृषि की उन्नति तो उद्योग धन्धे नहीं पनप सकते हैं। जैसा सुकरात ने कहा है कि “जब खेती फलती फूलती है, तब सब धन्धे पनपते हैं, किन्तु जब भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता है तब अन्य सभी धन्धे नष्ट हो जाते हैं।”¹

2.2:- कृषि एवं उद्योग में अन्तर्सम्बन्ध-

किसी भी देश अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और उद्योग धन्धे जिस देश में पनपते रहते हैं वही देश उन्नति के पथ पर अग्रसर जैसे-अमेरिका, जापान, जर्मनी, आदि देश।

अतः स्पष्ट है कृषि और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के लिये परस्पर सहायक होते हैं। औद्योगिकरण की सफलता कृषि पर अवलम्बित है और कृषि का विकास औद्योगिकरण पर औद्योगिकरण की सफलता पर्याप्त सीमा तक कृषि पर निर्भर होती है। कृषि में सुधार एवं विकास किये बिना औद्योगिकरण के सम्भव नहीं है क्योंकि कृषि में जब तक नयी-नयी तकनीकी बीजों मशीनों का प्रयोग नहीं होता है जब तक कृषि का विकास सम्भव नहीं है। उद्योग धन्धों का प्रमुख भोजन कच्चा माला होता है कच्चा माल हमको उन्नत कृषि से ही उपलब्ध होता है। इसीलिये सुकरात ने कहा “जब खेती फलती-फूलती है तब सब धन्धे पनपते हैं किन्तु जब भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता है तब अन्य सभी धन्धे नष्ट हो जाते हैं।”

वास्तव में कृषि ही देश के आर्थिक ढाँचे की ऐढ़ की हड्डी है। अर्थात् स्पष्ट है कि

कृषि व उद्योग एक सिक्के के दो पहलू हैं एक के बिना अर्थव्यवस्था को गाड़ी चल नहीं सकती है।

अतः यह भी स्पष्ट कर देना उचित है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर हैं-

कृषि निर्भर करती है उद्योगों पर-

कृषि पूर्णतः उद्योग धन्धों पर ही आधारित है कृषि का विकास पूर्णतः उद्योग धन्धों पर ही आधारित है । क्योंकि तकनीकी प्रगति उद्योग धन्धों के द्वारा ही होती है उद्योग द्वारा ही नये-नये कृषि सम्बंधों यन्त्र तैयार किये जाते हैं तथा नये प्रकार उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण भी उद्योग द्वारा किया जाता है अच्छे किस्म की खादें भी उद्योग द्वारा ही कृषि को प्राप्त होती हैं। सिचाई के लिये नये साधनों प्रदान करनेमें जो मशीनों का प्रयोग की जाती है वो भी उद्योगों के द्वारा ही तैयार की जाती है। उद्योगों के द्वारा कृषि को प्राप्त सहायता इस प्रकार है जिसको सारिणी द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

सारिणी संख्या:-2.2(अ)

**जनपदों में कृषि विकास में सहायक यन्त्रीकरण
खाद व बीजों की स्थिति (जो उद्योगों द्वारा प्राप्त हैं)**

1998-99 में

क्र.सं.	यन्त्रीकरण	खाद	बीज	कीटनाशक दवायें
1	2	3	4	5
1	24620	11779	4858	1630

स्रोत:- सांख्यिकीय पत्रिका - 1998-99

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद उन्नत बीज, यन्त्रीकरण, खाद, बीज कीटनाशक दवाइयों की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ये सब सुविधायें उद्योग धन्धों के

कारण ही उपलब्ध है।

उद्योग पूर्णता निर्भर है कृषि पर-

“उद्योग पूर्णतः कृषि पर आधारित है। क्योंकि आज उद्योगों को 213 कच्चा माल कृषि से ही मिलता है”। अतः विभिन्न उद्योग धन्ये कृषि के कारण ही पनप रहे हैं विभिन्न उद्योग प्रधान देशों के आर्थिक विकास के ऐतिहासिक अवलोकन से ज्ञात होता है कि कृषि के सुधार के द्वारा ही वहाँ के उद्योगों का विकास एवं उन्नति सम्भव हो सकी है। कृषि क्षेत्र औद्योगिकरण को अनेक प्रकार से सहायता देता है जो कि निम्नलिखित हैं-

1. कृषि के द्वारा ही उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है।
2. कृषि विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एकसाधन है कृषि उत्पादन का निर्यात करके विदेशों से औद्योगिकरण के लिये आवश्यक पूंजीगत वस्तुयें मंगाई जा सकती है।
3. वह उद्योगों के लिये निजी बचतों से पूंजी उपलब्ध करता है।
4. वह विनिमय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है और इससे आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था का संचालन सम्भव होता है।

इसी सम्बंध में पी0टी0 बौर तथा बी0एस0 यामें ने कहा भी है-

“आज के अग्रणी औद्योगिक देश भी किसी समय कृषि प्रधान देश थे आर्थिक इतिहासकारों ने इन उपायों का पता लगाया है जिनका अवलम्बन करते हुये समृद्ध एवं विकासशील कृषि ने समवर्ती या उत्तरवर्ती औद्योगिकरण के लिये आधार प्रस्तुत किया”

अतः स्पष्ट होता है पूर्णतः उद्योग कृषि पर निर्भर है। एक सारिणी द्वारा स्पष्ट कर है कि जनपद में कितना कच्चा माल कृषि द्वारा उद्योगों को प्राप्त होता है-

सारिणी-2.2(ब)

जनपद में कृषि से उद्योगों को प्राप्त कच्चा माल
उत्पादन मीटरी टन

क्रमसं०	फसल	1995	1996	1999
1	2	3	4	5
1.	चावल	53554500	53,24,800	54,24,600
2.	गेहूँ	- -	- -	- -
3.	दालें	59.00	93573.00	1.61182.00
4.	कपास	28,24,00	67,59,900	8749.00
5.	जूट	- -	- -	- -
6.	सनई	53,800	437.00	54,38,900

स्रोत:-सांख्यिकीय पत्रिका-

उपरोक्त सारिणी 2.2(ब) स्पष्ट कि कृषि-आधारित उद्योगों को पूर्णतः कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है।

अतः कृषि और औद्योगिकरण में घनिष्ठ सम्बंध है। इसी घनिष्ठ सम्बंध के विषय में प्रो० स्टेले ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं-“कृषि की उत्पादकता में वृद्धि औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने का सबसे ठोस साधन है।”

2.3 अन्तर्सम्बंधगत सैद्धान्तिक परिकल्पनायें-

कृषि और उद्योग में घनिष्ठ सम्बंध है। पीछे अध्यायों से स्पष्ट है। अतः कृषि और उद्योग को सैद्धान्तिक रूप में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।

किसी भी उद्योग में जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र में उत्पाद या output कहते हैं तथा जिन साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उसे आदा व Input कहते

है। यहाँ कृषि को अदा input है और उद्योग को प्रदा output माना है क्योंकि कृषि से अदा प्राप्त होता है और उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जाता है इन दोनों के सम्बंधों को गणितीय रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि Input और output के बीच गणितीय सम्बंध है जैसा बीसप ने कहा “the production function is a mathematical relationship describing the way in which the quantity of a particular product depends upon the quantities of particular inputs used”¹

अतः किसी फार्म के उत्पाद तथा पड़त के सम्बंधों को उत्पादन प्रकार्य या फलन कहते हैं।

उत्पादन फलन में दो घटक होते हैं एक निर्धारक होता है और दूसरा निर्धारण साधन जा उत्पादन के कार्य में लगे रहते हैं निर्धारक तत्व होते हैं और उत्पादन की मात्रा उन पर निर्धारण तत्व होते हैं। जैसे-

$$X = F(n, k, a)$$

$$X = \text{उत्पादन (उद्योग)}$$

$$F = \text{फलनात्मक सम्बंध}$$

$$n = \text{श्रमिकों की संख्या}$$

$$k = \text{पूंजी}$$

$$a = \text{कृषि से प्राप्त साधन}$$

अतः Input, Output सम्बंध को सैद्धान्तिक रूप से इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं अतः अधिकतम कुशल तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतक करते हैं इस फलनात्मक सम्बंध को हम दो प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं

1. अल्पकालीन उत्पादन फलन

2. दीर्घकालीन उत्पादन फलन

1. यदि एक आदा को स्थिर रखा जाये और कुछ में परिवर्तन किया जाये तो अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इस स्थिति को उत्पत्ति हास नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं।

2. जब सभी परिवर्तनशील हो तो उस विवेचना दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इस स्थिति को पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं।

अतः कृषि उद्योगों फलनात्मक सम्बंध को निम्न सिद्धान्तों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

1:-उत्पत्ति हास नियम-

जब एक अदा को स्थिर रखा जाये और दूसरे को बढ़ा जाये या उनमें परिवर्तन किया जाये तो कुल उत्पादन बढ़ेगा तथा सीमान्त उत्पादन घटेगा।

2:- पैमाने का स्थिर प्रतिफल-

यदि साधनों को स्थिर नहीं रखा जाये बल्कि साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते रहे, तो कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है।

3:- प्रतिस्थापन्न का प्रतिफल-

यदि उत्पत्ति के साधनों की समान अनुपात में न बढ़ाकर भिन्न-भिन्न अनुपातों में बढ़ाया जाता है तो ऐसी दशा में जो कुल उत्पादन में वृद्धि होती है उसे प्रतिस्थापन प्रतिफल कहते हैं।

अतः स्पष्ट होता है कृषि और उद्योग के सम्बंध को सैद्धान्तिक रूप से इन सिद्धान्तों द्वारा स्पष्ट करते हैं। इन सिद्धान्तों के मध्यम से कृषि और उद्योग का फलनात्मक सम्बंध स्पष्ट हो जाता है।

2.8 बाँदा जनपद की विकास प्रक्रिया एवं कृषि उद्योग अन्तसम्बन्ध-

उ०प्र० के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँदा जनपद कृषि प्रधान क्षेत्र है। जनपद में 87 प्रतिशत व्यक्तियों की जीविका का आधार कृषि है। यहाँ की मुख्य फसलें-मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल, कपास, मटर, चना, तिलहन, जूट, सनई है। यहाँ की मुख्य फसलों की तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

सारिणी संख्या-2.4(अ)

फसलों का उत्पादन (मी०टन में)


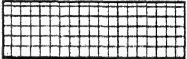

क्रम सं०	फसल	93-94	94-95	95-96	98-99
1.	चावल	53,54,4500	73,12,200	53,24,800	54,24,600
2.	गेहूँ	--	--	--	--
3.	जौ	13,28,700	81,28,100	78,15,00	77,14,00
4.	ज्वार	59,67,6900	71,40,00	88,900	89,50,00
5.	जूट	--	--	--	--
6.	कपास	28,24,00	67,59,900	88,49,00	87,49,00
7.	सनई	53,800	43700	53,38,900	54,38,900
8.	तम्बाकू	--	58.00	--	--

स्त्रोत:- सांख्यिकीय पत्रिका 1993-94 से 1998-99

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यहाँ कृषि उत्पादन की बाहुल्य है। कुल धान्य 1995-96 में 283451.00 कुल तिलहन 6256.00 मी०टन कुल दालें 16118.00 मी० टन है।

अतः इस जनपद की विकास प्रगति पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। इस जनपद में कृषि आधारित उद्योग अधिक संख्या में हैं वर्तमान में जनपद में उद्योग की संख्या 3288 हो गयी है।

जनपद की आर्थिक प्रगति में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों के मध्यम से ही जनपद की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है और अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त है जनपद की व्यावसायिक संरचना इस प्रकार है।

प्राथमिक क्षेत्र	
द्वितीय क्षेत्र	
तृतीय क्षेत्र	

कृषि-आधारित उद्योग हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। जनपद में उद्योगों की स्थिति को एक तालिका द्वारा दृष्टव्य कर सकते हैं।

सारिणी तालिका 2.4 (ब)

उद्योगों की स्थिति

क्रमसं० उद्योगों की संख्या	वर्ष			
	1993	1997	1998	1999
1. कृषि	404	1054	1065	1087
2. अकृषि	504	23651	24661	27651

स्रोत:-सांख्यिकीय पत्रिका 1993-1997-98

उपरोक्त तालिका स्पष्ट है कि जनपद के आधे से अधिक उद्योग कृषि पर आधारित हैं। और इस उद्योगों में जनपद के आधे से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों रोजगार में लगे व्यक्तियों की स्थितियों को इस प्रकार दृष्टव्य कर सकते हैं।

तालिका-रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	उद्योग	1993-94	1996-97	1998-99
1.	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	1067	1767	1784
2.	लघु उद्योगों ईकाइयों में	997	1767	1789
3.	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों ईकाइयों में	2224	3534	3664

स्रोत:- उद्योग निदेशालय पत्रिका

अतः उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में 3534 व्यक्तियों कृषि आधारित उद्योगों में कार्यरत है।

इस प्रकार जनपद की विकास का आधार स्तम्भ कृषि-आधारित उद्योग ही नजर आते हैं जिनके प्रति वर्ष उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है। जनपद में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि कृषि उद्योगों के कारण ही हो रही है जनपद के 55 प्रतिशत व्यक्ति कृषि आधारित उद्योगों में कार्यरत है। अतः पूर्णतः स्पष्ट होता है कि कृषि आधारित उद्योग ही जनपद की प्रगति के आधार स्तम्भ है।

२.५ -बाँदा जनपद में कृषि-आधारित औद्योगिकरण हेतु अवस्थापनायें-

प्रस्तुत अध्याय में बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों हेतु अवस्थापनाओं अथवा सुविधाओं पर प्रकाश डालेंगे किसी भी उद्योग के अध्ययन के लिये उस उद्योग से सम्बंधित आवश्यकताओं विशेषकर कच्चे माल एवं उस उद्योग से सम्बंधित यन्त्रों तथा प्रबंधकीय स्थिति के बारे में विस्तृत विवेचना पर विचार किया जायेगा।

कृषि-आधारित उद्योगों के लिये अवस्थापनायें -

बाँदा नगर में संचालित कृषि-आधारित उद्योग हेतु सभी उपयुक्त अवस्थापनायें विद्यमान हैं क्योंकि बाँदा जनपद कानपुर एवं इलाहाबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। इन

उद्योगों के लिये कच्चा माल जनपद के अन्दर से तथा आसपास के इन नगरों से मिल मालिक प्राप्त करते हैं। इस उद्योग हेतु श्रमिक जनपद ही में ही मिल जाते हैं। इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मशीने जनपद में उपलब्ध न होने से मिल मालिक दूसरे नगरों से क्रय कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ यातायात की कोई परेशानी नहीं होती है जनपद में इस उद्योग के लिये निम्न अवस्थापनायें या सुविधायें उपलब्ध हैं।

1-कच्चा माल-

बाँदा जनपद में खरीफ ,रबी, जनपद में तीनों फसलें अधिक मात्रा में होती हैं इसके तिलहन, जूट, कपास, सनई, आदि फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। इसलिये यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग अधिक मात्रा में लगाये जाते हैं। जनपद में प्रति वर्ष फसलों के उत्पादन की स्थिति इस प्रकार जो कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में प्रयोग की जाती है।

सारिणी संख्या 2.5(अ)

जनपद में फसलों की औसत उपज (कुन्टल प्रति हेक्टेयर)

क्र.सं०	फसलों का नाम	वर्ष		
		93-94	94-95	98-99
1.	चावल	9.01	10.60	7.25
2.	गेहूँ	14.44	14.77	14.99
3.	ज्वार	8.57	9.14	7.29
4.	जौ	17.18	8.89	12.44
5.	कुल दालें	59.42	6.72	7.41
6.	कुल तिलहन	44.02	4.63	39.80
7.	गन्ना	482.29	474.65	313.81
8.	सनई	4.89	4.03	4.42
9.	कपास	1.84	4.03	4.45
10.	जूट	- -	- -	- -

स्रोत:- सांख्यिकीय पत्रिका-1993-94-1995-96।

उपरोक्त सारिणी संख्या 2.5 से स्पष्ट है कि जनपद में दाल,चावल, तिलहन, जूट, कपास, सनई, का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है अतः कृषि-आधारित उद्योगों के कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है।

1. वित्तीय सहायता-

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग मकें उत्पादन कार्य मिल मालिकों द्वारा स्वयं निजी साधनों एवं सम्पत्ति पर किया जाता है वैसे इन उद्योग में से कुछ इकाईयों ने बैंकों तथा जिला उद्योग कार्यालय से ऋण लेकर उत्पादन कार्य कर रही है लेकिन अधिकांश

फर्म स्वयं की निजी पूंजी पर आधारित है। इसके अतिरिक्त निम्न स्रोतों से भी कृषि आधारित है। इसके अतिरिक्त निम्न स्रोतों से भी कृषि-आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

- 1:- व्यक्तिगत पूंजी
- 2:- मित्र एवं साहूकार
- 3:- महाजन एवं साहूकार
- 4:- राजकीय सहायता

1. व्यक्तिगत पूंजी-

कृषि-आधारित उद्योगों में अधिकतर ईकाईयों के मालिक अपने निजी साधनों से ही पूंजी लगाते हैं, इस उद्योग में अधिकांश पूंजी लगाते हैं, इस उद्योग में अधिकांश पूंजी मिल मालिकों को ही लगाना पड़ता है।

2. मित्र एवं सम्बन्धी-

कृषि-आधारित उद्योग के मालिक मित्र एवं सम्बंधियों से नाम मात्र को पूंजी प्राप्त करते हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि फर्म मालिकों के मित्र एवं सम्बंधी इतने अधिक धनी हो कि वह उनकी सहायता कर सकें फिर भी कुछ मिलों को मित्र या सम्बंधियों से भी वित्त प्राप्त हो जाता है।

3. महाजन एवं साहूकार-

कृषि-आधारित उद्योगों के मालिक अधिकतर अशिक्षित हैं या फिर अर्द्ध शिक्षित हैं, जिससे वे सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधाओं का पूर्ण रूपसे लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिये अधिकांश उत्पादक मिलों के स्वामी महाजनों एवं साहूकारों से वित्त प्राप्त करते हैं। इनकी ब्याज दर भी बहुत ऊँची होती है। किन्तु भी अधिकतर मिल मालिकों को इनसे वित्त प्राप्त करना पड़ता है।

4. राजकीय सहायता-

इस उद्योग की तरफ वैसे सरकार कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। किन्तु फिर भी कुछ मिल मालिक ने बैंकों से ऋण प्राप्त करके तथा जिला उद्योग केन्द्र के तरह ऋण प्राप्त करके ऋण प्राप्त करके वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

5. श्रम सुविधा-

कृषि आधारित हेतु उद्योग हेतु श्रम की पूर्ति जनपद में ही हो जाती है लेकिन अधिकांश श्रमिक अधिकांश अशिक्षित रहते हैं जिस कारण वह कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जनपद में श्रम की मात्रा को एक सारिणी द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

सारिणी संख्या 2.5(ब)

जनपद में श्रम की मात्रा

क्रमसं०	वर्ष	श्रमिकों की संख्या
1.	1994	28365
2.	1996	28365
3.	1997	30460
4.	1999	36540

स्त्रोत:- सांख्यिकीय पत्रिका 1994,1996,1999,

सारिणी संख्या 2.5 (ब) से स्पष्ट है कि जनपद में श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

4:- विपणन की सुविधायें-

जनपद में विपणन की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। यहाँ मिल मालिक उत्पादक माल को जनपद के अन्दर ही मण्डियों में बेचते हैं। अगर नहीं होता है तो आसपास के नगरों

की मण्डियों में बेचते हैं।

5. बाजारी सुविधायें-

इन उद्योगों के लिये बाजारी सुविधाये जनपद में ही उपलब्ध हो जाती हैं। नहीं तो मशीने आदि आसपास के नगरों से उपलब्ध हो जाती हैं।

6. परिवहन की सुविधा-

इन उद्योगों में उत्पादन माल को मण्डियों तक ले जाने के लिये पर्याप्त सुविधायें हैं। टैक्स्टर , ट्रक , बैलगाड़ी, बस, रेल इत्यादि।

उपरोक्त सभी साधनों के आसानी से उपलब्ध होने के साथ-साथ अन्य कई सुविधायें एवं इन उद्योगों के लिये उचित वातावरण तथा प्रबंधकीय दशायें भी बाँदा जनपद में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।



तृतीय अनुक्रम

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों की अवस्थिति एवं निष्पादन एवं निष्पादन पक्ष

3.1 कृषि-आधारित उद्योगों का विकास खण्डवार स्थानीयकरण

3.2 उत्पादन के प्रकार व गुण

3.3 उत्पादन विधायन की प्रस्थिति

3.4 कृषि-आधारित उद्योगों का निष्पादन

3.5 निष्पादनगत विशिष्ट प्रवृत्तियाँ

तृतीय अनुक्रम

कृषि-आधारित उद्योगों का विकास खण्डवार स्थानीकरण :

बाँदा जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाँदा जनपद में चार तहसीलें हैं-1. बाँदा 2. बबेरु 3. नरैनी 4. अतर्रा । और बाँदा जनपद में 8 विकासखण्ड हैं। 1. बड़ोखर खुर्द 2. तिन्दवारी 3. जसपुरा 4. बबेरु 5. कमासिन 6. बिसण्डा 7. महुआ 8. नरैनी।

बाँदा जनपद में कृषि उपज की अधिकता है, इसलिये जनपद के अन्दर कृषि आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। बाँदा जनपद में प्रत्येक विकास खण्डों में कृषि आधारित उद्योगों की संख्या अधिक है। प्रत्येक विकासखण्ड में कितने कृषि-आधारित उद्योग हैं इस स्थिति को सारिणी संख्या 3.1 द्वारा दर्शाया जा रहा है-

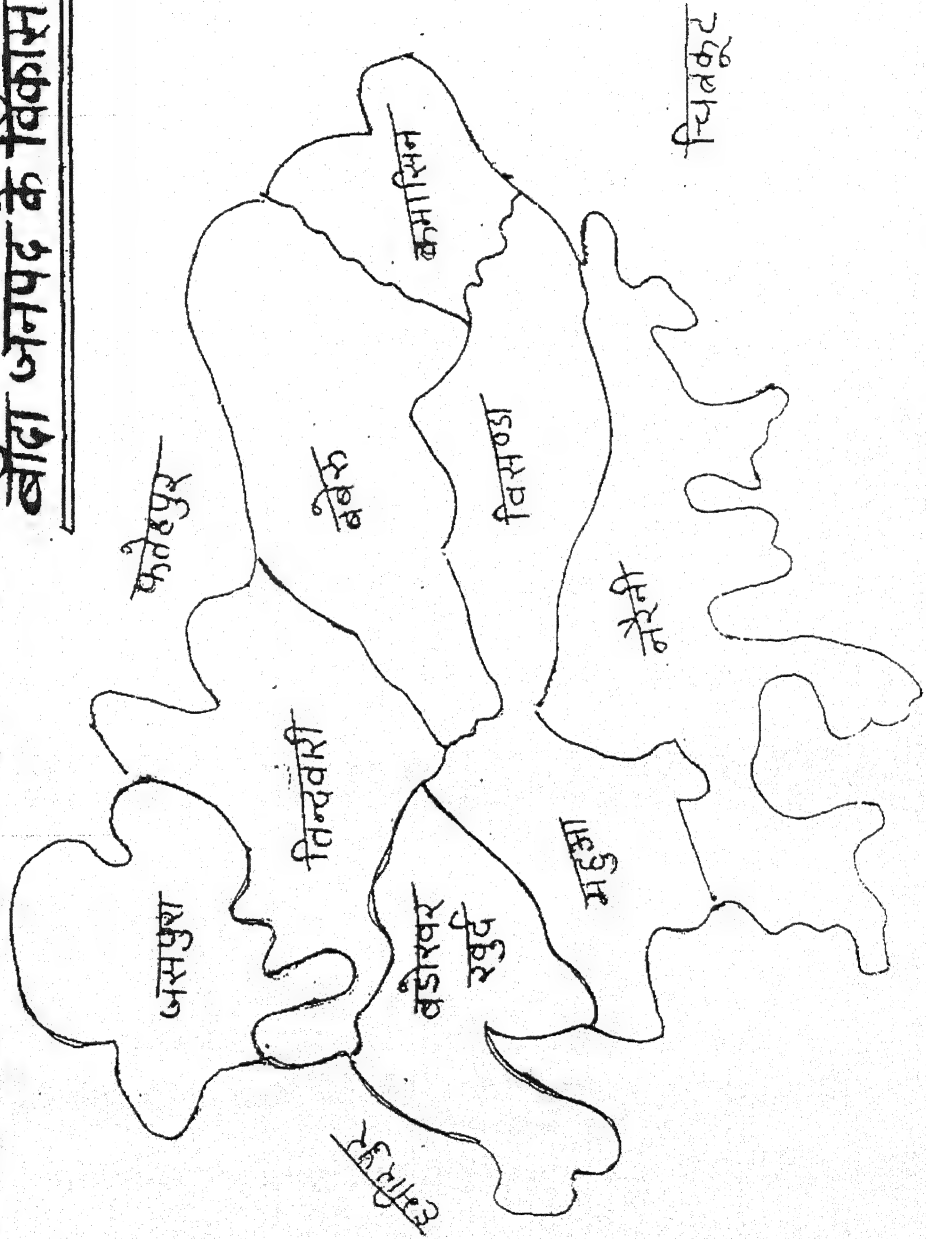
सारिणी संख्या 3.1

कृषि-आधारित उद्योगों का विकासखण्ड वार स्थानीकरण

क्रम संख्या	विकास खण्ड	मिलों की संख्या
1.	बड़ोखर खुर्द	3
2.	तिन्दवारी	2
3.	जसपुरा	8
4.	बबेरु	10
5.	कमासिन	3
6.	बिसण्डा	13
7.	महुआ	8
8.	नरैनी	10

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, बाँदा

बौदा जनपद के विकास खण्ड



महाराष्ट्र प्रदेश

उपरोक्त सारिणी संख्या 3.1 से स्पष्ट है कि बड़ोखर खुर्द विकास खण्ड में 3 मिलें, तिन्दवारी विकास खण्ड में 2 मिलें, जसपुरा विकास खण्ड में 8 मिलें, बबेरु में 10 मिलें, कमासिन विकासखण्ड में 3 मिलें, बिसण्डा विकास खण्ड में 13 मिलें, महुआ में 8 मिलें नरैनी विकास खण्ड में 10 मिलें स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त 11 मिलें अतर्रा में तथा 24 मिलें बाँदा में स्थित हैं।

अतः स्पष्ट है कि विकासखण्डों में अधिक मिलें इसलिए स्थित हैं क्योंकि यहाँ इन मिल मालिकों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है सबसे अधिक मिलें बिसण्डा विकासखण्ड में हैं, बिसण्डा विकासखण्ड अतर्रा तहसील के अन्तर्गत है।

3.2 उत्पादन के प्रकार व गुण -

उत्पादन का अर्थ-

सामान्त्य उत्पादन से अर्थ किसी पदार्थ या वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ यह नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य न तो किसी पदार्थ को बना सकता है। वह तो केवल प्रकृति द्वारा दत्त पदार्थों का रंग रूप व स्थान आदि बदलकर उनकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है। जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

फेयर चाइल्ड

“वस्तु या पदार्थ को अधिक उपयोगी बनाना ही उत्पादन है।”

अतः स्पष्ट है कि मनुष्य पदार्थों का सृजन नहीं कर सकता है, बल्कि अपनी बुद्धि मेहनत व योग्यता से उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार उपलब्ध पदार्थों में तुष्टिगुण का सृजन करना ही उत्पादन फहलाता है।

उत्पादन के प्रकार -

उत्पादन छः प्रकार का होता है-

- 1- रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन
- 2- स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन
- 3- समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन
- 4- अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन
- 5- ज्ञान में वृद्धि द्वारा परिवर्तन
- 6- सेवा द्वारा उत्पादन

1-रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन-

जब किसी पदार्थ के रूप में वजन रंग व सुगन्ध आदि में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। कि वह पदार्थ मनुष्य के लिये पहले से अधिक उपयोगी बन जाये तो इसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं।

2-स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन-

जब कोई व पदार्थ एक ऐसे स्थान से जहां वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है या जहाँ पर उसकी मांग कम है। वहाँ से किसी ऐसे स्थान पर ले जाये जहाँ वह अपेक्षाकृत दुर्लभ है। या जहाँ उसकी मांग अधिक है तो इस प्रकार की क्रिया को स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं।

3-समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन-

जब किसी वस्तु को कुछ समयके लिये सुरक्षित रख लिया जाता है। तो उस वस्तु के तुष्टिगुण में वृद्धि हो जाती है। इस सुरक्षित रखने की क्रिया को समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं।

4-अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन-

जब किसी वस्तु या पदार्थ के अधिकार के परिवर्तन से उसके तुष्टिगुण में वृद्धि हो जाती है। तो इसे अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं।

5-ज्ञान में वृद्धि द्वारा उत्पादन-

जब किसी वस्तु के तुष्टिगुण में वृद्धि उसके विषय में अधिक ज्ञान हो जाने से हो जाती है। तो इसे ज्ञान द्वारा उत्पादन कहते हैं।

6-सेवा द्वारा उत्पादन-

जब किसी कार्य या सेवा द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता की वृप्ति हो जाती है तो इसे सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है।

उत्पादन के गुण-

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्पादन के अनेक गुण हैं। यदि अर्थशास्त्र का महत्व समाप्त हो जायेगा। उत्पादन के अनेक गुण इस प्रकार हैं।

1. आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन द्वारा होती है-

एक व्यक्ति उत्पादन करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

2. जीवन स्तर उत्पादन की मात्रा पर निर्भर है-

जिस देश का उत्पादन जितना अधिक होता है। उस देश के नागरिकों की प्रति आय उतनी अधिक होती है।

3. देश की आर्थिक उन्नति का आधार उत्पादन है-

जिस देश में जितनी अधिक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा उस देश की उन्नति उतनी ही अधिक होगी।

4. उत्पादन राजकीय आय को बढ़ा सकता है-

सब वस्तुओं के उत्पादन पर कर लगाती जिस देश में जितनी अधिक वस्तुएं उत्पादित होगी उस देश की आय में उतनी ही वृद्धि होगी।

5. उत्पादन के द्वारा ही उपभोग सम्भव है-

आजकल आधुनिक परिपेक्ष्य में उत्पादन के द्वारा ही उपयोग सम्भव है।

अतः स्पष्ट है कि उत्पादन ही देश की आर्थिक उन्नति का आधार है।

आर्थिक विकास की दृष्टि से साधनों की गतिशीलता को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे एक ओर बाजार का अपूर्णतायें दूर होती है, अर्थात् एकाधिकारी व एकाधिकात्यक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने में मदद मिलती है तथा दूसरी ओर साधनों का पूर्ण व अनुकूलतम उपयोग सम्भव होता है। परिणामस्वरूप जहाँ साधनों को उनका उचित प्रतिफल मिलता है व उनका शोषण नियन्त्रित होता है। लागत गिरती है इसका समग्र परिणाम यह होता है कि साधन अप्रयुक्त नहीं रहते उनको बेरोजगारी व अल्प रोजगार की समस्या दूर होती है। तथा तकनीकी प्रगति व आर्थिक विकास प्रोत्साहित होते हैं।

3.3 उत्पादन विधायन का प्रस्थिति-

अर्थशास्त्र में उत्पादन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उत्पादन हमेशा से आर्थिक विकास का मापदण्ड रहा है सामान्यतः उत्पादन से अर्थ किसी पदार्थ या वस्तु के निर्माण से लगाया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन यह अर्थ है कि *“उपलब्ध पदार्थों में तुष्टिगुण का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है”* उत्पादन के सम्बंध में प्रो० टॉमस ने कहा कि *“मूल्य का सृजन ही उत्पादन है”*¹ फयेर चाइल्ड केयरनक्रांस मेयर्स इत्यादि आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पादन को इसी प्रकार परिभाषित करते हैं।

कृषि आधारित उद्योग के अन्तर्गत मिलों में कच्चे माल द्वारा ही उत्पादन कार्य होता है। जैसे चावल मिल में धान से चावल बनाया जाता है, तेल मिल में लाई से तेल बनाया जाता है, आटा मिल गेहूँ से आटा बनाया जाता है दाल मिल में चने से दाल बनाई जाती है इत्यादि।

अतः इस उद्योगों में कच्चे माल धान, गेहूँ, लाही, गेहूँ, कपास की उपयोगिता बढ़ायी जाती है। और इस तरह मूल्य का सृजन किया जाता है। इस उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत

मिलों में कच्चे माल की आर्थिक उपयोगिता को श्रम, पूंजी, प्रबंध मशीनें, जल विद्युत के सहयोग से बढ़ाया जाता है। अतः श्रम, पूंजी, प्रबंध मशीने, जल विद्युत आदि के मध्यम से धान, गेहूँ, लाई, चले, कपास को चावल, आटा, तेल, दाल, सूत में परिवर्तित किया जाता है, जिससे की मूल्यों का सृजन होता है।

कृषि-आधारित उद्योग की उत्पादन संरचना-

उत्पादन की संरचना इस बात पर निर्धारित होती है कि उत्पादन किस श्रेणी के अन्तर्गत आता है। मुख्य रूप से उत्पादन को निम्न लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

1. प्राथमिक उत्पादन
2. अन्तर्वर्ती उत्पादन
3. अन्तिम उत्पादन

प्राथमिक उत्पादन की प्रथम श्रेणी है। इसके अन्तर्गत उत्पादन की प्रथम अवस्था अर्थात् कच्चे माल के प्रथम उपयोग को लिया जाता है। जैसे धान से चावल निकालना प्राथमिक उत्पादन है। अन्तर्वर्ती उत्पादन की द्वितीय अवस्था है। जैसे चावल से लाई पापड़, आटा से डबलरोटी अन्तर्वर्ती उत्पादन के अन्तर्गत आता है। अन्तिम उत्पादन के अन्तर्गत आता है। अन्तिम उत्पादन की तृतीय अवस्था है।

उत्पादन की श्रेणियोंको जानने से इस इन कृषि-आधारित उद्योगों की संरचना स्पष्ट हो जाती है।

किसी भी उद्योग के अन्तर्गत होने वाला उत्पादन स्वयं भी कुछ श्रेणियों में बटा होता है। कृषि-आधारित उद्योगों का उत्पादन भी कई क्रियाओं के माध्यम से होता है। प्रथम क्रिया कच्चे माल को मंगाने की होती है। तदोपरान्त द्वितीय क्रिया जैसे चावल मिल में है तो धान को मशीन में डालना तृतीय क्रिया में धान की भूसी से चावल अलग करना चतुर्थ क्रिया चावल में पालिश और साफ कराना तथा पंचम क्रिया बिक्री के लिये भेजना यही प्रक्रिया दाल

मिल में होती है।

किसी मिल या फैक्टरी का उत्पादन जितना अधिक होगा वह उतनी ही समृद्धिशाली समझी जायेगी। साथ ही मिल का उत्पादन देश की समृद्धिशाली बनाने में भी सहयोग देगा।

इन उद्योगों में उत्पादन कच्चे माल से प्रभावित होता है। कृषि आधारित उद्योगों में मिलों में चावल मिल में धान, दाल मिल में चना, अरहर, आटा मिल में गेहूँ, तेल मिल में लाई आदि कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है।

इन मिलों में प्रतिवर्ष 1704672 कुन्टल कच्चा माल मंगाया जाता है। कच्चा माल उपलब्ध हो जाने पर उत्पादन कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इन मिलों का प्रतिमास औसत उत्पादन 35514 होता है। इस उत्पादित माल को इसके बाद मण्डियों में भेज दिया जाता है।¹¹

उत्पादन- सम्भावना वक्र की अवधारणा और कृषि आधारित उद्योग के संदर्भ में उत्पादन सम्भावना वक्र-

उत्पादन सम्भावना वक्र आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण यंत्र होता है। यदि किसी समय विशेष में साधनों की मात्रा स्थिर है तथा उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है। और एक अर्थव्यवस्था केवल दो केवल दो वस्तुओं तथा का उत्पादन कर रही है तो वस्तु की अधिक मात्रा के उत्पादन करने का अर्थ है कि वस्तु 4 के उत्पादन के साधनों को हटाना पड़ेगा अथवा की अधिक मात्रा के उत्पादन का अर्थ है की कम मात्रा का उत्पादन करना पड़ेगा वस्तु की कितनी मात्रा तथा वस्तु की उत्पादन किया जाये इसके लिये समाज को चुनाव करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में साधनों के पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में समाज को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के सम्बंध में चुनावों की सूची का निर्धारण करना पड़ेगा।

पीपी रेखा उत्पादन सम्भावना रेखा है। इस रेखा पर बिन्दु ए बताता है कि समाज वस्तु की ओ एम मात्रा तथा वाई वस्तु को 0.5 का उत्पादन कर सकता है। बिन्दु सी वस्तु एकस

की ओ एल मात्रा तथा एक्स की ओ आर मात्रा के उत्पादन की सम्भावना को बताता है। इसको चित्र संख्या 3.3 में स्पष्ट कर सकते हैं।

इन मिलों के संदर्भ में उत्पादन सम्भावना वक्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्पादन सम्भावना वक्र के माध्यम से श्रम व पूंजी की मात्रा के संयोगों का पता लगाया जाता है। अतः एक वर्ष में श्रम को कितनी मात्रा प्रयोग की जाये। पूंजी की कितनी मात्रा प्रयोग की जाये इसका पता वार्षिक उत्पादन सम्भावना वक्र के माध्यम से होता है।

श्रम के अन्तर्गत मानसिक व शरीरिक दोनों प्रकार के श्रम लिया गया है। तथा पूंजी के अन्तर्गत मशीनों को भी शामिल किया गया है।

इन मिलों का उत्पादन सम्भावना वक्र पी बिन्दु से प्रकट होता है जिससे पता चलता है कि किसी वर्ष विशेष में चलता है कि किसी वर्ष विशेष में श्रम की ओ पी मात्रा तथा पूंजी की वाई पी मात्रा इन मिलों के लिये अधिकतम है।

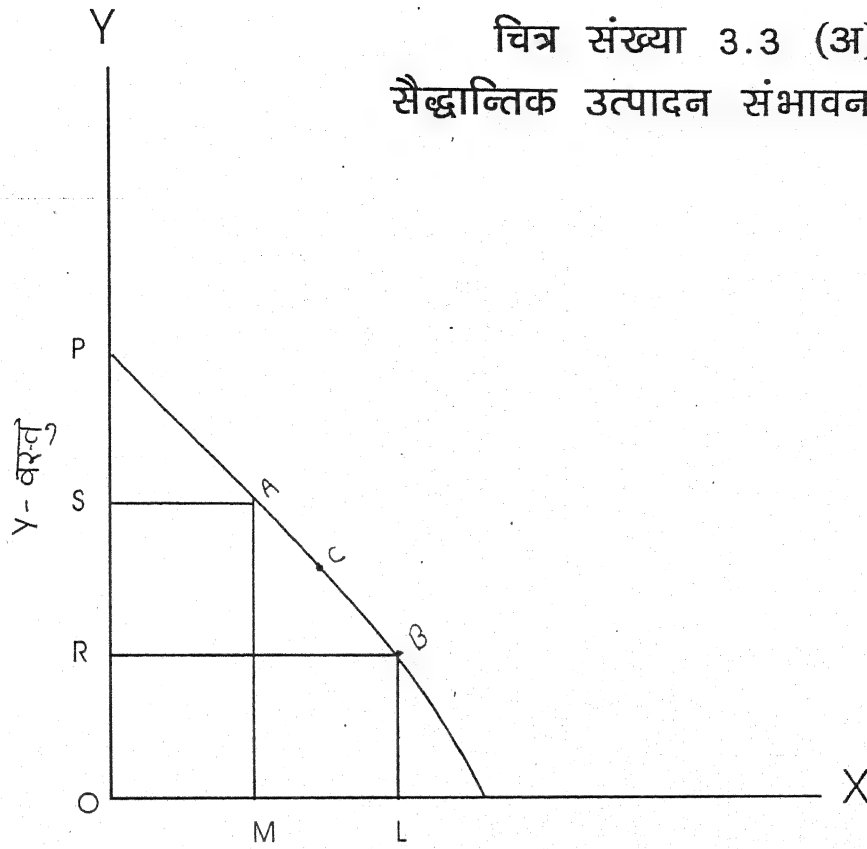
वार्षिक उत्पादन सम्भावना वक्रको आधार मानकर काल्पनिक सम्भावना वक्र बनाये जा सकते हैं। जो कि श्रम व पूंजी के उचित संयोगों को प्रकट करते हैं। सबसे ऊपर वाला वक्र वाई 5 पी श्रम व पूंजी के अधिकतम संयोगों को बताता है। (चित्र 3.3 में स्पष्ट है।)

3.4 कृषि-आधारित उद्योगों का निष्पादन-

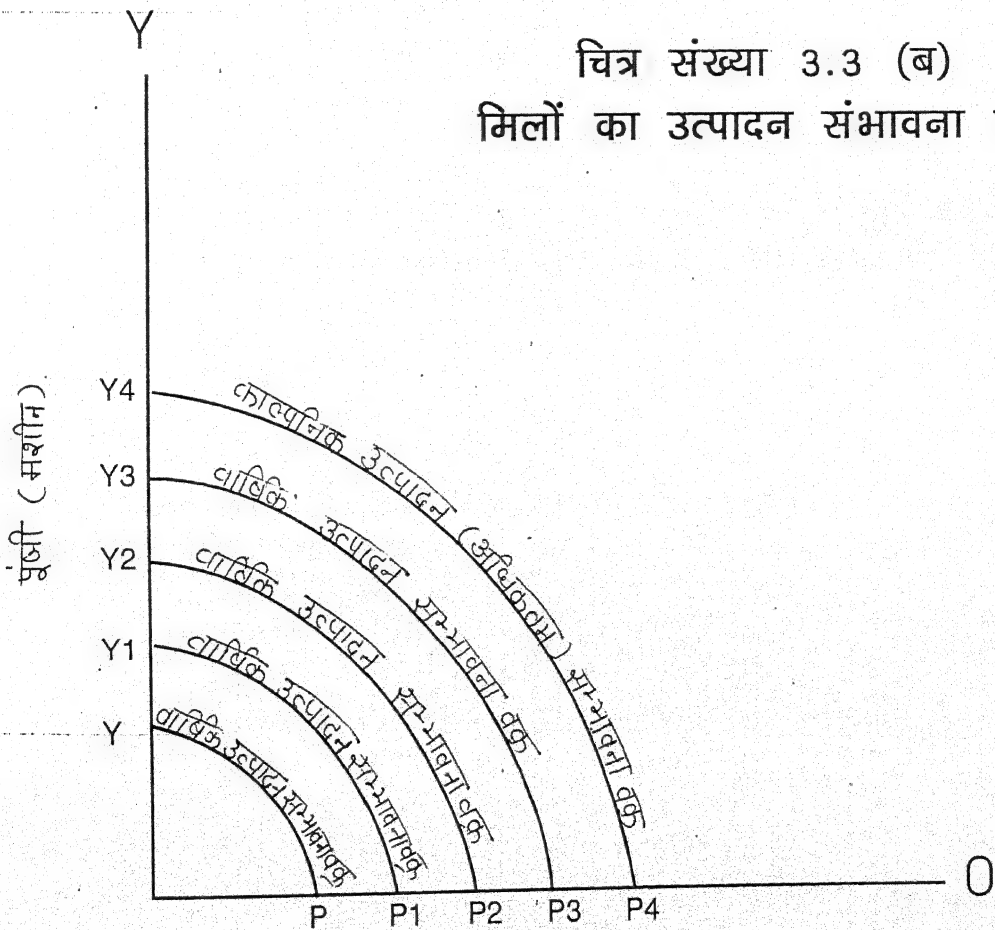
किसी मिल के लिये उसके द्वारा निष्पादित उत्पाद का अत्यन्त महत्व होता है। उत्पादन उत्पाद का अत्यन्त महत्व होता है। उत्पादन निष्पादन पर ही मिल की सफलता निर्भर करती है। किसी देश का उत्पादन ही उसके औद्योगिक विकास की स्थिति को स्पष्ट करता है।

कृषि-आधारित उद्योगों का उत्पादन कच्चे माल द्वारा ही होता है। और कच्चे माल की अधिकतम उपयोगिता को श्रम, पूंजी, प्रबंध, मशीनें, जल, विद्युत का सहयोग से बढ़ाया जा

चित्र संख्या 3.3 (अ)
सैद्धान्तिक उत्पादन संभावना रेखा वक्र



चित्र संख्या 3.3 (ब)
मिलों का उत्पादन संभावना वक्र



सकता है। अतः श्रम, पूंजी, प्रबंध, मशीने, जल विद्युत आदि के द्वारा गेहूँ धान, लाई अरहर, कपास, को चावल, आटा मिल, तेल, दाल, सूत में परिवर्तित किया जाता है। जिससे की उत्पादन प्रक्रिया सम्भव होती है।

वर्ष भर में हुये उत्पादन को वार्षिक उत्पादन कहते हैं। वार्षिक उत्पादन को ज्ञात करने के लिये वर्ष में प्रत्येक मास में हुये उत्पादन को जोड़ा जाता है। कृषि आधारित उद्योग के अर्न्तगत कार्यरत मिलों के उत्पादन निष्पादन की स्थिति को सारिणी संख्या 3.4 में प्रदर्शित कर सकते हैं।

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग के अर्न्तगत कार्यरत
मिलों में उत्पादन निष्पादन की स्थिति
(दस वर्षीय अवधि 1988-98 में)

क्रम सं	वर्ष	उत्पादन (कुन्टल में)
1.	1988-89	22,500
2.	1989-90	23,700
3.	1990-91	49,900
4.	1991-92	22,900
5.	1992-93	34,200
6.	1993-94	24,100
7.	1994-95	21,700
8.	1995-96	22,500
9.	1996-97	54,000
10	1997-98	31,300
	समग्र योग	2,79,800

स्रोत-साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी संख्या 3.4 से स्पष्ट है कि 50 मिलो द्वारा दसवर्षीय अवधि में 1988-89 में 22,500 कुन्टल, 1989-90 में 23,700 कुन्टल, 1990-91 में 49,900 कुन्टल, 1991-92 में 22,900 1992-93 में 34,200 कुन्टल, 1993-94 में 24,100 1994-95 में 21,700 कुन्टल, 1995-96 22,500 कुन्टल, 1996-97 में 45,000 कुन्टल, 1997-98 में 31,300 कुन्टल, उत्पादन की मात्रा रही है। सबसे अधिक उत्पादन की मात्रा 1990-91 में रही तथा सबसे कम 1994-95 में उत्पादन की

मात्रा रही। इस स्थिति को चित्र संख्या 3.4 में स्पष्ट किया गया है।

उपयुक्त उत्पादन सामग्री का उपयोग-

किसी भी उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त व बेकार सामग्री अवश्य बचती है। इस कृषि सामग्री बचती है। जैसे चावल मिल में धान की भूसी, दाल मिल में अरहर चने की भूसी सब बेच दी जाती है दाल मिल में निकाली भूसी जानवरों के खाने के काम आती है। धान की भूसी बर्फ रखने के काम आती है। तथा तेल मिल में निकली खरी भी बेची जाती है जानवर खाते है।

चित्र संख्या 3.4

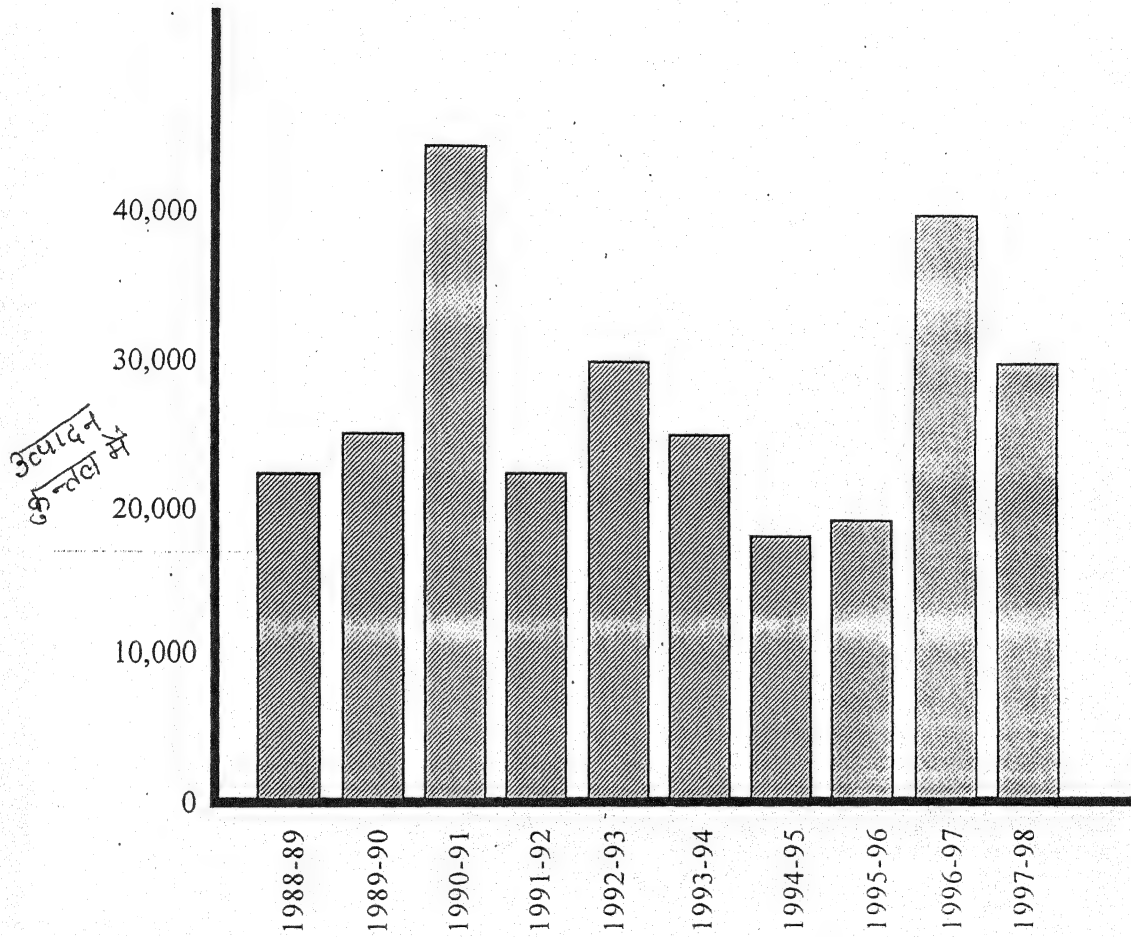
दसवर्षीय अवधि कृषि आधारित उद्योग में कार्यरत 50 मिलों का उत्पादन निष्पादन-

3.4 निष्पादनगत विशिष्ट प्रवृत्तियाँ-

किसी मिल के द्वारा उत्पादन निष्पादन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादन निष्पादन पर महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादन निष्पादन पर ही मिल की सफलता निर्भर ही है। कृषि आधारित उद्योगों का उत्पादन कच्चे माल द्वारा ही होता है। अतः निष्पादनगत विशिष्ट प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है।

1. उत्पादन निष्पादन में कच्चे माल के साथ-साथ श्रम, पूँजी, प्रबंध, जल, विद्युत की भी आवश्यकता होती है।
2. वर्ष में हुये उत्पादन को ही वार्षिक उत्पादन निष्पादन कहते है।
3. वार्षिक उत्पादन को ज्ञात करने के लिये वर्ष में प्रत्येक मास में हुये उत्पादन को जोड़ा जाता है।
4. 50 मिलों द्वारा दसवर्षीय अवधि में सबसे अधिक उत्पादन 1990-91 में 49000 कुन्टल हुआ । और सबसे कम उत्पादन 1994-95 में 21.700

चित्र संख्या 3.4
दसवर्षीय अवधि कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत
50 मिलों का उत्पादन निष्पादन



पैमाना 1" = 10,000 कुन्तल

उत्पादन हुआ।

5. उत्पादन को मुख्य तीन श्रेणियों में रखा जाता है। प्राथमिक अर्न्तवर्ती अंतिम इन्ही श्रेणियों से होकर उत्पादन प्रक्रिया पूरी होती है।
6. दसवर्षीय अवधि में 50 मिलों का कुल उत्पादन 27,9800 कुन्टल हुआ।
7. उत्पादन के पश्चात् बचने वाली बेकार सामग्री का उपयोग हो जाता है।



चतुर्थ अध्ययन

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों का प्रबंधन एवं वित्तीय पक्ष

4.1 कृषि-आधारित उद्योग की प्रबंध व्यवस्था

4.2 कृषि-आधारित उद्योग के वित्त पोषण के स्रोत

4.3 कृषि-आधारित उद्योग एवं बैंक ऋण तथा सरकार प्रेरणायें

4.4 कृषि-आधारित उद्योग एवं मितव्यतायें

4.5 प्रबंधन एवं वित्तीय पक्ष के विशिष्ट पक्ष

चतुर्थ अनुक्रम:-

कृषि-आधारित उद्योगों की प्रबंध व्यवस्था :

प्रबंध किसी भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है प्रबंध पैमाने की बचतें उत्पन्न करता है। जिससे लाभ की उत्पत्ति होती है। प्रबंध उत्पादन में उत्पत्ति बुद्धिमान नियम को गतिशील बनाये रखता है। प्रबंध उत्पादन की बिक्री की नयी तकनीकों को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने का प्रयास करता है तथा श्रमिकों के उचित प्रयोग का उपाय करता है प्रबंध को उत्पादन में महत्ता को जानने से पूर्व इसके अर्थ को जानना अति आवश्यक है।

प्रबंधकीय कौराल की अवधारणा-

प्रबंध के ऊपर उत्पादन को उचित रूप से संगठित करने का भार होता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को इस अनुपात में नियोजित करना कि लागत न्यूनतम रहे प्रबंध का ही कार्य होता है। प्रबंध का अर्थ साहसीधम के अर्थ से अलग है। साहसी का अर्थ है अनिश्चितता को वहन करना जबकि प्रबंध का अर्थ है। उत्पादन को अधिकतम करने के लिये मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम का त्याग करना प्रबंध उत्पादन संबंधी अनेक बातों का निर्णय लेता है। वह यह निश्चित करता है कि उत्पादन छोटी मात्रा में किया जाये या बड़ी मात्रा में इसके साथ-साथ उत्पादित वस्तु को कहाँ-कहाँ बेचा जाये इसका निर्धारण भी प्रबंध करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंध वह है जो उत्पादन को उचित रूप से संगठित करता है। जिन कृषि-आधारित उद्योग का अध्ययन किया जा रहा है उसके अन्तर्गत प्रबंध की अति आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रबंध की आवश्यकता को नकार नहीं जा सकता क्योंकि प्रबंध के बिना उद्योगों में चलना मुश्किल है। अतः इन उद्योगों में एक प्रबंध एक मुनीम, कोषाध्यक्ष, व कर्मचारी वर्ग होता है इस उद्योगों में प्रबंधक मानसिक व शारीरिक श्रम करता

है। तथा उत्पादन संबंधी अनेक बातों का निर्णय लेते हैं इस सबके बदले उसे आटा या वेतन प्राप्त होता है।

कृषि-आधारित उद्योग में प्रबंधकीय कौशल का महत्व

प्रबंध का उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंध उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं को सुचारु रूप से क्रियाशील करता है जिससे उत्पादन में नियमितता बनी रहती है। प्रबंध का अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह पैमाने की बचतों की उत्पन्न करता है। इसके लिये प्रबंध बिक्री व उत्पादन की नयी तकनीकों का प्रतिपादन करता है। और उन्हे प्रयोग में लाता है इसमें विक्रय क्रय उत्पादन तथा उद्योग एवं व्यवसाय के विभिन्न कार्यों की व्यवस्था करनी होती है।

इसके आलावा प्रबंध उत्पादन में उत्पत्ति वृद्धिमान नियम को क्रियाशील बनाये रखने में सहायक होता है। तथा साथ ही उत्पत्ति ह्रासमान नियम पर नियंत्रण रखता है।

कृषि-आधारित उद्योग की प्रबंध व्यवस्था-

बौदा जनपद में इन उद्योगों में एक प्रबंधक एक मुनीम एक कोषाध्यक्ष और एक श्रमिक होते हैं।

इन उद्योगों में प्रबंधक मुख्य होता है यही अधिकतर उद्योगों में स्वयं सभी कार्य देखता है। प्रबंधक से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो संचालक मण्डल के निरीक्षण नियंत्रण एवं निर्देशन या महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लेता है। उत्पादन क्रिया को सुचारु रूप से चलाने का कार्य प्रबंध ही करता है। अतः इन उद्योगों का सम्पूर्ण भार प्रबंधक या मैनेजर के ऊपर ही रखता है।

एक मुनीम होता है जो इन उद्योगों में लिखा पढ़ी का सारा काम देखता है सारा हिसाब इन उद्योगों का मुनीम द्वारा रखा जाता है। सारे बहीखाते उद्योगों के मुनीम तैयार करता है। प्रत्येक मिल में 3 या अधिक से अधिक से अधिक 8 श्रमिक तक कार्य करते हैं जो इन

मिलों के उत्पादन सम्बंधी कार्य में पूर्ण सहयोग देते हैं। मिलों में श्रमिकों के मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं।

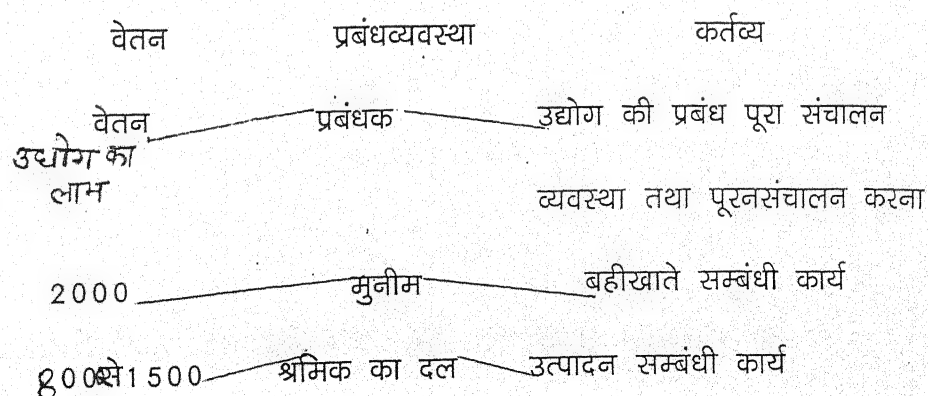
- 1- मशीनों को चलाना।
- 2- उत्पादित माल को कचड़े से अलग करके साफ करना। जैसे दाल और चावल मिल में भूसी को अलग करना और उत्पादित माल को साफ करना।
- 3- मिलों से निकले कचड़े को फेंकना।
- 4- तैयार माल को विक्रय के लिये यातायात के साधन तक पहुँचाना।
- 5- मिलों की सफाई आदि का कार्य करना।
- 6- इसके आलाव प्रबंधक द्वारा बताये गये प्रत्येक को करना।

इन मिलों में श्रमिकों का वेतन लगभग 900 से 1500 के बीच में होता है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रबंध व्यवस्था ही ऐसी है जो उत्पादन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चला सकती है। कृषि-आधारित उद्योगों की प्रबंध व्यवस्था को चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं-

चित्र संख्या-4.1-

प्रबंध व्यवस्था



चित्र संख्या 4.1 से स्पष्ट है कि इन उद्योगों में प्रबंधक ही प्रमुख होता है सभी उद्योग की सारी व्यवस्था देखता है इसका वेतन क्या जितना उद्योगों को लाभ होता है सारी

प्रबंधक को मिलता है क्योंकि जनपद में सारे उद्योग निजी स्वामित्व में हैं। इसके बाद मुनीम होता है ओर उसके बाद श्रमिक होते हैं जो उत्पादन सम्बंधी कार्य करते हैं। इनका वेतन 1200 से 1500 तक रहता है।

४.२ कृषि-आधारित उद्योगों के वित्त पोषण के स्रोत-

किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी उद्योग को लगाने में वित्त की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्योग बिना धन व्यय किये नहीं लगाया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योगों के लगाने में जो संस्थायें या बैंक वित्त प्रदान करते हैं उन्हें ही वित्त पोषण के स्रोत कहते हैं।

उद्योगों की वित्तीय आवश्यकतायें-

उद्योग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त पोषण के स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है ये वित्त निम्न प्रकार के हैं-

1. अल्पकालीन
2. मध्यमकालीन
3. दीर्घकालीन

१. अल्पकालीन औद्योगिक वित्त की आवश्यकता-

यह वित्त कच्चा माल खरीदने का भुगतान करने, माल का स्टॉक करने आदि के लिये आवश्यक होता है। इस वित्त की पूर्ति 1-देशी बैंकों से ऋण 2-व्यापारिक ऋण 3-बैंकों से ऋण 4-जन निरपेक्ष 5-विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से

२. मध्यमकालीन औद्योगिक वित्त की आवश्यकता-

इसकी आवश्यकता बिल्डिंग बनाने या नयी मशीन खरीदने जैसी आवश्यकताओं के लिये होती है। इस वित्त पूर्ति 1-विशिष्ट संस्थायें 2-जन निक्षेप 3-ऋणपत्र

3. दीर्घकालीन आद्योगिक वित्त की आवश्यकता-

इस वित्त आवश्यकता नयी बिल्डिंग बनाने या नयी मशीने खरीदने जैसी आवश्यकताओं के लिये होती है। इस वित्त की पूर्ति 1-अंश पूजी 2-ऋण पत्र 3-अर्जित लाभों का पुनर्विनियोग।

8- विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि से की जा सकती है।

कृषि-आधारित उद्योग के वित्त पोषण स्रोत-

1. भारतीय औद्योगिक वित्त नियम- ये संस्था कृषि आधारित उद्योगों को मध्यमकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।
2. भारत का यूनिट ट्रस्ट -यह भी उद्योगों को वित्तीय साधन प्रदान करती है।
3. साहूकार- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योग धन्धे लगाने के लिये साहूकारों या महाजनों के द्वारा भी ऋण प्राप्त हो जाता है।
4. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम- इस संस्था के द्वारा निजी क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिये की गयी है।
5. राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक- इस संस्था को नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। ये कृषि उद्योगों के लिये वित्त प्रदान करती है।
6. व्यापारिक बैंक- ये कृषि-आधारित उद्योग को दीर्घकालीन व मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान किये करते हैं।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- ये बैंक छोटे पैमाने उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण देती हैं।
8. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा- ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से निजी या सहकारी समितियों को ऋण

पर 4 प्रतिशत ब्याज देय होता है। इससे अधिक के ऋण पर सामान्य ब्याज लिया जाता है।

9. लघु उद्योग विकास बैंक- निजी व सार्वजनिक कृषि आधारित उद्योगों का ऋण प्रदान किया जाता है।

10. विक्रय द्वारा- मध्यम व वृहद उद्योगों की स्थापना हेतु 10 करोड़ तक का ऋण विक्रय द्वारा प्रदान किया जाता है।

11. उ०प्र० वित्तीय निगम- सामान्य ऋण योजना के अर्न्तगत लघु उद्योग स्थापित करने हेतु तथा एन्सलरी ईकाई हेतु ऋण प्रदान किये जाते हैं।

इस प्रकार अन्य वित्तीय संस्थाएँ कृषि आधारित उद्योगों को वित्त प्रदान करती हैं।

8.3-कृषि-आधारित उद्योग एवं बैंक ऋण तथा सरकारी प्रेरणायें।

किसी भी उद्योग को लगाने में वित्त की आवश्यकता होती है। इस वित्त की पूर्ति देशी बैंकस या बैंकों से की जाती है। अब सरकार ने भी कई योजनायें ऐसी शुरू कर दी हैं जिससे अब अधिक से अधिक लोग कृषि-आधारित उद्योग लगाने के लिये प्रेरित हो रहे हैं। बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिये वाणिज्य बैंक ग्रामीण बैंक, ग्राम विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, ग्राम विकास बैंक, जिला सहकारी बैंक सभी ऋण प्रदान कर रहे हैं इसके अलावा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अनेक योजनायें भी शुरू की गयीं जिसके मध्यम से उद्योग लगाने के लिये वित्त की व्यवस्था बैंकों के माध्यम से आसानी से हो जाती है। जैसे प्र० सी० वी० श्रीवास्तव ने कहा है कि-“वित्त को व्यापार एवं उद्योग के पहियों के लिये तेल हड्डियों का सार नाड़ियों का रक्त एवं सभी व्यापारियों की आत्मा बताया है।”¹

अतः वित्त या पूंजी को उद्योगों का रक्त कहा गया है, उद्योगों के लिये धन सम्बंधी आवश्यकतायें तीन प्रकार की होती है।

1. अल्पकालीन औद्योगिक वित्त की आवश्यकता
2. मध्यकालीन औद्योगिक वित्त की आवश्यकता
3. दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की आवश्यकता

अतः उद्योगों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति बैंकों जनपद में इस प्रकार से की गयी है।

9. जिला सहकारी बैंक द्वारा वित्तीय सहायता-

जिला सहकारी बैंक की जनपद में 17 शाखायें तथा प्रारम्भिक ऋण समितियाँ कार्य कर रही हैं। ये शाखायें तथा समितियाँ कृषि सम्बंधी उद्योगों के लिये ऋण प्रदान कर रहे हैं। 1996-97, 20 लाख रु¹ की धनराशी उद्योगों की ऋण के रूप में व्यय की गयी।

2. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय सहायता-

ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये की गयी है। इस बैंक उद्योगों के लिये 1993-94, 2-166.83 लाख रु० की धनराशी व्यय की गयी। 1996-97 में 271.41,³- लाख रु० की धनराशी ऋण के रूप में जनपद में व्यय की गयी।

3. ग्राम विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता-

ग्राम विकास बैंक की जनपद में 4 शाखायें कार्यरत हैं ये सभी शाखायें तहसील स्तर पर हैं। ये कृषि-आधारित उद्योगों के लिये ऋण प्रदान करती हैं। 20 लाख-रु० धनराशी उद्योगों का ऋण के रूप में प्रदान की गयी।

-
1. संभाव्यतायुक्त योजना-1996-97 नाबार्ड
 2. सर्विस एरिया क्रेडिट प्लान - 1993-94
 3. संभाव्यतायुक्त योजना-1996-97 नाबार्ड

४. वाणिज्य बैंक द्वारा वित्तीय सहायता-

जनपद में इलाहाबाद बैंक की 26 शाखाएँ, भारतीय स्टेट बैंक की 6 शाखाएँ, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की 3 शाखाएँ, बैंक आफ बड़ोदा की 1 शाखा, यूनियन बैंक की एक शाखा, पंजाब नेशनल बैंक की 1 शाखा, कार्यरत है। इन बैंक के द्वारा भी इन उद्योगों को ऋण प्रदान किये गये हैं। 284.84 लाख रु० की धनराशि 1996-97 में व्यय की गयी है।

सारणी- 4.3

बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की सारणी-(राशि लाख में)

वित्तीय सहायता	राशि	
	1995-96	1996-97
वाणिज्य बैंक	227.09	284.84
ग्रामीण बैंक	151.59	166.83
ग्राम विकास बैंक	6.00	20.00
जिला सहकारी	6.00	20.00
योग:-	390.68	418.87

स्रोत:- नाबार्ड बैंक पत्रिका-

सारिणी संख्या-4.3(अ)

प्रदत्त बैंक ऋण- (राशि लाख में)

क्रम सं०	उद्योग का नाम	1995-96	1996-97
1.	मिनी धान मिल	8.27	9.00
2.	आटा मिल	11.42	10.00
3.	शीत गृह	11.83	12.60
4.	गुड़ निर्माण	4.42	4.50
योग:-		36.34	36.10

स्त्रोत:- संभाव्यतायुक्त योजना-1995-96, 1996-97

अतः स्पष्ट बैंकों द्वारा उद्योगों के लिये 1995-96, में 582.45, 1 लाख रु० की राशि के लिय 1996-97 में 667.17, 2 लाख रु० की राशि प्रदत्त की गयी।

सरकारी प्रेरणायें व सुविधायें-

सरकार द्वारा अनेक प्रेरणायें व सुविधायें शुरू की गयी है जिससे व्यक्ति कृषि आधारित उद्योग लगाने के प्रेरित हो रहा है। उद्योग लगाने के लिये शुरू की गयी योजनायें, इस प्रकार की है।-

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजना-

यह योजना जनपद में ग्रामीण शहरी युवकों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिये ऋण प्रदान करती है। इस योजना के अर्न्तगत 1996-97 में बैंको द्वारा 150.00 लाख रु० के ऋण वितरित किये गये।

2. हस्तशिल्प ऋण योजना-

नाबार्ड योजना के माध्यम से रिफाइलैसिंग योजनान्तर्गत तथा अधिकतम रु० 2 लाख तक स्थानीय बैंकों से ऋण प्रदान कराया जाता है।

3. एकल विन्डो योजना-

रु0 30 लाख तक की पूंजी निवेश के लघु उद्योगों के स्थापार्थ उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा भूमि भवन मशीनरी एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण किया जाता है।

4. नाबार्ड योजना-

इस योजना के माध्यम से लघु/लघुत्तर इकाईयों की स्थापना हेतु जिला उद्योगा केन्द्र उद्यमियों को रु0 10 लाख तक ऋण स्थानीय बैंको से उपलब्ध कराता है। जो कि नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदाता बैंको को पुर्न वित्त योजना के माध्यम से देय है।

5. खादी ग्रामोद्योग द्वारा प्रदत्त सुविधायें-

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभिन्न कुटीर/लघुत्तर/लघु उद्योगों की स्थापना हेतु 2 लाख तक क ऋण जिला स्तर से विभिन्न बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न बैंको द्वारा वित्त पोषण पर बोर्ड द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज में अनुदान/छूट उद्यमी के पक्ष में सम्बंधित बैंक को उपलब्ध कराई जाती है।

6. व्यापार कर छूट-

नई औद्योगिक इकाईयों को जो 1495 के बाद एवं 31.3.2000 के पूर्व स्थापित हुई हो अथवा स्थापित ईकाई में विस्तार, विविधाकरण, आधुनिकीकरण किया गया हो जिसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त अचल पूंजी विनियोजन के साथ-साथ 25 प्रतिशत उत्पादन में भी विस्तार हुआ हो उन्हें व्यापार कर में छूट मिलेगी।

7. विद्युत भार-

ईकाई स्थापना में आवश्यक 100 अश्वशक्ति तक के विद्युत भार की जिला स्तर पर जिला उद्योग बंधु के माध्यम से स्वीकृति प्रदान कराई जाती है। तथा 100 अश्वशक्ति से अधिक वांछित विद्युत भार स्वीकृति हेतु मण्डल स्तरीय कमेटी का संस्तुति भेजी जाती है।

8. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय-

ये हथकरघा उद्योग व बुनकरों को सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्षतः स्पष्ट हैं कि बैंक द्वारा समय-समय कृषि आधारित उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। जिससे कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता मिल जाती हैं। सरकार ने अनेक योजनायें शुरू की हैं जिससे लोग आधारित उद्योग लगाने के लिये प्रेरित हो रहे हैं।

उपरोक्त वित्तीय सहायता व योजनाओं के संदर्भ में शोधार्थीनी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा मिलों के मालिकों से उनकी वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी है जिसे सारिणी संख्या 4.3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या-4.3(ब)

जनपद में कृषि-आधारित उद्योगोंको प्राप्त वित्तीय सहायता।

क्रमसंख्या	वित्तीय सहायता	हाँ	नहीं
1	2	3	4
1.	बैंको द्वारा	26	24
2.	जिला उद्योग के माध्यम से	15	35
3.	अन्य स्रोतों से	12	38

स्रोत:- साक्षात्कार अनुसूची

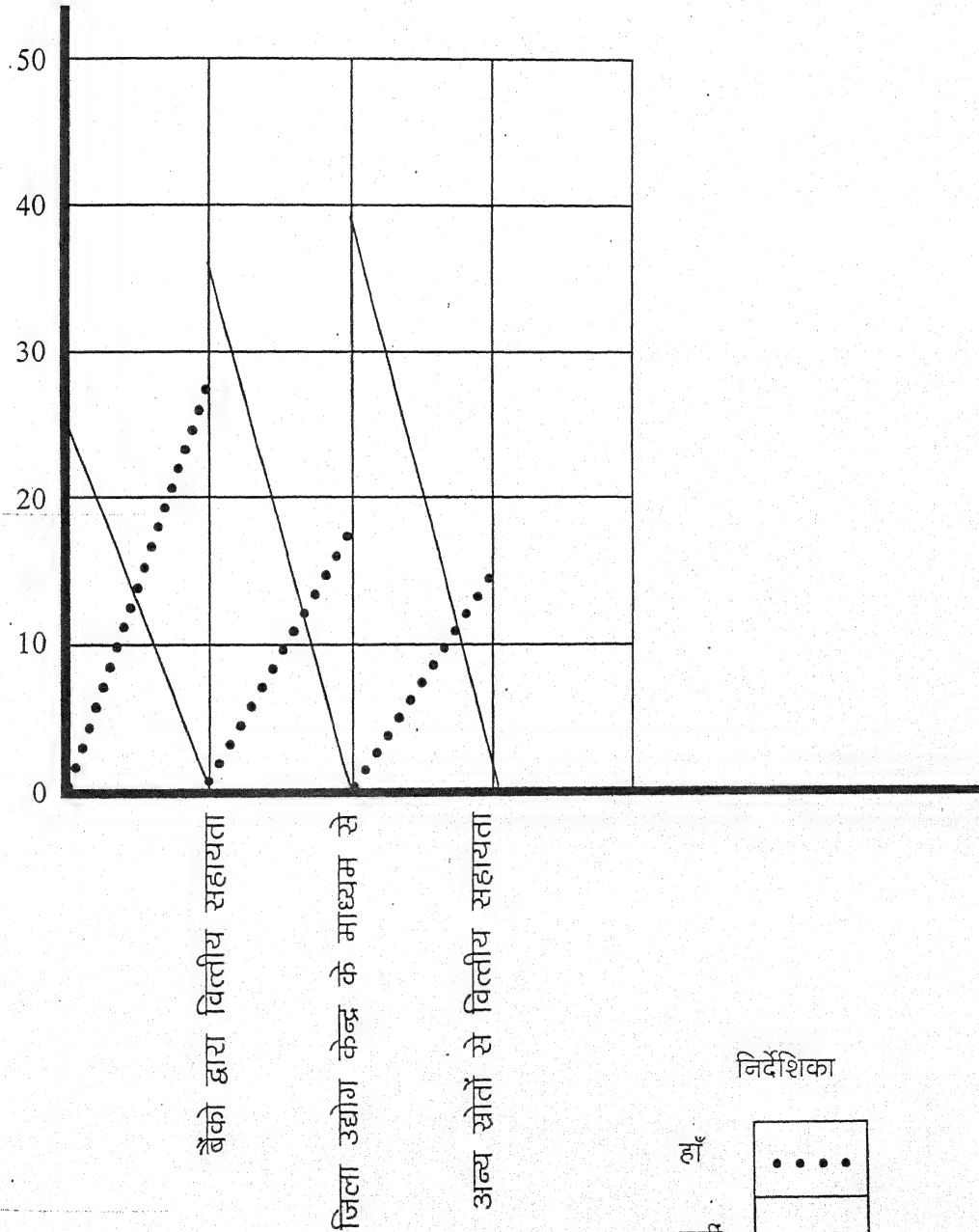
चित्र संख्या-4.3-बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग को प्राप्त वित्तीय सहायता

1 बैंको द्वारा वित्तीय सहायता 2 जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 3 अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता

निर्देशिका- हाँ नहीं

सारिणी संख्या-4.3

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग
को प्राप्त वित्तीय सहायता



निर्देशिका

हाँ

• • • • •
—

नहीं

सारिणी संख्या 4.3 के अनुसार जनपद में 50 मिलो को प्राप्त वित्तीय सहायता को हाँ/नहीं में व्यक्त किया गया। जिसमें 26 सबसे अधिक बैंको से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

8.8-कृषि-आधारित उद्योग एवं मितव्यतायें/अमित्यतायें

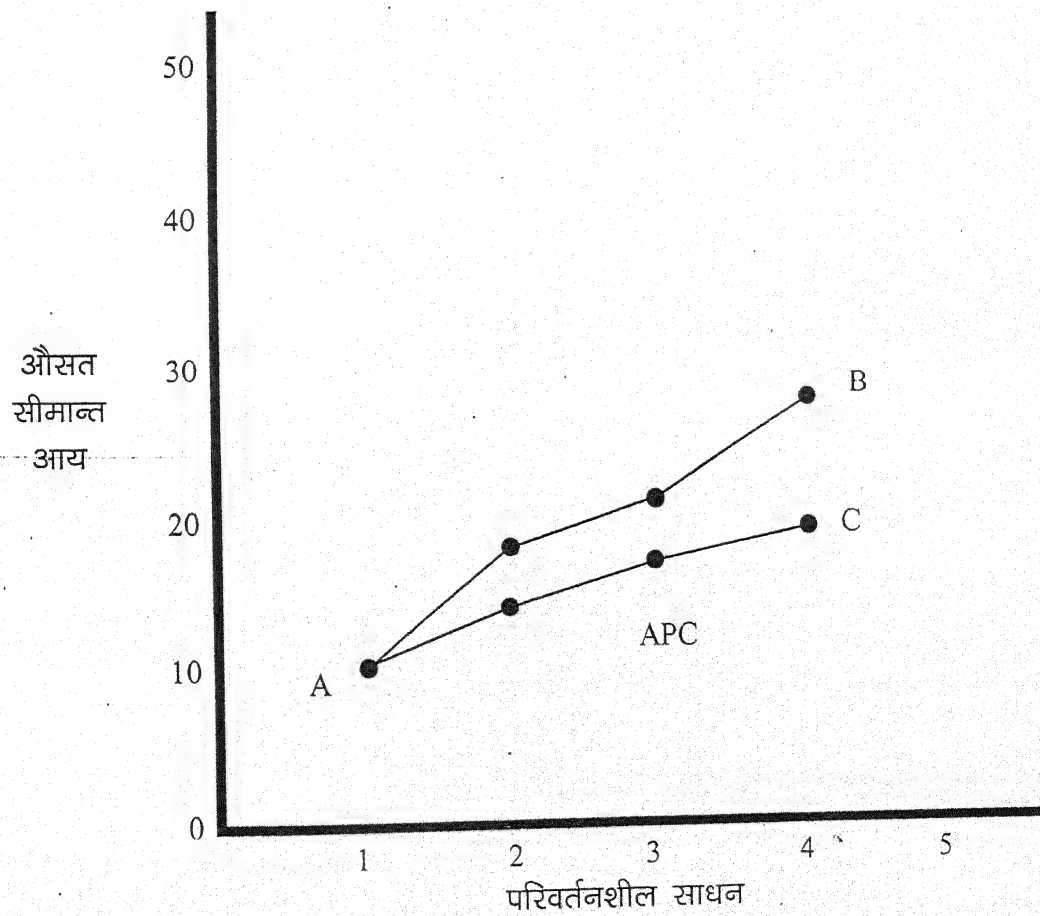
कृषि-आधारित औद्योगिकरण की मूल संकल्पना कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था से सम्बद्ध है। इसका मूल उद्देश्य ग्राम्य आर्थिक संरचना को उर्ध्वमुखी रूप में रूपान्तरित करना है। इन उद्योगों के द्वारा उस क्षेत्र का भी विकास सम्भव हो जाता है। जहाँ ये उद्योग स्थापित किये जाते हैं उस क्षेत्र में विपणन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है यातायात के साधन बड़े मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि-आधारित उद्योगों के द्वारा मितव्यतायें प्राप्त होती हैं क्योंकि उद्योग धन्धों में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। नियम यह बताता है “जब उत्पादन के एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है तो जिस अनुपात से इन साधनों में वृद्धि की जाती है। उत्पादन की मात्रा उस अनुपात से भी अधिक बढ़ती है उत्पादन वृद्धि की इस प्रवृत्ति को उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं।”¹

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

सारिणी संख्या-4.4

श्रम की ईकाईयों	कुल उत्पादन टीपी	औसत उत्पादन एपी	सीमान्त उत्पादन एमपी
1	10	10	10
2	24	12	14
3	45	15	21
4	76	19	31
5	115	23	39

चित्र संख्या-4.4



अतः स्पष्ट है कि उद्योग धन्धों में वृद्धि नियम लागू होता है इसलिये कृषि-आधारित उद्योगों में मितव्यतायें प्राप्त होती है जो इस प्रकार है।

- 1- चीनी उद्योगों में निकला कचड़ा भी काम आ जाता है।
- 2- तेल मिल से निकली खरी जानवरों के खाने के काम आती है।
- 3- दाल मिल से निकली भूसी जानवरों के भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं।
- 4- आटा मिल से निकली भूसी भी काम में आ जाती है।
- 5- चावल मिल से निकली भूसी भी बर्फ रखने के काम में आ जाती है।
- 6- कताई मिल में निकले छोटे रेशों से दरी आदि बन जाती है।
- 7- जूट उद्योग में निकले माल से सजावट का सामान बनाया जाता है। जहाँ ये उद्योग होते हैं। वहाँ सड़क बन जाती है। यातायात के साधन सुलभ हो जाते हैं।

अमित्यतायें-

कृषि-आधारित जिन क्षेत्रों में स्थापित होते हैं वहाँ अमित्यतायें भी प्राप्त होती है जो अमित्यतायें प्राप्त होती है वो इस प्रकार है-

- 1- जिन क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ प्रदूषण फैलता है।
- 2- कृषि-आधारित उद्योगों में कृषि उत्पादन कम होने पर लागत अधिक आ जाती है । ये उद्योग पूर्णतः कृषि पर आधारित रहते हैं।
- 3- इन उद्योगों में श्रमिकों को कार्यनुसार वेतन प्राप्त नहीं होते हैं।
- 4- जिन क्षेत्रों में ये उद्योग होते हैं। वहाँ शोर अधिक होता है
- 5- जिन क्षेत्रों में यह उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ कचड़ा अधिक फैलता है।

8.4-प्रबंधन एवं वित्तीयन पक्ष के विशिष्ट पक्ष

प्रबंधन-

कृषि-आधारित उद्योग में मुख्य रूप से प्रबंध का कार्य प्रबंधक ही देखता है। इन उद्योगों में प्रबंधन इस प्रकार से होता है-

- 1- इन उद्योगों में मुख्य प्रबंधक होता है। वही फर्म का सम्पूर्ण कार्य देखता है।
- 2- इन उद्योगों में एक मुनीम होता है। जो फर्म का बही खाते सम्बंधित कार्य करता है।
- 3- इन उद्योगों व फर्मों में उसे 8 श्रमिक तक होते हैं जो बाकि सारा कार्य करते हैं। जैसे-मशीन को चलाना, उत्पादित माल को कचड़े से अलग करना इत्यादि।

वित्तीयन पक्ष-

इन उद्योगों का वित्तीयन प्रबंध इस प्रकार होता है।

- 1- वाणिज्य बैंको, ग्रामीण बैंकों, तथा सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं।
- 2- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भी बाँदा द्वारा भी इन उद्योगों को अनेक योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री योजना नाबार्ड योजना, खादी ग्रामोद्योग, इत्यादि के माध्यम से वित्त प्रदान किया जाता है।
- 3- साहूकारों तथा महाजनों के द्वारा भी इन उद्योगों को वित्त प्रदान किया जाता है।
- 4- अधिकतर उद्योग अपना वित्तीयन प्रबंधन स्वयं करते हैं।
- 5- जनपद में अधिकतर मिल मालिक बैंको से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।



पंचम अनुक्रम

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों का रोजगार सृजन एवं आय संवृद्धि पक्ष

5.1 कृषि-आधारित उद्योगों का मजदूरी/वेतन पक्ष

5.2 कृषि-आधारित उद्योगों का रोजगार सृजन पक्ष

5.3 कृषि-आधारित उद्योगों का आय संवृद्धि पक्ष

5.4 कृषि-आधारित उद्योगों की श्रम संरचना

5.5 कृषि-आधारित उद्योगों के रोजगार सृजन एवं आय संवृद्धि की विशिष्ट प्रवृत्तियां

पंचम अनुक्रम

५.१ कृषि-आधारित उद्योगों का मजदूरी/वेतन पक्ष -

किसी भी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को श्रम के प्रयोग के लिये दी गयी कीमत मजदूरी कहलाती है। जैसा बेन्हम ने कहा भी है-

"A wage may be defined as a sum of money paid under contract by an employer to a worker services rendered".¹

अर्थात् मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो समझौते के अनुसार एक सेवायोजक अपने श्रमिक को उसकी सेवाओं के लिये देता है।

किसी भी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कुछ निश्चित अवधि में किया जाता है। मजदूरी भुगतान की प्रकृति का निर्धारण फर्म मजदूरी भुगतान की प्रकृति का निर्धारण फर्म मालिक प्रदान की जाती है। इस उद्योग में दैनिक व साप्ताहिक मजदूरी प्रदान की जाती है। इस उद्योग में प्रबंधक श्रमिकों को आवश्यकता एवं स्थिति को देखते हुये मजदूरी का भुगतान करते हैं। जिसमें श्रमिकों को सुविधा हो। जबकि फर्म मालिकों को कोई अतिरिक्त व्यय भार सहन नहीं करना पड़ता है। बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योगों मजदूरी भुगतान की प्रकृति सारिणी संख्या 5.1 में प्रदर्शित की गयी है।

1. सिंह एस0पी0 अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

सारिणी संख्या-5.1

बाँदा जनपद के कृषि-आधारित उद्योग के विभिन्न
फर्मों (मिलों) में मजदूरी की प्रकृति

क्रम संख्या	भुगतान की प्रकृति	मजदूरी रु० में	फर्मों की संख्या (मिलों)	
1.	दैनिक	0-50	04	8.00 प्रतिशत
		50-100	06	12.00 %
2.	मासिक	0-1000	06	12.00 %
		1000-2000	32	64.00 %
		2000-3000	02	4.00 %
	समग्र योग		50	100 प्रतिशत

स्तोत्र -साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी - कोष्ठक में प्रदर्शित संख्या प्रदर्शित कालम संख्या का प्रतिशतांश है।

उपरोक्त सारिणी संख्या 5.1 से स्पष्ट होता है कि बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान दैनिक एवं मासिक आधार पर हो किया जाता है। जनपद में 10 मिलों या फर्मों में दैनिक मजदूरी भुगतान जबकि 6 अन्य मिलों में 1000 रु० मासिक के अन्दर ही श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 32 मिलों में 1000-2000 के मध्य प्रति श्रमिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है और 2 फर्मों में 2000-3000 के मध्य प्रति श्रमिक मजदूरी भुगतान किया जाता है।

मजदूरी भुगतान की दरें-

कुल उत्पादन में से साधन श्रम का जो भाग अथवा परितोषण दिया जाता है उसे

साधारण मजदूरी कहते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण श्रम का मूल्य कह सकते हैं। किसी उद्योग में मजदूरी की दरे श्रमिकों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की जाती है। जनपद की विभिन्न मिलों में मजदूरी की दरे अलग-अलग निर्धारित होती है। बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग को पर्याप्त सुविधा एवं प्रशासनिक देखरेख न प्राप्त हो पाने के कारण इनके श्रमिकों की मजदूरी बहुत कम रहती है। कुछ उद्योगों में कार्य के घण्टे भी निश्चित नहीं है। जिससे इन श्रमिकों को अपने कार्य के अनुरूप मजदूरी नहीं प्राप्त हो पाती है।

इन उद्योगों में यदि श्रमिक छुट्टी लेता है तो दैनिक वेतन के हिसाब से उसका वेतन काट लिया जाता है।

4.2 कृषि-आधारित उद्योगों का रोजगार सृजन पक्ष-

आज उद्योगों में श्रमिक को रोजगार देकर बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाता है। जनपद में आधे से अधिक श्रमिक कृषि आधारित उद्योगों में कार्य में लगे हैं।

रोजगार का तात्पर्य है काम पाने वाले व्यक्तियों का काम मिल सके।

लेकिन वर्तमान परिपेक्ष्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं है। जैसे केन्स ने अपने सिद्धान्त में वर्णित किया कि *अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की दशा में नहीं रहती अपितु सामान्य तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह सदैव अपूर्ण रोजगार की स्थिति में ही रहती।*¹

अतः स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है।

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों में रोजगार की स्थिति को शोधार्थीनी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा सारिणी संख्या 5.2 में प्रदर्शित किया गया है।

1. केन्स - General Theory of Employment Interest and Money.

सारिणी संख्या-5.2

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों में
रोजगार में लगे श्रमिक

क्रम सं	उद्योग का नाम	मिलों की संख्या	रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या
1.	दाल मिल	04	32
2.	चावल मिल	12	96
3.	तेल मिल	24	154
4.	मसाला उद्योग	02	08
5.	लाही उद्योग	02	08
6.	आटा मिल	06	48
	संग्रह योग	50	346

स्रोत साक्षात्कार अनुसूची

संदर्भ सारिणी 5.2 के अनुसार जनपद की 50 मिलों में रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या को स्पष्ट किया गया है। दाल मिलों में 32 श्रमिकों चावल मिलों 84 श्रमिकों को तेल मिल में, 154 श्रमिकों को मसाला उद्योग में 8, श्रमिकों को लाही उद्योग में 8 श्रमिकों को, आटा मिलों में 48 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। इस प्रकार कृषि-आधारित में जनपद के श्रमिकों को रोजगार प्राप्त है।

अतः कृषि आधारित उद्योगों में शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाता है इनमें महिला श्रमिकों को भी काम मिल जाता है। जिससे उनके जीविकोपार्जन का सहारा हो जाता है। अतः जनपद में सबसे अधिक श्रमिक कृषि-आधारित उद्योगों में ही रोजगार में लगा है।

4.3 कृषि-आधारित उद्योगों का आय संवृद्धि पक्ष-

संवृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि होना। आय संवृद्धि से तात्पर्य है आय में वृद्धि होना। आय में यह वृद्धि उत्पादन में वृद्धि करके तथा अधिक रोजगार प्रदान करके की जा सकती है। कृषि आधारित उद्योग में कार्यरत मिलों में लगे श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल से दस वर्षीय अवधि में कुल 120314000 आय प्राप्त हो रही है। इस उद्योग में 346 व्यक्ति रोजगार में लगे हैं। एक सारिणी 5.3 रोजगार के द्वारा आय संवृद्धि को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।

सारणी - 5.3

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग
में रोजगार लगे व्यक्तियों द्वारा आय में वृद्धि
(दस वर्षीय अवधि 1988-98)

क्रमसं	उद्योग का नाम	मिलो की संख्या	रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या	रोज0से प्राप्त आय
1.	दाल मिल	4	32	11127306
2.	चावल मिल	12	84	29209178
3.	तेल मिल	24	154	53550161
4.	मसाला उद्योग	2	8	2781462
5.	लाही उद्योग	2	8	2781462
6.	आटा मिल	6	48	16690959

स्रोत-साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी में दसवर्षीय अवधि में कृषि-आधारित उद्योग में मिलों में रोजगार में लगे व्यक्तियों से आय में संवृद्धि की स्थिति इस प्रकार है। दाल मिल में 32 व्यक्तियों द्वारा आय में 1127306 रु० आय में वृद्धि चावल मिल में 84 व्यक्तियों द्वारा मसाला उद्योग में 8

व्यक्तियों के द्वारा 2781662 रु० की आय में वृद्धि लाही उद्योग में 8 व्यक्तियों द्वारा 2782461 रु० की आय में वृद्धि हुयी।

उपरोक्त आय में वृद्धि व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने के कारण प्राप्त हो रही है। क्योंकि जब व्यक्तियों या श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। तो उत्पादन कार्य में वृद्धि होती ही की जाती है। क्योंकि उत्पादन कार्य श्रमिकों द्वारा ही सम्पन्न होता है।

अतः स्पष्ट है कि उत्पादन बिक्री के अतिरिक्त आय में संवृद्धि व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करके की जा सकती है। क्योंकि जितने अधिक श्रमिक उत्पादन कार्य में लगेगे उत्पादन उतना ही अधिक मात्रा में होगा। और उत्पादन बिक्री से अधिक आय प्राप्त की जा सकेगी।

५.४ कृषि-आधारित उद्योगकी श्रम संरचना-

किसी भी उद्योग की उत्पाद संरचना में श्रम एक महत्वपूर्ण साधन है। बाँदा जनपद कृषि आधारित उद्योग में श्रम की महत्ता बहुत अधिक समस्या है। इन उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिये मानवीय श्रम की ही आवश्यकता होती है। अतः यह उद्योगपूर्णतया मानवीय श्रम पर आधारित है।

“श्रम का अर्थ मानव के उस मानसिक तथा शारीरिक प्रयास से है जो अशतः या पूर्णतया कार्यशील प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले आनन्द के अतिरिक्त किसी लाभ की दृष्टि से किया जाये। अतः श्रम के लिये दो बातें होना आवश्यक है।”¹

1. श्रम के अन्तर्गत शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित किये गये हैं।
2. श्रम के अन्तर्गत केवल वे ही प्रयत्न आते हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक होता है। केवल आनन्द केलिये किये गये श्रम को अर्थशास्त्र में श्रम नहीं कहेंगे।

श्रम को मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. कुशल तथा अकुशल श्रम।
2. उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम।

सामान्य रूप में अकुशल श्रम वह है जिसमें केवल सामान्य योग्यता की आवश्यकता हो तथा कुशल श्रम वह है जिसमें सामान्य के अतिरिक्त विशेष योग्यता की आवश्यकता हो।

इन उद्योगों में कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक कार्य करते हैं। वैसे इन उद्योगों में अकुशल श्रम अधिक कार्य करता है। जैसे दाल चावल मिल में तैयार माल से भूसी अलग करना। और मशीनों को चलाने के लिये कुशल श्रम की आवश्यकता होती है।

श्रम का उत्पादक व अनुत्पादक रूप में वर्गीकरण अत्यन्त भांतिपूर्ण है। प्रो मार्शल ने उत्पादक व अनुत्पादक श्रम को इस प्रकार व्यक्त “वह श्रम अनुत्पादक है जो हमें उद्देश्य की ओर बढ़ाने में असफल है। इसलिये वह उपयोगिता का उत्पादन नहीं करता ऐसे श्रम को छोड़कर अन्य सभी श्रम उत्पादक हैं।

इन उद्योगों में चूंकि श्रमिक उत्पादक हैं। कार्य करते हैं परिश्रमिक प्राप्त करते हैं। अतः यहाँ प्रयुक्त श्रम उत्पादक है

इन उद्योगों में श्रमिकों की स्थिति व प्रकृति उद्योगों में श्रमिकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें श्रम मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार का है। बिना श्रम के इन उद्योगों की उत्पादन व निष्पादन की प्रक्रिया असम्भव है।

बाँदा जनपद के कृषि-आधारित उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय है श्रमिक के जीवन स्तर एवं कार्यक्षमता का स्तर बहुत निम्न एवं कम है। इन उद्योगों में अधिकांश मिलों में स्वयं साहसिक एवं श्रमिक है। इसलिये अधिकांश काम श्रमिकों को करना पड़ता है। इन उद्योगों में महिला श्रमिक है। व बाल श्रमिक नहीं होते हैं। इन उद्योगों में

अशिक्षित श्रमिक अधिक कार्य करते हैं। इसलिये इनका शोषण होता है। इन वेतन कम दिया जाता है। इन उद्योगों में श्रमिकों के जीवन स्तर के निम्न होने के कारण दे।

अशिक्षा अज्ञानता रुढ़िवादिता आर्थिक दुर्बलता इत्यादि। मशीनों को चलाने केलिये इनको प्रशिक्षण दिया जाता है उस समय भी न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है।

बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग में लगे हुये श्रमिकों की स्थिति सारिणी संख्या 5.4 से स्पष्ट है।

सारिणी संख्या 5.4 से स्पष्ट होता है कि नगर में संचालित कृषि उद्योग में स्वयं मालिकों व प्रबंधकों के अतिरिक्त जो श्रमिक जो कार्य करते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है। कारण यह है कि इस उद्योग में कार्य करने वाले अधिकतर श्रमिक अशिक्षित हैं, इन उद्योगों में श्रमिकों की स्थिति को सारिणी संख्या 5.4 में दर्शाया जा रहा है-

सारिणी संख्या-5.4 (अ)

बाँदा नगर में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति (1988-98)

क्रमसं	श्रमिकों के प्रकार	शिक्षित	अशिक्षित
1.	पुरुष	76	246
2.	महिला	---	12
3.	बाल श्रमिक	---	---
	समग्र योग	76	258

स्रोत साक्षात्कार अनुसूची

सारिणी संख्या-5.4 में 76 पुरुष श्रमिक शिक्षित तथा 246 पुरुष श्रमिक अशिक्षित हैं। 12

महिला श्रमिक हैं जो अशिक्षित हैं।

श्रमिकों के कार्य करने की अवधि-

श्रमिकों की मजदूरी और कार्य करने की अवधि में सदैव ही विवाद रहा है। प्रारम्भ में लोगों का विश्वास था कि मजदूर जितनी देर तक कार्य करेगा। उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। जब कभी काम के घण्टों को कम किया गया तो इसका कारण केवल मिल मालिकों की उदारता थी। अब सरकारी तौर पर हमारे देश में मजदूरों की कार्य अवधि 8 घण्टे निश्चित की गयी है। इसके अतिरिक्त मिल अतिरिक्त मिल मालिक मजदूरों को सुविधा देने के लिये बाध्य है। इन उद्योगों में श्रमिकों के कार्य करने की अवधि सारिणी संख्या 5.4 से स्पष्ट है।

सारणी - 5.4 (ब)

कृषि-आधारित उद्योगों में विभिन्न मिलों में श्रमिकों की कार्य अवधि की परिगणना (1988-98)

क्रमसं	कार्यावधि घण्टों में	फर्मों की संख्या	
1.	2-4	00	(0.00%)
2.	4-6	00	(0.00%)
3.	6-8	48	(96.00%)
4.	8-10	02	(4.00%)
	समग्र योग	50	100%

स्रोत-साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी - लघु कोष्ठ में प्रदर्शित संख्या सम्बंधित कालम संख्या का प्रतिशतांश है।

अतः सारिणी संख्या 5.4 से स्पष्ट है कि 48 मिलों में 6 से 8 घण्टे काम होता है।

तथा 2 मिलों में 8 से 12 घण्टे काम होता है।

५.५ कृषि-आधारित उद्योगों के रोजगार सृजन एवं आय संवृद्धि की विशिष्ट प्रवृत्तियों-

1. कृषि-आधारित उद्योग में जनपद में 346 श्रमिक कार्यरत हैं।
2. आज अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है अर्थात् आज कल सभी को रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिये अपूर्ण रोजगार की स्थिति है।
3. जनपद में सबसे अधिक श्रमिक तेल उद्योग में लगे हैं।
4. अतः जनपद में कृषि आधारित उद्योग में चावल मिल व तेल मिल अधिक मात्रा में है इसलिये तेल मिल तथा चावल मिल जनपद में लगाना ज्यादा लाभप्रद है। इसमें अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल जायेगा।
5. आय संवृद्धि उत्पादन में वृद्धि करके तथा अधिक मात्रा में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके की जा सकती है।
6. कृषि आधारित उद्योग में मिलों में रोजगार में लगे श्रमिकों द्वारा आय में प्रत्येक वर्ष वृद्धि ही हुयी है।
7. दस वर्षीय अवधि में कृषि आधारित उद्योग में मिलों में लगे श्रमिकों से 120314000 रु० की आय प्राप्त हो रही है।
8. रोजगार से आय संवृद्धि उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही सम्भव है।
9. सबसे अधिक आय तेल मिलों के मध्यम से प्राप्त होती है।

अतः स्पष्ट है कि जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों में अधिक व्यक्तियों या श्रमिकों को रोजगार प्रदान करके आय में संवृद्धि की जा सकती है अतः आय संवृद्धि हो सकती है।



षष्ठम अनुक्रम

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों का लागत लाभ पक्ष

6.1 कृषि-आधारित उद्योगों का लागत पक्ष

6.2 कृषि-आधारित उद्योगों का मूल्य निर्धारण पक्ष

6.3 कृषि-आधारित उद्योगों का विक्रय पक्ष

6.4 कृषि-आधारित उद्योगों का आगम पक्ष

6.5 कृषि-आधारित उद्योगों का प्रतिफल पक्ष

पष्ठम अनुक्रम

६.१ कृषि-आधारित उद्योगों का लागत पक्ष :-

एक दी हुई कीमत पर कोई उत्पादक वस्तु विशेष का कितना उत्पादन करेगा यह बात उत्पादन लागत पर निर्भर करेगी। उत्पादन लागत प्रायः तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है।

- 1- द्वाब्यिक लागत।
- 2- वास्तविक लागत।
- 3- अवसर लागत।

साधारणतया किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिये उत्पादक जो द्रव्य व्यय करता है उसे इस मिलों के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है। अवसर लागत का विचार एक महत्व पूर्ण विचार है। अवसर लागत उत्पत्ति के साधनों को वितरित करने में सहायक है साथ ही यह लागत में परिवर्तन पर प्रकाश डालता है।

इन उद्योगों केलिये सबसे अधिक महत्व कुल लागत का है जो भागों में बटी है-

- 1- स्थिर लागत
- 2- परिवर्तन लागत

१. कुल स्थिर लागत :-

कुल स्थिर लागत वह है जो स्थिर साधनों को प्रयोग में लाने के लिये लगायी जाती है। स्थिर साधन वे साधन हैं जिनकी मात्रा बहुत शीघ्रता से परिवर्तित नहीं की जा सकती है। जैसे मिल की स्थिर पूंजी अर्थात् मशीन यंत्र, भूमि व बिल्डिंग आदि।

२. कुल परिवर्तनशील लागत-

इन उद्योग में उत्पादक वर्ग की परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो कि परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिये की जाती हैं। कुल परिवर्तनशील लागतें अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन के फलस्वरूप बदल जाती हैं। अर्थात् जब उत्पादन घटता है तो

परिवर्तनशील लागतें घटती हैं और जब उत्पादन बढ़ाया जाता है तो वे बढ़ती हैं, इन उद्योगों में परिवर्तनशील लागतों में श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल की कीमतें व्यय व मेन्टीनेन्स लागत सम्मिलित हैं। कृषि आधारित उद्योगों के उत्पादक वर्ग की कुल परिवर्तनशील लागतों में शोधार्थिनी द्वारा उत्पादक वर्ग की मेन्टीनेन्स लागतों को सारिणी संख्या 6.1 में प्रदर्शित किया जायेगा।

सारिणी 6.1 (अ)

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों में विभिन्न मिलों में नवीनीकरण लागत की परिगणना (1988-99)

क्रम संख्या	नवीनीकरण लागत रुपये में	फर्मों की संख्या	
1	2	3	
1.	0-1000	20	40 प्रतिशत
2.	1000-2000	26	52 प्रतिशत
3.	2000-3000	04	8 प्रतिशत

स्रोत : साक्षात्कार अनुसूची।

टिप्पणी - लघु कोष्ठ में प्रदर्शित संख्या प्रदर्शित कालम संख्या का प्रतिशतांश है।

संदर्भ सारिणी के अनुसार 50 कृषि आधारित उद्योगों में 20 अर्थात् (40 प्रतिशत) मिलों की मेन्टीनेन्स या नवीनीकरण लागत 0-1000 रुपये है। 26 मिलों अर्थात् (52 प्रतिशत) की नवीनीकरण लागत रुपये 1000-2000 रुपये है एवं 4 अर्थात् 8 प्रतिशत मिलों की नवीनीकरण लागत रुपये 2000-3000 रुपये है।

कुल लागत वह लागत है जिसमें किसी फर्म के द्वारा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को पैदा करने के लिये जितना व्यय करना पड़ता है।

कुल लागत -स्थिर लागत +परिवर्तनशील लागत

सारिणी संख्या 6.1 (ब)

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों
में मिलों में उत्पादित वस्तुओं की लागत का परिमाण

क्रम संख्या	वर्ष	लागत(रु०में)
1	2	3
1	1988-89	9246800
2	1989-90	9313200
3	1990-91	15687600
4	1991-92	10319600
5	1992-93	13131200
6	1993-94	9778000
7	1994-95	9005200
8	1995-96	9246800
9	1996-97	16716800
10	1997-98	17168400
	समग्र योग	114673600/ रु०

स्रोत-साक्षात्कार सूची

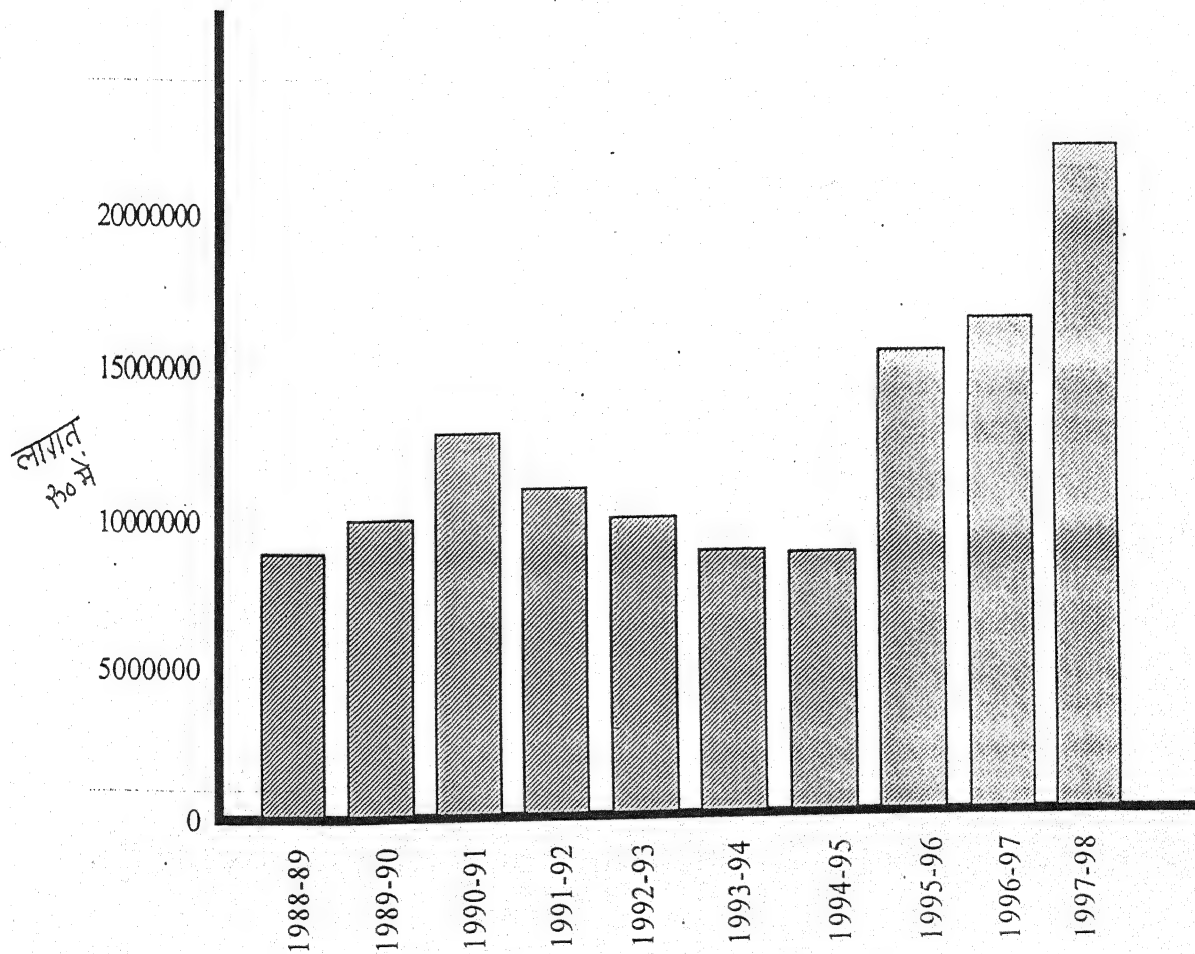
टिप्पणी: कुल-कुल स्थिर लागत+कुल परिवर्तन शील लागत

चित्र संख्या-6.1 बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में मिलों में उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत

संदर्भ सारिणी 6.1 के अनुसार बाँदा जनपद के कृषि-आधारित उद्योग के अर्न्तगत मिलों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन में दस वर्षीय अवधि में वर्ष 1992,94,95 में लागत

सारिणी संख्या 6.1

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों
में मिलों में उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत

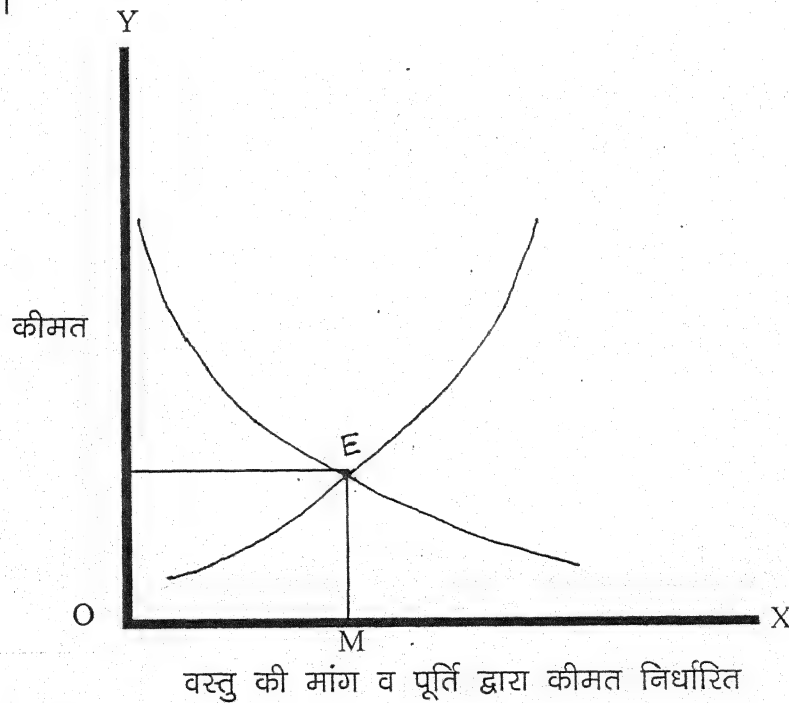


पैमाना 1" = 5000000 रु०

घटी है। बाल्कि सभी वर्षों में लागत में वृद्धि हो रही है। सम्भवतः दस वर्षीय में 1998 अवधि में कृषि आधारित उद्योग में क्रमशः अधिक उत्पादन कार्य हुआ।

6.2 कृषि-आधारित उद्योगों का मूल्य निर्धारण पक्ष-

कृषि आधारित उद्योगों में मूल्य निर्धारण उत्पादन लागत (पूर्ति) तथा उपयोगिता (मांग) द्वारा निर्धारण होता है अतः यहाँ मूल्य निर्धारण वही होता है जहाँ मांग व पूर्ति का सन्तुलन होता है इन उद्योगों में एक कीमत निर्धारित होती है उसी कीमत पर सभी मिले अपना उत्पादन बेचती है। मूल्य निर्धारण की स्थिति को चित्र इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं।



यहाँ कीमत ओ पी पर निर्धारित होती है क्योंकि यहाँ ई सन्तुलन का बिन्दु है यहाँ मांग व पूर्ति बराबर है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि-आधारित उद्योगों में मांग व पूर्ति सन्तुलन पर ही मूल्य निर्धारण होता है। बाँदा जनपद में दाल मिलों में 2390 रु० की 1 कुन्टल दाल बेची जाती है। चावल मिलों में 1200 रु० का 1, कुन्टल चावल बेचा जाता है। तेल मिलों में 2500 रु० में 1 कुन्टल तेल बेचा जाता है। तथा आटा मिल में 800 रु० में 1 कुन्टल आटा

बेचा जाता है। मसाला मिल में 2000 रु0 के हिसाब से मसाला बेचा जाता है। लाही उद्योग में 1000 रु0 1 कुन्टल लाही बेची जाती है। अतः इस प्रकार मिलों में मूल्य निर्धारण किया गया है।

कृषि-आधारित उद्योगों का विक्रय पक्ष -

इन कृषि आधारित उद्योगों में कार्यरत मिलों में उत्पादित का विक्रय जनपद के अन्दर तथा देश विभिन्न शहरों में किया जाता है। इसमें लखनऊ, कानपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद, घाटमपुर आदि प्रमुख हैं। यदि विक्रय मूल्य लागत से अधिक होता है तो लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक उत्पादक का यह उद्देश्य होता है कि उत्पादन को लागत कम से कम रखे और अधिक से अधिक विक्रय मूल्य प्राप्त करे। परन्तु इन मिलों में विक्रय मूल्य लागत से अधिक रहा है। कृषि आधारित उद्योगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विक्रय मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है, बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत 50 मिलों के द्वारा बेचने गये उत्पादन की मात्रा तथा बचेने से प्राप्त विक्रय मूल्य को सारणी संख्या 6.3 में प्रदर्शित किया जा सकता है।

सारिणी संख्या-6.3

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत 50 मिलों के द्वारा बेचे गये उत्पादन की मात्रा तथा उससे प्राप्त विक्रय मूल्य दस वर्षीय अवधि में (1988-98)

क्रम संख्या	वर्ष	बेचे गये उत्पादन मात्रा (कुन्तल में)	उत्पादन से प्राप्त विक्रय मूल्य रुपये में
1	2	3	4
1.	1988-89	22,500	9,67,5,000
2.	1998-90	23,700	10,19,1,000
3.	1990-91	41,900	18,017,000
4.	1991-92	22,900	98,47,000
5.	1992-93	34,200	14,70,6,000
6.	1993-94	24,100	10,36,3,000
7.	1994-95	21700	93,31,000
8.	1995-96	22,500	96,75,000
9.	1996-97	45,000	1,93,50,000
10.	1997-98	21,300	9159000

स्रोत:-साक्षात्कार अनुसूची

उपरोक्त सारणी संख्या 6.3 से स्पष्ट है कि 50 मिलों में सबसे अधिक उत्पादन दसवर्षीय अवधि में सन् 1996-97 में बेचा गया और सबसे अधिक विक्रय मूल्य भी 1996-97 में 19,35,00,000 रु० प्राप्त हुआ। और सबसे कम उत्पादन 197-98 में बेचा गया और सबसे कम विक्रय मूल्य 91,59,000 में प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है

कि मिलों द्वारा उत्पादित माल को जनपद के अन्दर मण्डियों, बाजारों, में तथा जनपद के बाहर अनेक नगरों में बेचा जाता है।

६.४ कृषि-आधारित उद्योगों का आगम पक्ष-

आर्थिक क्रिया में आगम ही उत्पादन का प्रेरक होता है क्योंकि किसी भी उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। चूंकि लाभ उत्पादन लागत तथा विक्रय राशि के अन्तर के बराबर होता है इसलिये अधिकतम लाभ इस लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि यथासम्भव लागत कम की जाये तथा बिक्री अधिकतम हो अर्थशास्त्री आगम को तीन अर्थों में प्रयोग करते हैं।

- 1- कुल आगम।
- 2- औसत आगम।
- 3- सीमान्त आगम।

इस उद्योग के संदर्भ में मुख्य रूप से कुल आगम को ही लिया गया है। एक मिल मालिक अपने उत्पादन की निश्चित मात्रा बेचकर जो कुल धनराशि प्राप्त करती है उसे कुल आगम कहते हैं। या कुल आगम को दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं यदि वस्तु की प्रति ईकाई मूल्य की विक्रय की गई वस्तु की ईकाइयों की कुल संख्या से गुणा कर दिया जाये तो गुणनफल कुल आगम प्रदर्शित करेगा।

कुल आगम - प्रति ईकाई मूल्य वस्तु की बेची गई कुल ईकाइयों की संख्या इस गुणनफल को इस प्रकार रखा जा सकता है।

इस गुणनफल को इस प्रकार रखा जा सकता है - $SP = P_n \times Q_n$

उपरोक्त समीकरण में SP कुल आगम या बिक्रीगत आय क्योंकि आगम का तात्पर्य ही बिक्री गत आय होती है। Q_n बेची गई कुल ईकाइयों की संख्या और P_n प्रति ईकाई मूल्य को प्रदर्शित करता है। यदि प्रति ईकाई औसत आगम की गणना की जाय तो

वह P_n केतुल्य होगी अर्थात्

$$SP_a = \frac{Q_n \cdot P_n}{Q_n} = P_n$$

लेकिन कुल विक्रय आय एस पी अथवा औसत आगम एसपीए कीधारणा महत्वपूर्ण नहीं है जितनी किकुल विशुद्ध आगम की धारणा यहाँ उल्लेखनीय है कि विशुद्ध आगम के परिकलन में कुल आगम में से मिलों द्वारा दी जाने वाली कर राशि घटा दी जायेगी अर्थात्-

$$NSP = Q_n \cdot P_n - t$$

उपरोक्त समीकरण में NSP कुल विशुद्ध आगम है तथा एवं क्रमशः बेची गई इकाईयों की संख्या प्रति ईकाई मूल्य तथा कर राशि है।

बोंदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में मिलों को प्राप्त कुल आगम की दस वर्षीय स्थिति (१९८८-९८)

अध्ययन में प्रस्तुत जनपद में कृषि-आधारित उद्योग में मिलों को प्राप्त कुल आगम की स्थिति को सारणी संख्या 6.4 में प्रदर्शित किया

सारिणी संख्या-6.4

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में मिलों
को प्राप्त कुल आगम की स्थिति(1988-98)

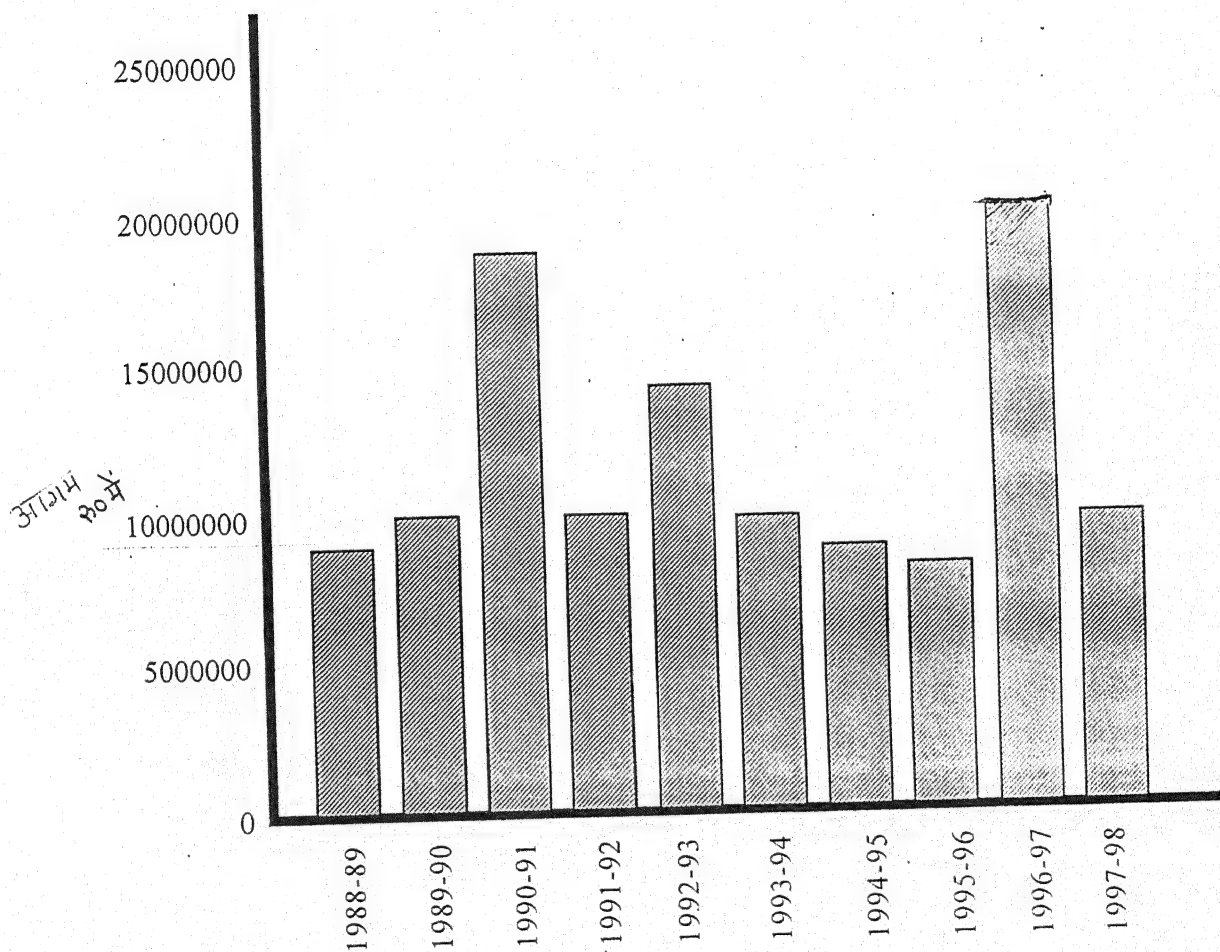
क्रम संख्या	वर्ष	कुल आगम (रु०)
1	1988-89	9675000
2	1989-90	10191000
3	1990-91	18017000
4	1991-92	9847000
5	1992-93	14706000
6	1993-94	10363000
7	1994-95	9331000
8	1995-96	9675000
9	1996-97	19350000
10	1997-98	9159000
	समग्र योग	120314000-रु०

स्रोत्र-साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी कुल आगम -प्रति ईकाई मूल्य × वस्तु की बेची गई कुल ईकाईयों की संख्या चित्र

संख्या-6.4 बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग में मिलों को प्राप्त कुल आगम

चित्र संख्या 6.4
बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग में
मिलों को प्राप्त कुल आगम



पैमाना 1" = 5000000 रु०

संदर्भ सारिणी संख्या-6.4 के अनुसार बाँदा जनपद के कृषि आधारित उद्योग में 50 मिलों की 1988-98 अवधि में क्रमशः 1990, 1991, 1993, 1997 में कुल आगम बढ़ रही है। तथा 1992, 94, 95, 96, 97, 98 में आगम घट रही है। कृषि आधारित उद्योग की 50 मिलों में प्रत्येक को औसतन 22500 रु० का आगम प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ है। जो लागत की तुलना में अधिक है।

अतः सम्पूर्ण सारिणी पर दृष्टि पात करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाँदा जनपद के कृषि-आधारित उद्योग के उत्पादक वर्ग की आय मध्यम स्तरीय है।

सीमान्त आगम-

किसी उद्योग में फर्म द्वारा प्रति ईकाई उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल आगम में होने वाली वृद्धि को सीमान्त आगम का महत्व नहीं है।

अतः आगम की धारणा से स्पष्ट होता है कि जनपद में कृषि आधारित उद्योग लगाना लाभकारी है।

६.५ कृषि-आधारित उद्योगों का प्रतिफल पक्ष-

राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में साहसियों को प्राप्त होता है। लाभ स्वभाव में अवशेष होता है। अर्थात् अन्य सभी साधनों को पुरस्कार देने के बाद कृषि आधारित उद्योग में कार्यरत मिल के मालिकों को जो शेष बचता है वह लाभ है लाभ को दो अर्थों में प्रयोग करते हैं।

1- आर्थिक या विशुद्ध लाभ-

2- कुल लाभ-

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों में दस वर्षीय (१९८८-१९९९) लाभ पक्ष का विरलेखन-

बाँदा जनपद के कृषि आधारित उद्योग के सम्बंध में इस पक्ष पर विचार कर लेना उचित

होगा कि उत्पादन लागत के बावजूद भी इस उद्योग में लाभ की स्थिति क्या है।

लाभ की धारणा एक अर्थ शास्त्रीय धारणा है। इसकी एक सैद्धान्तिक व्यवस्था है सन्दर्भ वश यह कहा जा सकता है कि फर्म के संतुलन विश्लेषण में लाभ कुल आगम और कुल लागत का अन्तर है। लाभ एक उद्योग पति या साहसी को उत्पादन के क्षेत्र में जोखिम उठाने और अनिश्चितता वहन करने के लिये प्राप्त होने वाला प्रतिफल है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में लाभ मापन उसके प्रकृति विश्लेषण की उपरोक्त व्याख्या नहीं ली गयी है। वरन व्यवहारिक रूप से बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग के अन्तर्गत कुल विशुद्ध विक्रयगत आय तथा कुल परिव्यय का अन्तर ही लाभ का मापन होगा।

उपरोक्त दृष्टिकोण से इस उद्योग में प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा दसवर्षीय (1988-98) अवधि में निम्नवत रही है। जिसे सारिणी संख्या 6.5 एवं चित्र संख्या 8.5 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी-6.5

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित
उद्योग में लाभ की परिगणना 1988-98

क्रम संख्या	वर्ष	लाभ(रु० में)
1.	1988-89	4,28,200
2.	1989-90	8,77,800
3.	1990-91	23,29,400
4.	1991-92	- - - -
5.	1992-93	15,74,800
6.	1993-94	5,85,000
7.	1994-95	3,25,800
8.	1995-96	4,28,200
9.	1996-97	26,33,200
10.	1997-98	- - - -
	समग्र योग-	12,72,24, 400 रु०

स्रोत-साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी लाभ -कुल विशुद्ध विक्रयगत आय-कुल परिव्यय

जिन वर्षों में खाने खाली है उसमें हानि हो रही है।

उपरोक्त सारिणी संख्या 6.5 से सुस्पष्ट है कि बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग एक लाभप्रद उद्योग है जनपद में दसवर्षीय (1988-98) अवधि में लाभ की मात्रा सन् 1991,93,94,94-95 में घट रही है। सर्वाधिक लाभ की मात्रा 1996-97 में है 2633200 का 11992-98 में हानि हो रही है। 1992 में 472600 रु० की तथा 1998 में 8009400 रु० की हानि हो रही है।

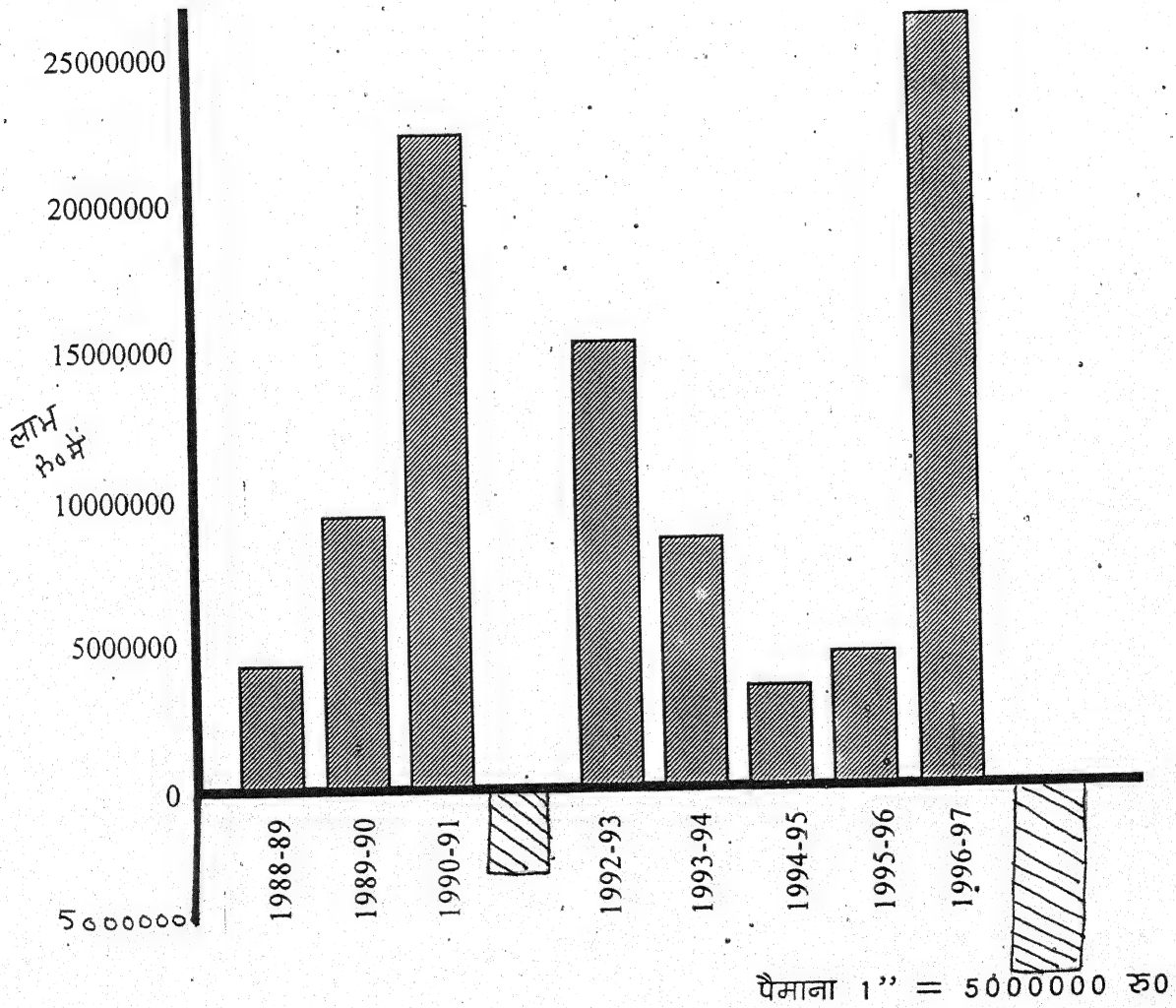
निश्चित रूप में बाँदा जनपद में इस उद्योग के विकास अथवा उत्पादन में लाभोत्पादन की व्यापक सम्भावनायें सन्निहित हैं।

किसी भी उद्योग में लाभ के साथ-साथ हानि भी होती है किन्तु बाँदा जनपद के कृषि आधारित उद्योग में किसी प्रकार की हानि होती ही नहीं है इस प्रकार यहाँ लाभ की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं।

चित्र संख्या-6.5 बाँदा जनपद में संचालित-कृषि आधारित उद्योग में मिलों में लाभ की परिगणना(1988-98)

चित्र संख्या 6.5

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग
में मिलों में लाभ की परिगणना (1988-98)



टिप्पणी- जो खाली वर्ष है उसमें हानि हो रही है। हानि के वक्र त्रिकोणमय
स्थिति में दिखाये गये हैं।



सप्तम अनुक्रम

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों का समस्यात्मक पक्ष

- 7.1 कृषि-आधारित उद्योग की वित्त पोषण पक्ष सम्बंधी समस्यायें।
- 7.2 कृषि-आधारित उद्योगों की प्रशासनिक पक्ष सम्बंधी समस्यायें।
- 7.3 कृषि-आधारित उद्योग की कच्चा माल एवं रम आपूर्ति पक्ष की समस्यायें।
- 7.4 कृषि-आधारित उद्योग की शक्ति के साधन सम्बंधी समस्यायें।
- 7.5 कृषि-आधारित उद्योग की प्रबंधकीय समस्याये।

सप्तम अनुक्रम-

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों का समस्यात्मक पक्ष-

बाँदा जनपद में संचालित उद्योग अनेक समस्याओं से घिरे हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से बाँदा नगर के इस उद्योग की समस्याओं की निम्न मांगों में विभाजित कर सकते हैं।

1. कृषि-आधारित उद्योगों की वित्त पोषण पक्ष की समस्यायें।
2. कृषि-आधारित उद्योगों की प्रशासनिक पक्ष की समस्यायें।
3. कृषि-आधारित कच्चा माल एवं श्रम आपूर्ति पक्ष की समस्यायें।
4. कृषि-आधारित शक्ति के साधन की समस्यायें।
5. कृषि-आधारित प्रबंधकीय समस्याये।

9.9 कृषि-आधारित उद्योगों की वित्त पोषण पक्ष की समस्यायें।

- 1- बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योग में मालिकों या प्रबंधकों के पास वित्त की समुचित व्यवस्था नहीं है। नई विधियों से उत्पादन करने के लिये आवश्यकतानुसार पूंजी न होने के कारण अधिकांश फर्म के प्रबंधक धनाभाव के कारण मिलों में पुरानी मशीनों एवं विधियों का प्रयोग करते हैं। जिससे फर्म की उत्पादन क्षमता घट जाता है।
- 2- सरकार की ओर से इन उद्योगों में लगी व्यक्तियों के लिये अनुदान या कम ब्याज पर धन की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण फर्म के प्रबंधकों की वित्त सम्बंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- 3- यदि सरकार वित्त की कोई व्यवस्था करती भी हैं तो स्थानीय बैंकों की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया लम्बी होती है जिससे इन उद्योगों के प्रबंधक इस सुविधा का लाभ सही समय पर नहीं उठा पाते हैं।
- 4- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता उचित व्यक्तियों को नहीं मिल पाती है यह लाभ उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जिनकी बैंक के अधिकारियों एवं अनुदान प्रदान करने वाले अधिकारियों के पास पहुँच हैं।
- 5- सरकार द्वारा वित्तीय सहायता न मिलने के कारण उद्योगों के प्रबंधक महाजनों एवं साहूकारों से ऋण या वित्त प्राप्त करते हैं जिनकी ब्याज दर बहुत ऊँची होती है इसलिये उत्पादक अच्छी प्रकार से विकास नहीं कर पाते हैं।

७.२-कृषि-आधारित उद्योगों की प्रशासनिक पक्ष की समस्याएँ-

बाँदा जनपदमें कृषि-आधारित उद्योग में प्रशासनिक सम्बंधी निम्नलिखित समस्याएँ होती हैं।

1. जिला उद्योग केन्द्र से अपनी रजिस्ट्रेशन कराने में असुविधा होती हैं
2. प्रशासन की ओर से कृषि आधारित उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
3. सरकार की ओर इन उद्योगों के सम्बंध में कोई नीति नहीं बनाई गयी जिसका लाभ इन उद्योगों को मिल सके।
4. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इन कृषि-आधारित उद्योगों के मालिकों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है किसी काम के लिये मिल मालिकों जिला उद्योग केन्द्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

७.३-कृषि-आधारित उद्योगों को कच्चा माल एवं श्रम आपूर्ति पक्ष की समस्याएँ-

बाँदा जनपद के कृषि-आधारित उद्योगों में कच्चा माल एवं श्रम आपूर्ति पक्ष सम्बंधी निम्नलिखित समस्याएँ।

1. इन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल अब पर्याप्त मात्रा में जनपद में उपलब्ध न होने के कारण उत्पादकों या प्रबंधकों को कच्चा माल अन्य नगरों से मगाना पड़ता है। जिससे उत्पादकों को कच्चा माल मंगाने में अधिक लागत और अधिकसमय लग जाता है। अतः नये उद्यमी हतोत्साहित होते हैं।
2. सरकार कच्चा माल सस्ती दर पर उपलब्ध भी कराती है तो इसकी सुविधा प्रत्येक मिल मालिकों को नहीं मिल पाती है।
3. कच्चा माल लाने के लिये उचित परिवहन का साधन नहीं है।
4. इन उद्योगों के लिये अगर जनपद के अन्दर कच्चा माल मिल भी गया तो वो अच्छी किस्म का नहीं होता है। जिससे उत्पादन विधायन में असुविधा होती है।
5. जनपद में प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी है इन उद्योगों में मजदूरी कम होने पर शिक्षित बेरोजगार रूचि नहीं लेते हैं।
6. इन उद्योगों में श्रमिकों के जिलों का ध्यान नहीं रखा जाता है कम मजदूर पर अधिककाम लिया जाता है।
7. इन उद्योगों में श्रमिकों को आवास की सुविधा भी नहीं दी जाती है
8. इन उद्योगों में श्रमिकों का वेतन भी छूट्टी लेने पर काट लिया जाता है।

७.४-कृषि-आधारित उद्योगों व शक्ति के साधनों की समस्याएँ-

बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योगों के समक्ष शक्ति के साधनों की समस्याएँ भी

अपना मुहँ बाये खड़ी है शक्ति के साधनों से सम्बंधी समस्यायें निम्नलिखित हैं।

1. विद्युत आपूर्ति बीच-बीच में बन्द हो जाने से मशीन सुचारु रूप से नहीं चल पाती है जिससे उत्पादन कम होता है।
2. जल की आपूर्ति भी इन उद्योगों बराबर नहीं मिल पाती है जिससे समस्या उत्पन्न होती है।
3. कुछ मशीने जो इन उद्योगों में उपयोग की जाती हैं वो डीजल से चलती हैं उनके लिये पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिल पाता है।
4. सरकार विद्युत की आपूर्ति में ध्यान नहीं दे रही है दिन व रात किसी समय जनपद में विद्युत की कटौती होती है जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है।
5. मशीने को सुचारु रूप से चलाने के लिये जनपद के अन्दर तकनीकी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं।

७.५-कृषि-आधारित उद्योगों की प्रबंधकीय समस्यायें-

बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों की निम्नलिखित प्रबंधकीय समस्यायें हैं जो इस प्रकार हैं।-

1. इन उद्योगों का प्रबंध ठीक से नहीं किया जाता है जिससे उद्योग को चलाने में असुविधा होती है
2. ये उद्योग अधिकतर निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं इसलिये स्वामित्व होता है।
3. सरकार इन उद्योगों को में कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है।
4. जनपद में ये उद्योग में दो या चार व्यक्तियों होते हैं जो पूरी फर्म को चलाते हैं किसी फर्म केवल एक मालिक व एक श्रमिक होता है जिससे उत्पादन सुचारु से नहीं हो पाता है इस ओर सरकार ध्यान नहीं जा रहा है।

5. प्रबंध में श्रमिकों की संख्या कम होती है जिससे उनसे अधिक काम लिया जाता है और काम न करने पर निकाल दिया जाता है।
6. प्रबंध व्यवस्था को चलाने में इन उद्योगों प्रबंध को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अन्य समस्याएँ-बाँदा जनपद में इन उद्योगों में अन्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1. परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में न होने से कच्चा माल लाने में असुविधा होती है।
2. जनपद में प्रशिक्षण की सुविधा न होने से श्रमिकों को असुविधा होती है।
3. नगर के कृषि-आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिये शोध कार्य की आवश्यकता है सरकार द्वारा शोधार्थिनी को कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

उपरोक्त समस्याओं के संदर्भ में शोधार्थिनी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची द्वारा उद्योगों के प्रबन्धकों से उनकी जानकारी प्राप्त की है। सारिणी 7.1 एवं चित्र संख्या 7.1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या-7.5

बाँदा जनपद में संचालित कृषि-आधारित उद्योगों के
प्रबंधकों द्वारा अनुभावित कठिनाईयाँ

क्रमसंख्या	सौविध्य	हाँ	नहीं
1	कच्चा माल समस्या	20	30
2	श्रमिक समस्या	5	45
3	प्रशासनिक समस्यायें	10	40
4	वित्तीय समस्यायें	30	20
5	विद्युत आपूर्ति समस्यायें	40	10
6	अन्य समस्यायें	02	04

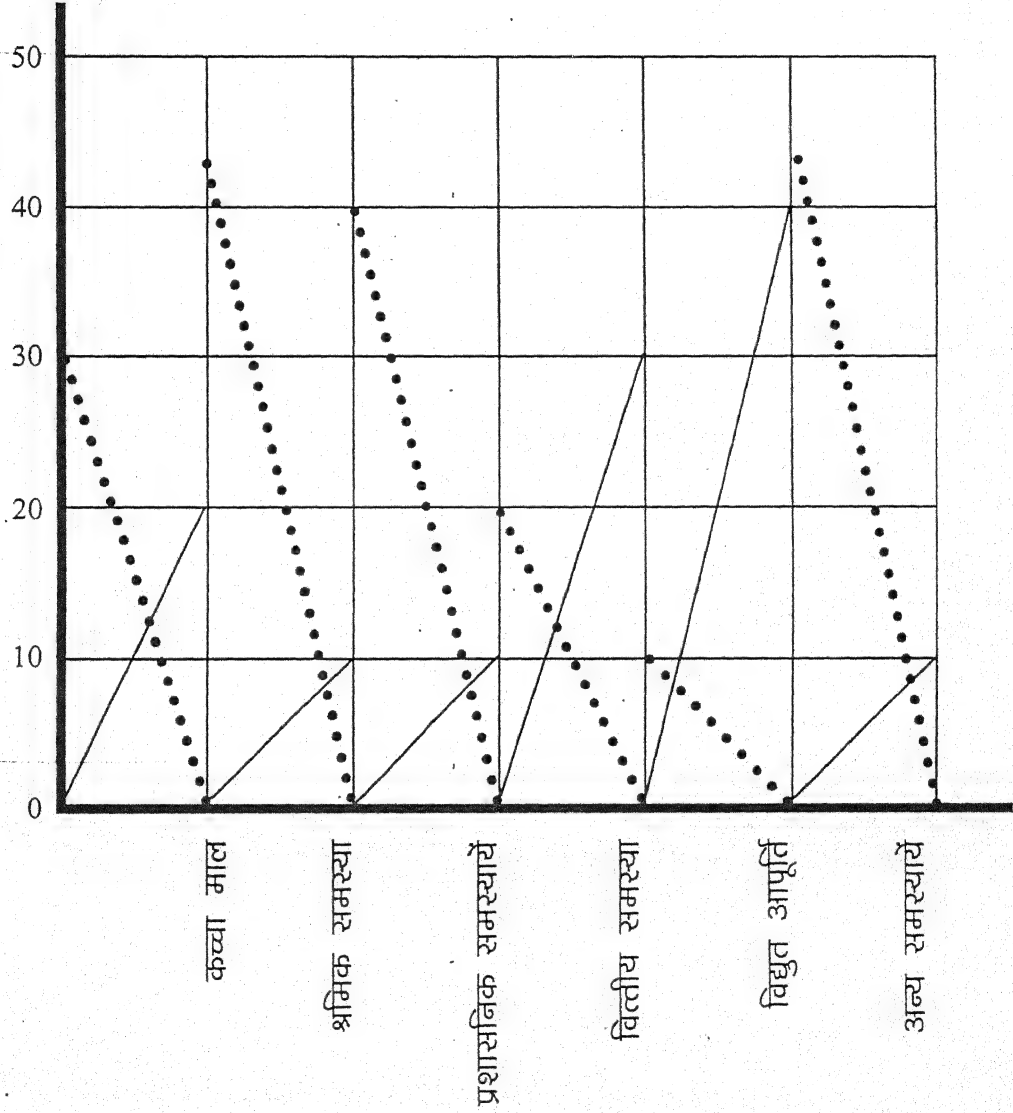
स्त्रोत-साक्षात्कार अनुसूची

चित्र संख्या 7.5 बाँदा नगर के केन्द्र आधारित उद्योग फर्मों द्वारा अनुमानित कठिनाईयाँ
सारिणी संख्या 7.5 में जनपद की 50 मिलों में समस्याओं को हाँ/नहीं में व्यक्त किया
गया है। जनपद के कृषि आधारित उद्योग में सर्वाधिक 40 मिलों को विद्युत की समस्या है।

सारिणी संख्या-7.5

बाँदा नगरमें कृषि-आधारित उद्योग

फर्मों द्वारा अनुमानित कठिनाइयाँ



निर्देशिका

हॉ	• • • • •
नहीं	—



अष्टम अनुक्रम

8.1 निष्पादन एवं समस्याओं का मूल्यांकन

8.2 अध्ययनगत निष्कर्ष बिन्दु

8.3 कतिपय सम्भवित कृषि-आधारित उद्योगों के नियोजन हेतु सुझाव

8.4 प्रवर्तमान स्थिति हेतु सुझाव

8.5 अग्रामी शोध की दिशाएँ

अष्टम अनुक्रम-

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्पादन एवं समस्याओं का मूल्यांकन -

बाँदा जनपद में संचालित उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसी भी अनुसंधान में समस्याओं का मूल्यांकन व समीक्षा करना उत्पन्न आवश्यक है क्योंकि मूल्यांकन के मध्यम से ज्ञात हो सकता है कि मिल मालिकों द्वारा बतायी गयी समस्यायें वास्तविकता में हैं कि केवल दिखावटी रूप में हैं। और कौन सी समस्यायें वास्तविकता में हैं कि केवल दिखावटी रूप में हैं। और कौन सी समस्यायें उद्योगों के उत्पादन में अधिक बाधक हो रही हैं। तथा किन समस्याओं के द्वारा उत्पादन ऋणात्मक हो रहा है। अतः मिल मालिकों द्वारा बतायी गयी समस्याओं का मूल्यांकन इस प्रकार से करते हैं। और उन समस्याओं के सम्बंध में सुझाव भी प्रस्तुत हैं।

- 1- बाँदा जनपद में संचालित कृषि उद्योग में कार्यरत मालिकों से ज्ञात हुआ कि उनकी प्रमुख समस्या कच्चे मालकी है कि उनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है ये समस्या मिल मालिकों के समक्ष वास्तविक रूप में। क्योंकि पहले जनपद में कृषि आधारित उद्योग कम थे तो कच्चा माल आसानीसे मिल जाता था परन्तु अब इनकी संख्या बढ़ जाने से कच्चा माल मिलने में कठिनाई हो रही है कच्चा माल न मिलने से मिलों का उत्पादन घट रहा है।

कच्चा माल की समस्या को अन्य पास के नगरों से कच्चा माल मंगाकर दूर किया जाये तथा कृषकों को चावल दाल तथा लाही को उत्पादन बढ़ाना चाहिये जिससे मिल मालिकों को कच्चा माल मिल सके।

- 2- बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग के अर्न्तगत कार्यरत करना पड़ता है। वित्त की समस्या का सामना करना पड़ता है। वित्त की समस्या इस उद्योग के लिये

वास्तविक समस्या नहीं है। क्योंकि आजकल उद्योगों के लिये सरकार ने वित्तीय व्यवस्था के लिये इतनी योजनाओं शुरू कर दी जिनके मध्यम से ऋण प्राप्त करके वित्त की समस्या को दूर किया जा सकता है। वैसे ये समस्या अब इन उद्योगों में कम हो रही है।

- 3- बौदा जनपद में इस उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत मिलों के मालिकों के समक्ष श्रम आपूर्ति की समस्या है जो श्रमिक मिलते भी हैं वो निरक्षर होते हैं अतः उत्पादन कार्य को ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनको इन मिलों में उपयोग होने वाली मशीनों को चलाने में परेशानी वाली मशीनों को चलाने में परेशानी होती क्योंकि उनको तकनीकी ज्ञान नहीं होता है ये समस्या वास्तविकता में इन उद्योगों के समक्ष है क्योंकि इन जनपद के अन्दर जो श्रमिक मिलते भी हैं तो वे पूर्ण रूप से निरक्षर होते हैं। इसका प्रभाव उत्पन्न पर भी पड़ता है। वैसे अब ये समस्या कम हो रही है क्योंकि आजकल धीरे-धीरे शिक्षित श्रमिक आसानी से कम मजदूरी पर मिल जाते हैं।

इस समस्या को श्रमिकों को प्रशिक्षित करके दूर कर सकते हैं तथा श्रमिकों उनके अनुसार मजदूरी देकर उन्होंने आवास की सुविधा देकर इस से छुटकारा पाया जा सकता है।

- 4- इस उद्योग में कार्यरत मिल मालिक द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके समक्ष शक्ति के साधनों की समस्या है। क्योंकि विद्युत आपूर्ति जनपद के अन्दर बीच-बीच में बन्द हो जाती है। इससे उत्पादन कार्य रुक जाता है ये समस्या वास्तविक रूप से मिल मालिकों के समक्ष है क्योंकि जनपद में विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं और विद्युत के बिना मशीन नहीं चल पाती है और उत्पादन कार्य रुक जाता है जल आपूर्ति भी ठीक न होने से उत्पादन कार्य सुचारु रूप उसे नहीं हो जाता है। वैसे अब

ये समस्या कम हो रही है क्योंकि अधिकतर मिल मालिक जनरेटर द्वारा विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। वैसे भी इस समस्या को बड़े हार्स पावर का जनरेटर लगाकर दूर किया जा सकता है।

- 5- इस उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत मिल मालिकों के समक्ष प्रशासनिक समस्याओं भी उत्पन्न हो जाती हैं जैसे जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रेशन करने में असुविधा होती है। तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने में जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी मदद नहीं करते हैं तथा ठीक से हपरामर्श नहीं देते हैं तथा इनको रजिस्ट्रेशन करने में असुविधा होती है।

इस समस्या की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये तथा प्रशासन ठीक करना चाहिये तथा इन उद्योगों के सम्बंध में कोई नीति बनानी चाहिये।

- 6- इन उद्योग में कार्यरत मालिकों के समक्ष प्रबंधकीय समस्याये भी हैं। क्योंकि इन उद्योगों में प्रबंध व्यवस्था ठीक है। अधिकतर मिल निजी स्वामित्व में चल रही हैं जनपद के अन्दर सभी मिले निजी स्वामित्व में चल रही हैं कोई भकी सरकार के हसतक्षेप नहीं है एक मवई मिल थी जो अब बन्द चल रही है।

अतः निजी स्वामित्व में चलाने के कारण मिल मालिक में चलाने के कारण मिल मालिक स्वयं प्रबंधक का कार्य करते हैं। और अपने हिसाब से मिलों की प्रबंध व्यवस्था चलाते हैं जिससे उत्पादन कार्य है सभी कार्य स्वयं देखते हैं इसी कारण श्रमिक भी असंतुष्ट रहते हैं। क्योंकि मिल मालिक उनको कार्य के अनुसार वेतन भी नहीं देते हैं ये समस्या वास्तविक नहीं हैं। इस समस्या को मिल मालिक अपनी प्रबंध व्यवस्था ठीक कर सकते हैं।

- 7- इसके अतिरिक्त मिल मालिकों को परिवहन और विपणन की समस्या है परिवहन के लिये उपयुक्त साधन न होने से कच्चा लाने व तैयार माल बेचने में कठिनाई

होती है। ये समस्या वास्तविक रूप में है।

अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये तहसीलों व विकास खण्डों में मण्डियों की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे तैयार माल वहाँ बेचा जा सके और उत्पादकों को नगर से दूर न चाना पड़े तथा परिवहन के लिये तहसीलों व विकासखण्डों से नगर तक उपयुक्त साधन की व्यवस्था करनी चाहिये।

इस प्रकार बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योगों के समक्ष उपस्थित समस्याये ऋणात्मक है जो दिनों दिन कम हो रही है। कच्चे माल की समस्या, विद्युत समस्या, प्रशासनिक समस्यायें, श्रम आपूर्ति, समस्याये वास्तविकता में इन मिलों मालिकों के समक्ष है। इन समस्याओं की ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिये।

६.२-अध्ययनगत निष्कर्ष-बिन्दु-

किसी अध्ययन का महत्व उसके मूल निष्कर्षों में निहित होता है। किसी भी अनुसंधान अध्ययन का अन्तिम चरण निष्कर्ष एवं सुझावों से अभिवृत्त होता है किसी भी अनुसंधान का निष्कार्णात्मक होना उसकी सफलता की सवार्धिक महत्वपूर्ण कसौटी है। अन्य व्यवसायो और क्षेत्रों बाँदा जनपद में भी कृषि आधारित की कार्यरत ईकाईयो है। उत्पादन कार्यों के संदर्भ में विशेष रूपसे लाभान्वित है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध भी एक निष्कार्णात्मक अध्ययन है पूर्व वर्णित अध्यायों के आधार पर “बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि आधारित औद्योगिकरण” अनुसंधान समस्या से उद्भूत प्रमुख निष्कर्षों को निम्नवत सुत्रबद्ध संजोया जा सकता है-

1. बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल आसानी से जनपद के अन्दर अब नही उपलब्ध हो पा रहा है इस लिये अधिकतर दाल, चावल मिले अब बन्द हो रही हैं। क्योंकि मिल मालिकों को कच्चा माल जनपद के बाहर आसपास के नगरों से मंगाना पड़ता है। जिससे उत्पादक वर्ग को यातायात में

अतिरिक्त धन व्यय तथा समय दोनों की हानि होती है।

2. कृषि-आधारित उद्योग का उत्पादन निष्पादन कोई खास वृद्धि नहीं हुयी हैं दस वर्षों में एक दो वर्षों को छोड़ कर उत्पादन घट रहा है। उत्पादन कम होने का कारण प्रबंध ही न होना तथा वित्तीय व्यवस्था सही न होना।
3. बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योगों में वेतन मजदूरी कम मिलने के कारण श्रमिक वर्ग इस उद्योग की अपेक्षा अन्य उद्योगों में कार्य करना अधिक उचित समझते है। जिसमें उनको कृषि आधारित उद्योग की तुलना में अधिक श्रम मूल्य प्राप्त होता है।
4. बाँदा जनपद के कृषि आधारित उद्योग में उत्पादकों को उत्पादन की लागत की अपेक्षा या तुलना में प्राप्त आगम की मात्रा लागत से कुछ ही अधिक है क्योंकि उत्पादक को कच्चा माल बाहर से उपलब्ध होने के कारण उत्पादन के लिये लागत अधिक लगानी पड़ती है। जबकि बिक्री से उनको आगम की प्राप्ति कम होती है।
5. बाँदा जनपद में बेरोजगारी, गरीबी, कृपोषण एवं भुखमरी जैसी ज्वलन्त समस्यायें विद्यमान है। इन समस्याओं का समाधान करने में कृषि आधारित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
6. बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग की मिलों में आज भी पुरानी व घटिया किस्म की मशीनों का प्रयोग हो रहा है। जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है।
7. सामान्यतः जनपद के कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत श्रमिक एवं उत्पादक मालिक में कोई अन्तर नहीं है क्योंकि इस लघु उद्योग में उत्पादक स्वयं ही अधिकतर कार्य करते है।
8. बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योग में कार्यरत मिलों मालिकों को वित्तीय

सहायता नहीं हो पाती हैं। अतः उनके पास वित्त व पूंजी का अभाव रहता है।

9. इस उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिक अशिक्षित होते हैं। जो उत्पादन कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं।
10. बाँदा जनपद का अधिकतर श्रमिक इस उद्योग में रोजगार में लगा है।
11. बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योग में मितव्यितायें अधिक हैं क्योंकि निकले कचड़े का वैकल्पिक प्रयोग हो जाता है जैसे दाल की भूसी जानवर खाते हैं।
12. बाँदा जनपद के कृषि आधारित उद्योग में कार्यरत मालिकों को उत्पादन कार्य में लागत अधिक लगाने एवं प्राप्त आगम की मात्रा कम होने के कारण केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा है।
13. अन्त में कृषि-आधारित उद्योग जनपद के अर्थिक विकास में सहायक है।

८.3-कतिपय सम्भावित कृषि-आधारित उद्योगों के नियोजन हेतु सुझाव-

बाँदा जनपदमें कृषि पर आधारित और भी उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ये जानकारी शोधार्थीनी द्वारा कृषि आधारित मिलों के मालिकों से जानकारी प्राप्त कीगयी कृषि पर आधारित कई उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं जैसे-बोसन मिल, आवले के प्रोडक्ट्स, सोयाबीन प्रोडक्ट्स बेकरी/ब्रेड, टमाटर के पेस्ट केचअप, आम की खटाई बनाना, आयुर्वेदिक दवाये बनाना, बांस के सजावटीह समान, पिसे मसाले, कालीन बनाना, अदरक की प्रोसेसिंग, बास की डलिया बनाना, खाण्डसारी उजोगन मशरूम उगाना आदि। इन उद्योगों के द्वारा जनपद के आर्थिक विकास किया जा सकता है। साथ इन उद्योगों की स्थापना से जनपद में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है, कतिपय सम्भावित कृषि आधारित उद्योगों के नियोजन हेतु सुझाव इस प्रकार है।

1. कृषि आधारित उद्योगों स्थापित करने के लिये सर्वप्रथम भूमि की व्यवस्था करनी

चाहिये।

2. उद्योग कीपरियोजना का अस्थायी पंजीकरण जिला उद्योग के माध्यम से कराना चाहिये।
3. कृषि-आधारित सम्भावित उद्योग स्थापित करने के लिये कार्यशील पूंजी के लिये बैंको में आवेदन करना चाहिये।
4. कृषि आधारित सम्भावित उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायताके लिये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा बैंको में जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से आवेदन करें।
5. इन उद्योग की स्थापना करने के पावर कनेक्शन के लिये आवेदन करें।
6. कृषि-आधारित सम्भावित उद्योग स्थापित करने के लिये कच्चे माल की आपूर्ति की व्यवस्था सर्वप्रथम करे।
7. कृषि आधारित सम्भावित उद्योग स्थापित करने के लिये जल आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिये।
8. कृषि आधारित सम्भावित उद्योग स्थापित करने के लिये अच्छे किस्म की मशीने मंगानी चाहिये।
9. कृषि आधारित सम्भावित उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोद्योगिकी/प्रक्रिया से सम्बंधित विशेष जानकारी एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय प्रोद्योगिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ से प्राप्त करे।
10. इन उद्योगों में कुशल श्रमिकों की भर्ती करनी चाहिये जो उत्पादन कार्य ठीक से कर सके।
11. इन उद्योगों के लिये वैधानिक लाइसेन्स क्लीयरेंस प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य सम्बंधित विभाग से प्राप्त कर लें

अतः उपरोक्त नियोजन सुझावों को ध्यान में रखकर उपरोक्त बताये गये उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये।

८.४-प्रवर्तमान स्थिति हेतु सुझाव-

किसी भी उद्योग स्थितियों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी विकास भी उत्पादन कार्य को श्रेष्ठ एवं कम लागतशील बनाने में अत्यन्त उपयोगी है। तथा वित्तीय व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिये। अतः बाँदा जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग की स्थितियों में निम्न लिखित सुझाव द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है।

1. सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योग में कार्यरत मिल मालिकों तकनीकी विकास के लिये जैसे-अच्छे किस्म की अधिक क्षमता वाली मशीनें खरीदने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाये।
2. मिल मालिकों को नयी तकनीकी वाली मशीनों का प्रयोग करना चाहिये जिससे उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके।
3. जनपद में संचालित कृषि आधारित उद्योग में कार्यरत मिल मालिकों को समय-समय पर हो रहे तकनीकी परिवर्तन की सूचना एवं ज्ञान की जानकारी दी जाये।
4. इस उद्योगों के लिये कच्चा माल कम लागत पर सरकार को उपलब्ध कराना चाहिये।
5. बाँदा जनपद में श्रमिकों मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इसके लिये जिले में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाये।
6. मिल मालिकों को अपनी मिलों अच्छे किसम व अधिक क्षमता वाली मशीनें लगाना चाहिये वाली मशीनें लगाना चाहिये जिससे उत्पादन क्षमता बढ़े सके।
7. मिल मालिकों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिये।

8. मिल मालिकों को अपनी प्रबंध व्यवस्था भी ठीक रूप में चलानी चाहिये।

9. जनपद के अन्दर कुशल इंजीनियरों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये जिससे मशीने खराब हो जाने पर जनपद के अन्दर मिल मालिक मशीने ठीक करा सकें।

उपरोक्त बताये गये सुझाव के द्वारा स्थितियों में परिवर्तन करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

८.५-अग्रामी शोध की दशाये-

प्रस्तुत शोध बाँदा जनपद के आर्थिक विकास में कृषि आधारित औद्योगिकरण प्रबंध में कृषि आधारित उद्योग की अवस्थिति निष्पादन समस्याओं एवं सम्भवनाओं का सर्वेक्षण तथा विश्लेषण किया गया है। जिसमें इन उद्योग की उत्पादन स्थिति, वित्तीय पक्ष, प्रबंध श्रम संरचना, लाभ हानि, लागत आगम, का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। इसके आगे भी इस विषय से सम्बंधित विषयों पर शोध कार्य किया जा सकता है। अग्रामी शोध के विषय निम्न लिखित हो सकते हैं।

1. बाँदा जनपद के कृषि-आधारित औद्योगिकरण का लागत आगम का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
2. बाँदा जनपद के कृषि-आधारित औद्योगिकरण के वित्तीयपक्ष का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन।
3. बाँदा जनपद के कृषि-आधारित औद्योगिकरण का लाभ-हानि का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन।
4. बाँदा जनपद में दाल मिलों की समस्याओं का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन।

इस प्रकार उपरोक्त पर शोध कार्य किया जा सकता है। परन्तु शोध कार्य करने पूर्व से अवश्य देख लेना चाहिये शोध विषय से सम्बंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है कि नहीं और उपरोक्त विषयों पर शोध करके कृषि आधारित उद्योग को ओर उन्नति के शिखर पर पहुँचाया जा सकता है



परिशिष्ट

- अ. ३०प्र० सरकार की औद्योगिक नीति
- ब. जिला उद्योग केन्द्र एवं कृषि-आधारित उद्योग
- स. कृषि-आधारित उद्योगों में शोध में अनुसंधान
- द. कृषि-आधारित उद्योग एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण
- य. कतिपय महत्वपूर्ण सारणियां
- श. साक्षात्कार अनुसूची

परिशिष्ट-

अ:- उ०प्र० सरकार की औद्योगिक नीति

ब:- जिला उद्योग केन्द्र एवं कृषि आधारित उद्योग

स:- कृषि आधारित उद्योगों में शोध में अनुसंधान

द:- कृषि आधारित उद्योग एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण

स:- कतिपय महत्वपूर्ण सारणियाँ

अ-उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति,

उ० प्र० सरकार द्वारा की गयी औद्योगिक नीति इस प्रकार है।

- 1- लघु रुग्ण इकाईयों के पुनर्जीवित करने हेतु राज्य स्तरीय पुनर्वासन बोर्ड गठित करने की घोषणा।
- 2- 100 बैटरी चालित तिपहिया वाहनों की बिक्री पर व्यापार कर छूट।
- 3- सूचना प्रौद्योगिक के विकास हेतु सॉफ्टवेयर उद्योग में महिला कर्मचारियों को 5 बजे के बाद काम करने की अनुमति।
- 4- फ़शर समाधान योजना में फ़शर स्वामी द्वारा अब केवल एक बार स्वेच्छा से मंडी शुल्क लेने का निर्णय।
- 5- राज्य वित्तीय निगम के अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहीत ईकाईयों की बिक्री करने पर वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही स्टैम्प शुल्क लिये जाने का निर्णय।
- 6- उद्योगों के आवेदन पत्र पर एक सप्ताह के अन्दर विद्युत भार स्वीकृत सम्बंधी निर्णय अनिवार्य रूप से लिये जाने की व्यवस्था के निर्देश।
- 7- निर्यातक ईकाईयों को पूरा संरक्षण और प्रोत्साहन।
- 8- वर्ष 1994 से जिन चावल उद्योगों के विरुद्ध मण्डी परिषद द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ

की गई है उसे तत्काल प्रभाव से वापस किये जाने की घोषणा।

9- नये उद्योगों को त्वरित गति से विद्युत भार स्वीकृत किये जाने के अधिकारों का तत्काल प्रभाव से आसान स्तरों पर प्रतिनिधायन का निर्णय।

10- कृषि उद्योग पार्क विकसित किये जाने के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी सुधार के मार्ग खुलेंगे तथा उत्पादित खाद्य सामग्री के निर्यात की व्यवस्था भी अतिकाधिक सुगम हो सकेगी।

11- उद्योग विभाग द्वारा चयनित 17 जनपदों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों जिनमें 32 के. वी. ए. से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। में 24 घण्टे निर्वाध विद्युत आपूर्ति।

12- फीडरो विद्युत सब स्टेशन के निर्णय के लिये सुपर विजन चार्ज 36.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत नई औद्योगिक विकास नीति के क्रियान्वयन 12 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ब-जिला उद्योग केन्द्र एवं कृषि-आधारित उद्योग-

वर्तमान बदलते हुये आर्थिक परिवेश एवं जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते हुये दबाव में सभी को नौकरी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। जिला उद्योग केन्द्र युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने में परामर्श देता है कृषि आधारित को जो सहयोग जिला उद्योग केन्द्र दिया है। वह इस प्रकार है।

- 1- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कृषि-आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 2- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कृषि आधारित उद्योगों को पंजीकरण कराने की सुविधा रहती है।
- 3- कृषि-आधारित उद्योग लगाने में आवश्यक 100 अश्व शक्ति तक के विद्युत भार की जिला स्तर पर जिला उद्योग बन्धु माध्यम से स्वीकृति की जाती है।

- 4- उद्यमियों की कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिये जिला उद्योग केन्द्र परामर्श देती है।
- 5- कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यमी को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भूमि की भी व्यवस्था करायी जाती है।
- 6- युवा वर्ग प्रशिक्षित वर्ग एवं प्रबंधकीय योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को इन उद्योगों की ओर वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाओं के द्वारा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आकर्षित किया जाता है।

स-कृषि-आधारित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान-

किसी भी विषय पर जब अधिक शोध एवं अनुसंधान होता है तभी इस बात की जानकारी होती है कि उस विषय के सम्बंध में क्या समस्याएँ क्या कमियाँ हैं जिसे दूर किया जा सके। बाँदा जनपद में कृषि आधारित उद्योगों के सम्बंध में अभी तक कोई शोध एवं अनुसंधान नहीं हुये हैं। हुये भी हैं तो वह सूक्ष्म के बराबर हैं। इसलिये इन कृषि आधारित उद्योगों का जनपद में अधिक विकास नहीं हुआ है। जो उद्योग हैं भी उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है उनको नयी तकनीकी क्षमता बहुत कम है उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है उनको नयी तकनीकी की कोई जानकारी नहीं है।

अतः कृषि आधारित उद्योगों के सम्बंध में शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। जिससे इन उद्योगों का विकास हो सकें।

द-कृषि-आधारित उद्योग एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण-

आज विकासशील राष्ट्रो के समक्ष प्रमुख समस्या पर्यावरण प्रदूषण की है ओजोन पर्त के निरंतर क्षरण से कल कारखानों से उड़ते हुये धुएँ से इनसे निकले हुये अवशिष्ट विषैले पदार्थों के नदियों में प्रवाहित होने के कारण वनों का निरंतर कटाव एवं भूमि क्षरण से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है।

हमें विकास चाहिये औद्योगिकरण चाहिये लेकिन हमें मानव और पर्यावरण साहचर्य वादी न्यूनतम प्रदूषण जनित वैकल्पिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया चाहिये।

कृषि आधारित औद्योगिकरण में पर्यावरण प्रदूषण कम फैलता है क्योंकि जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उसका उपयोग हो जाता है। अतः कचरे इत्यादि के नदी जल में विलय की संभावनाये कम होती है। और इन उद्योगों में धूम जनन अल्प होता है। और बाँदा जनपद में अधिकतर एफ कृषि आधारित उद्योगों में (मिलों में) प्रदूषण नियंत्रण इस सयन्त्र लगा है।

निष्कर्षतः इस प्रकार कृषि आधारित उद्योग से प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन की संभावनाये अल्प होती है। अतः इन उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित रहता है।

(य)

कतिपय महत्वपूर्ण सारणियां
बाँदा जनपद में कृषि-आधारित उद्योगों
में स्वामित्व के प्रकार

क्रम संख्या	स्वामित्व के प्रकार	फर्मों की संख्या	
1.	सोप्रोपाइटर	43	(84.00 प्रतिशत)
2.	पार्टनरशिपन	8	(16 प्रतिशत)
	समग्र योग	50	(100 प्रतिशत)

स्रोत साक्षात्कार अनुसूची

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में प्रदर्शित संख्या सम्बन्धित कालम का प्रतिशतांश है।

जनपद में विकास खण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

क्रम संख्या	वर्ष	कृषक	कृषि श्रमिक	उद्योग खान खोदना
1	2	3	4	5
1.	1971	226650	126376	93
2	1981	383790	130959	417
3.	1991	772550	335736	2094

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका-1998

बाँदा जनपद के आर्थिक विकास के कृषि उत्पादन आधारित औद्योगिकरण

शोध निदेशक-

सर्वेक्षिका-

डा० एस० के० त्रिपाठी

कु० कंचन श्रीवास्तव

सामान्य सूचनायें:-

- 1- फर्म का पूरा नाम व पता
- 2- यह फर्म किस वर्ष स्थापित की गयी
- 3- आपका उद्योग कहाँ स्थापित है, तहसील/विकास खण्ड/ जनपद-
- 4- इस उद्योग की स्थापित करने में कितनी पूंजी लगी थी, (स्थिर पूंजी/प्राथमिक लागत रु०में)
- 5- आपका उद्योग किस श्रेणी में आता है? कुटीर उद्योग/लघु उद्योग
- 6- फर्म के सवामित्व में पार्टनर शिप भी है, हां/नहीं

अवस्थापना पक्ष (साविध्य दशाएँ)

अ-कच्चा माल

- 7- इस उद्योग की स्थापना संभावित कच्चे माल मिलने की सुविधा के कारण की गयी है? हां/नहीं
- 8- इस फर्म के लिये कच्चा माल कहाँ से आता है?
- 9- क्या कच्चा माल लाने के लिये उचित साधन है? हां/नहीं
- 10- यदि हां तो किस साधन का प्रयोग करते हैं?
- 11- प्रति वर्ष कितना कच्चा माल मंगाते हैं।
- 12- क्या प्रति माह कच्चा माल मंगाने में संकट पड़ना है।

ब- विद्युत-आपूर्ति-

- 13- इस मिल के लिये विद्युत आपूर्ति कहाँ से की जाती है? जनरेटर/ शहर के पावर हाउस से-
- 14- यदि जनरेटर के द्वारा की जाती है तो जनरेटर कितने किलो वाट का है।
- 15- क्या जनरेटर फर्म का पूरा लोड ले सकता है?

16- आपके फर्म में लगे जनरेटर की क्षमता (कितनी है ?)

स- श्रम अनुपयोग ढांचा-

17- इस फर्म में कुल श्रमिक कार्य करते हैं।

18- फर्म में प्रयुक्त श्रमिक किस प्रकार के हैं ? शिक्षित/अशिक्षित।

19- आपके फर्म में स्थानीय श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

20- क्या आपकी फर्म में शिफ्ट में काम होता है ? हां/नहीं

21- प्रत्येक शिफ्ट में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

22- आपकी फर्म में कुल कितने घण्टे काम होता है ?

23- इस फर्म में मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

24- इस फर्म में दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

25- इस फर्म में श्रमिकों का मासिक वेतन रु० में।

26- इस फर्म में श्रमिकों का दैनिक वेतन रु० में।

27- यदि श्रमिक छुट्टी लेता है तो उसका वेतन काटा जाता है ? हां/नहीं।

28- यदि हां तो वेतन में कटौती किस हिसाब से होती है ?

29- श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्या श्रमिक के परिवार को क्षति पूर्ति व्यय दिया जाता है ?

30- यदि हां तो कितना दिया जाता है ? रु० में

31- क्या आपकी फर्म में महिला व बाल श्रमिक भी हैं।

32- क्या आपकी फर्म में महिला व बाल श्रमिक भी हैं।

33- यदि हां तो उनका कितना वेतन दिया जाता है ? रु० में।

34- क्या आपकी फर्म में मजदूरों की छटनी भी की जाती है ?

35- यदि हां तो किस आधार पर की जाती है।

(द)- ऋण प्राप्ति एवं स्थिति-

36- क्या वित्तीय प्रबंध स्वयं करते हैं ? हां/नहीं

37- क्या वित्तीय समस्याओं को पूरा करने के लिये ऋण लेने पड़ते हैं ? हां/नहीं-

38- यदि हां तो किस बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किये जाते हैं।

39- क्या कितनी ब्याज पर प्राप्त किये जाते हैं।

(य)-प्रबंधकीय पक्ष:-

40- इस फर्म के मालिक का नाम-

41- क्या फर्म कई विभागों में बटी है ?

42- प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(र)- उत्पादन एवं विधायन-पक्ष-

43- इस फर्म का उत्पादन किस श्रेणी में आता है ? प्राथमिक/अन्तिम।

44- प्रतिमाह कुल कितना उत्पादन होता है।

45- उत्पादन की औसत मासिक वार्षिक वृद्धि दर।

46- पिछले 10 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ (कुन्टल में)

1985-86

1989-90

1993-94

1997-98

1989-87

1990-91

1994-95

1987-88

1991-92

1995-96

1988-89

1992-93

1996-97

47- क्या प्रतिमाह बचने वाली अप्रयुक्त सामग्री का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है ?
हां/नहीं

48- यदि हां तो वैकल्पिक प्रयोग किस रूप में किया जाता है।

(ल)- लागत एवं आगम पक्ष:-

(1) लागत-

49- प्रतिमाह कच्चा माल खरीदने में कितनी लागत आती है रु0 में।

50- प्रतिमाह बिजली पर होने वाला व्यय रु0 में।

51- प्रतिमाह परिवहन पर होने वाला व्यय रु0 में।

52- क्या मशीनें बाहर से मंगाई जाती हैं ? हां/नहीं।

53- यदि हां तो मंगाने में कितनी लागत आती है।

54- मशीनों पर होने वाला प्रतिमाह घिसाई व्यय रु0 में।

55- पिछले 10 वर्षों में उत्पादन में आयी कुल लागत-

19985-89	1989-90	1993-94	1997-98
1989-87	1990-91	1994-95	
1987-88	1991-92	1995-96	
19988-89	1992-93	1996-97	

56- प्रतिमाह उत्पादन में कितनी स्थिर लागत आती है? रु0 में।

57- प्रतिमाह उत्पादन में कितनी सीमान्त लागत आती है?

(2)- आगम-

58- प्रतिमाह उत्पादन बेचने से कितनी आय प्राप्त होती है? रु0 में।

59- पिछले दस वर्षों में उत्पादन प्राप्त होने वाली आय।

1985-86	1989-90	1993-94	1997-98
1986-87	1990-91	1994-95	
1987-88	1991-92	1995-96	
1988-89	1992-93	1996-97	

60- प्रतिमाह फम को कितनी औसत आय प्राप्त होती है? रु0में।

61- प्रतिमाह फर्म को कितनी सीमान्त आय प्राप्त होती है?

62- फर्म को एक वर्ष में कुल कितनी आय प्राप्त होती है?

(व)- लाभ/हानि पक्ष:-

63- फर्म को एक वर्ष में कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ? रु0 में।

64- पिछले दस वर्षों में फर्म को लाभ-

1985-86

1986-87

1987-88	1990-91	1993-94	1996-97
1988-89	1991-92	1994-95	1997-98
1989-90	1992-93	1995-96	

65- फर्म को क्या हानि हो रही है? हां/नहीं।

66- यदि हां तो फर्म को एक वर्ष में कुल हानि कितनी हुई

(त)- तकनीकी पक्ष:-

- 67- या आपके फर्म की तकनीकी सुविधायें उपलब्ध हैं/हां / नहीं
- 68- क्या आपके अपनी फर्म में भारत से बनी मशीनों का उपयोग करते हैं? हां/नहीं
- 69- यदि नहीं तो किस देश से मशीनें मंगाते हैं।
- 70- क्या मशीनें बनवाने के लिए इन्जीनियर बाहर से बुलाने पड़ते हैं?
- 71- यदि हां तो इन्जीनियर बुलाने में कितनी लागत आती है।

(थ)- विपणन पक्ष:-

- 72- तैयार माल को बेचने के लिये क्या पास में विपणन की सुविधा है? हां/नहीं
- 73- यदि हां तो माल कहां बेचते हैं? बाजार में/मण्डी समिति में।
- 74- यदि बाजार में तो बाजार का नाम बताओं।
- 75- तैयार माल किस साधन तक बाजार में पहुंचाया जाता है।

(क)-पर्यावरण पक्ष:-

- 76- क्या आपकी फर्म द्वारा प्रदूषण फैलता है? हां/ नहीं
- 77- फर्म के द्वारा निकला कचड़ा कहां फैकते हैं?
- 78- क्या आपकी फर्म में प्रदूषण रहित यंत्र लगता है? हां /नहीं

(ख)- विशिष्ट समस्याएं-

- 79- क्या आपकी फर्म में श्रमिकों को वेतन समय पर मिल जाता है?
- 80- यदि नहीं तो इसको लेकर श्रमिक हड़तालें करते हैं? हां / नहीं
- 81- क्या आपकी फर्म में श्रमिकों को आवास की सुविधा प्राप्त है? हां / नहीं
- 82- अगर आपकी फर्म में श्रमिक हड़ताल करते हैं तो उसका निवारण आप किस प्रकार करते हैं।
- 83- यदि जल का साधन खराब हो जाता है तो फर्म में जल कहां से आता है।
- 84- क्या विद्युत आपूर्ति अनवरतन बनी रहती है? हां / नहीं
- 85- यदि नहीं तो क्या विकल्प है।
- 86- जनरेटर खराब हो जाने पर क्या करते हैं।
- 87- क्या कच्चा माल मंगाने में कठिनाई होती है? हां / नहीं

88- यदि हां तो किस प्रकार की कठिनाई होती है? वित्त / परिवहन।

(ग)-कृषि-आधारित औद्योगिकरण का विकासात्मक पक्ष-

89- आपने ऐसा ही उद्योग क्यों चुना जो कृषि पर आधारित है?

90- क्या वहां पर कृषि आधारित कच्चा माल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है?

91- क्या आपकी फर्म जनपद के विकास में सहायक है? हां/ नहीं

92- क्या आपकी फर्म से जनपद के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त हैं?

93- क्या आपकी फर्म आय वृद्धि में साह्यक हैं? हां / नहीं

94- क्या आपकी फर्म द्वारा कार्य नियति भी किया जाता है? हां / नहीं

95- क्या कृषि आधारित उद्योग लगाने में लाभ अधिक है? हां / नहीं।

(घ)-सरकारी नीति-

96- क्या इस सम्बन्ध में (कृषि आधारित औद्योगिकरण) कोई नीति बनाई है? हां / नहीं

97- यदि हां तो इस नीति का क्या नाम है।

98- क्या उस नीति का लाभ आपकी फर्म को भी प्राप्त है? हां / नहीं।

99- क्या उस नीति के द्वारा इस तरह के उद्योग लगाने में सहायता प्राप्त होगी? हां/नहीं

(ङ.)- उद्योग को रुग्णता से बचाने एवं स्वास्थ्य बिक्री

हेतु-सुझाव-

- 1- उद्योग को रुग्णता से बचाने के लिये हमें वित्त प्रबन्ध सुचारु मात्रा में करना चाहिये।
- 2- मशीनें उच्च कोटि की मंगानी चाहियें।
- 3- जल व विद्युत की सुचारु व्यवस्था होनी चाहिये।
- 4- उद्योग के पावर कनेक्शन के लिये आवेदन करना चाहिये-
- 5- उद्योग में कच्चा माल मंगाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उद्योग को सुचारु रूप में चलाया जा सकें।
- 6- श्रमिक को उनकी मेहनत के अनुसार वेतन प्रदान करना चाहिये।
- 7- बिक्री की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।
- 8- उत्तर प्रदेश सरकार रुग्ण इकाइयों का पुर्नवास के लिये एक योजना लागू की है जिसका नाम है ईकाइयों का पुर्नवसन इसके अन्तर्गत रुग्ण ईकाइयों के पुर्नवसन

की व्यवस्था कराई जाने का प्राविधान है। पूर्व में स्थापित इकाइयों जिनके ऋण खाते का मूलधन या ब्याज दो वर्ष से अधिक अवधि से अतिरिक्त हो अथवा इकाई के अधिकतम वास्तविक मूल्य के 50 प्रतिशत या अधिक अपक्षरण हुआ हो। वे इकाइयां इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Books:-

1. A.D.K.E.A.S., 'Rural Reconstruction in India' Karnataka University, 1974-230 p.
2. Arunachalam, K. and Natrajan, K.M., (eds) 'Integrated rural Development rev. Keithahn, Rev. Keithahan r.r.: felicitation volume madurai : Koodal publication 1977-224 p.
3. Chaurasi, R.A.,: Agro Industrial development Astudy. '
4. BAWA, p. s. : 'Rural project planning : ' Methodology and case studies, New rehhi; Bawa. p.s. 1977 211&43 p.
5. Azad, R.N. : Integrated rural revelopment in Sharma, S.K. (fd), Delhi, concept 1977 vol. p. 419-36.
6. Brjsto bekin : 'Rural Industrialization in India, New Delhi, ViKas publishing house, 1976- 23p.
7. Bhatnagar, K.p. Nigam, A.R. , srivastava, J.p.s., : Indian rural economy, 3rd ed Kanpur : Kishori publishing house, 198-146 p.
8. Singh Charen : 'India's poverty and its solution 2nd ed University 1958; 166p.
9. Ganguly, B.N. : 'problems of rural india, Calcutta : Calcutta university 1928-166 p.
10. karve, D.G., : rural revelopment Bombay: reserve Bank of india, 1967-75 p.
11. Mandal, G.C. : problems of rural development, Calcutta world press, 1961-118 p.
12. Mukerjee, p.k.: 'The basic pattern of India village economy, Agricultural situation of India 8-5 (August 1959)
13. Nanavati, Manilal B. and Anjaria, J.J.: The indian rural problem 7th ed.
14. Raja ragnam, K. : ' rural pevelopment in Indian with special reference to Agriculture, Education and administration, ph. D. Thesis, University of London 1964.
15. Pandey S.M. (ed.) : " rural labour in India : problems and policy Brispectives; ed. by S.M. panday New Delhi : shri Ram centre.
16. Sharib Zahurhasan : problems of rural reconstruction in India in India with special reference

toUttar predesh. Bombay Local self Government, 1956-215 p.

17. Sharma, S.K. and Malhotra S.K. : Integrated rural Development approach strategy.
18. Shiwaikar r. s : The twin problems of rural Development community Development and Agri-cultural production, Allahbad Kitab Mahai, 1968, 40
19. vyas. v.s.: 'rural Industrialisation and Integrated approach. Pharwar Karnataka university 1971, 77p.
20. Arora, R.C.: ' Industry and rural Development. 1993-462 p.
21. Aroral, R.C.: ' Industry and rural Development 248 p.
22. Dapola, T.S.: ' rural Industrialisation approaches and potential.
23. Singh p.: Indian ehrironment.
24. Bhatta charya, s.N.: , role of Indian rurel Institutions inbconomic Growth: Acritioal Study New Delhi, Metropolition.
25. Banerjee Brojendra Nath- Industry Agriculture and Rural Development.
- 26- डा. सिंह आर०पी० व डॉ० सिंह बी-प्रक्षेप प्रबंध एवं उत्पादन अर्थशास्त्र पृष्ठ 255
27. रुहेला सत्यपाल-सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान के मूलतत्त्व
28. गुडे और हॉट-मेथइय इन सोशल रिसर्च
29. गुप्ता आर०बी० एवं गुप्ता मीरा-सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञान

Articles :-

1. Ayodhya Singh : "Industrialisation of rural. Area by setting up more growth cetres, " capital (19th July 1977) 1162-3.
2. Dhal vinod : " Recent Trends in Industrial Finshcing prajnen, jan. March 1982- p. 13-18.
3. Durga prasad p. " Rural Industrial isationobjocts paradigm toaction process" (Two patrs) The ecocomic times, June 1 &2, 1998.
4. Fahimuddin- Approach to rural IndustrialisationKurukeshetra, 31 (7)-April 1984 p. 8-10.

5. yojana- Oct. 15-31, 1998, pp. 12-13 & July 1995
6. khanna S.S. and pavate M.V.: "Approach to rural Industrialisation and climatic Kurukshetra. April 1990 p. 9-12.
7. George m n. " Application of costs and decisionmaking Techniques in village Industries, " Khadi Gremidyog. (May 89) 393-397.
8. Gupta, B.N. : " Rural development part failures and New strategy, Eastern Economist "(5th August- 1977).
9. Jain, B.K.D.: "Rural development Need for training in agro Industries Economic times, Dec. 4, 1992_p 5.
10. Kamat G.S. : " Gramin Vikas Ke liya vitta Khadi Gramodyog " (August 1981) 515-81.
11. औद्योगिक निर्देशिका
12. औद्योगिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन जनपद-बाँदा
13. संभाव्यतायुक्त योजना-1995-96, 1997-98
14. उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1993-94, 95, 96, 97, 98
15. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक-1993-94, 1996-97, 1997-98
16. जिला सेक्टर योजना (बाँदा)
17. संदेश पत्रिका 30 प्र 0 मार्च, अप्रैल 2000

(C) Misc.

1. Banda District Gezetter
2. Census Head Book District Banda, 1981-19913.
3. Stalistcal Booklet District Banda. 1981-1991.